वैश्विक संवाद

11.2

अनेक भाषाओं में एक वर्ष में 3 अंक

समाजशास्त्र पर बातचीत दास्तेन जुलियन के साथ

जोहना सिटेल
वालिद अब्राहिम

वैश्विक असमानताएँ और महामारी

करीन फिशर
काजल भारद्वाज
केमिला जियानेला
क्रिस्टीना लस्कारिडिस
लकीस्टार मियानदाजी
ई. वेंकट रामनय्या
विहा इमांदी

राज्य की नयी भूमिका ?

जूली फ्राउड
एंड्रियास नोवी
रिचर्ड बार्नथेलर
बॉब जेसोप
क्लॉस डोरे
वालिद इब्राहिम
डेनियल मुलीस

सैद्धांतिक परिपेक्ष्य

आर्थर ब्यूनो

समाजशास्त्र का कला से मिलन

जेनी टिशर

कोविड–19: महामारी और संकट

मार्गरेट अब्राहम
करीना बेथयानी
महमूद धौदी
एलेजांद्रो पेल्फिनी

खुला अनुभाग

> नागरिक–राजनीतिक क्षेत्र में समाजशास्त्री
> त्रिनिदाद और टोबैगो में अंतरंग साथी हिंसा के आसपास चुप्पी
> विश्व की देखभाल करने की क्षमता पर
> होमो कल्चरस के रूप में मनुष्य
> 22 जुलाई, 2011 को नार्वे का आतंकवादी हमला

पत्रिका

अंक 11 / क्रमांक 2 / अगस्त 2021
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

GD

International Sociological Association

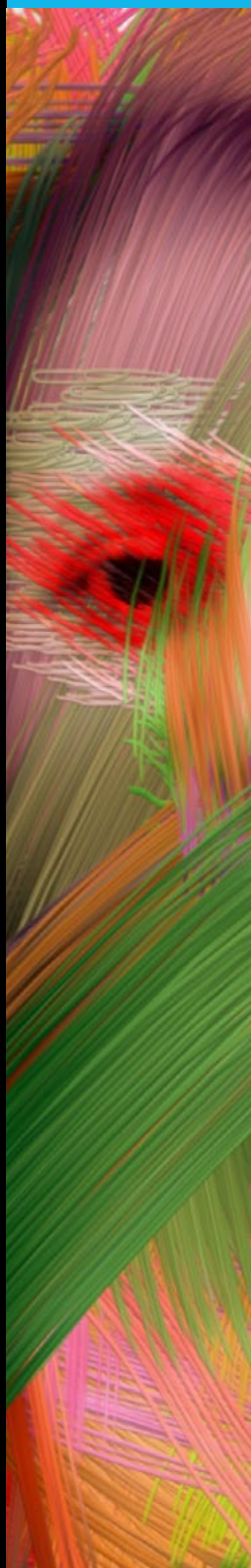

> सम्पादकीय

वैश्विक संवाद के इस अंक में ''समाजशास्त्र पर बातचीत'' का खंड चिली के वर्तमान घटनाक्रमों को उठाता है। जोहना सिटेल और वालिद अब्राहिम द्वारा आयोजित साक्षात्कार में समाजशास्त्र और इतिहास के प्रतिच्छेदन करने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले एक प्रसिद्ध अनुसंधानकर्ता दास्तेन जुलियन अपने देश में राजनैतिक घटनाक्रमों, सामाजिक विरोध प्रदर्शन और अनिश्चित कार्य पर और समाज विज्ञान एवं समाज के मध्य सम्बन्धों पर गहन चिंतन करते हैं।

पिछले डेढ़ साल से कोविड–19 महामारी ने रोजमर्रा की जिंदगी में बुनियादी बदलाव के साथ साथ नए आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक संकटों को जन्म दिया है। इसके प्रकोप के प्रारम्भ से *वैश्विक संवाद* ने दुनिया भर के घटनाक्रमों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास किया है। इस अंक के लिए, करीन फिशर ने भारत, पेरू, यू के और दक्षिण अफ्रीका से आलेखों के साथ महामारी और वैश्विक असमानताओं पर व्यवस्थित रूप से चिंतन करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यद्यपि महामारी पुरे विश्व की आबादी को प्रभावित करती है, ''हम सब एक ही नाव में सवार नहीं हैं।'' विकास, विपणन, और वैक्सीन की उपलब्धता (कमी), और स्वास्थ्य या शिक्षा की सन्दर्भ में महामारी के प्रभाव निर्धन और धनी देशों, वैश्विक दक्षिण और वैश्विक उत्तर, पहले से ही पारिस्थितिक या आर्थिक संकटों से पीड़ित कमजोर समूहों और वे समूह जो स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, के मध्य वैश्विक असमानताओं को बढ़ाते हैं।

हमारी दूसरी संगोष्ठी अर्तव्यवस्था और राज्य के मध्य संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तनों पर चर्चा करती हैं। फॉउण्डेशनल इकोनोमी की अवधारणा को बढ़ावा देने वाले विद्वान पिछले दशकों के आर्थिक उदारीकरण की आलोचना करते हैं और लोकतान्त्रिक संस्थानों द्वारा आकारित और नियंत्रित बुनियादी ढांचे के साथ स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, भोजन, सार्वजनिक हस्तांतरण इत्यादि के प्रावधानों की नए तरीकों की लिए याचना करते हैं। महामारी के सामने राज्य की बदलती भूमिका पर चिंतन करते हुए, लेखक इस बारे में चर्चा करते हैं कि दीर्घ अवधि में यह अर्थव्यवस्था और समाज के संबंधों को कितना प्रभावित कर सकती है, सत्तावादी या लोकतान्त्रिक प्रवृतियों के सन्दर्भ में यह किस दिशा में ले जा सकता है और नवीन राज्य हस्तक्षेपवाद द्वारा समाजशास्त्र किस प्रकार से चुनौती पाता है।

सैद्धांतिक अनुभाग में आर्थर ब्यूनो आर्थिक और सामाजिक संकट के साथ व्यक्तिपरकता का संकट पैदा करने वाले पिछले दशकों के नवउदारवादी युग का पुनर्निर्माण करते हैं। मंदी पर ध्यान केंद्रित करके वे स्व–उद्यमिता से थकावट और आत्मानुभूति से अलगाव की तरफ झुकाव, के साथ ही विरोध आंदोलनों एवं सत्तावादी नीतियों के प्रभाव और भावी परिपेक्ष्यों पर चर्चा करते हैं।

कलाकार जेनी टिशर अदृश्य कार्य को अधिक दृश्यमान बनाने के उद्देश्य से अपने दो कोलाजों की व्याख्या करके महामारी में आवश्यक कार्य पर सार्वजनिक बहस में योगदान देती हैं।

कोविड–19 पर अनुभाग समाजशास्त्र के लिए कुछ चुनौतियों को रेखांकित करता है। यहाँ मार्गरेट अब्राहम इस बात का विश्लेषण करती हैं कि महामारी किस प्रकार बढ़ती घरेलू हिंसा के साथ बढ़ती है। करीना बेथियानी और एस्तेबान टोरेस सामाजिक असमानताओं के मुद्दे को उठाते हैं और महमूद धौदी घृणा भाषण के बढ़ते प्रभावों पर चर्चा करते हैं जबकि अलेजांद्रो पेल्फीनी समाज की सीखने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

अंतिम लेकिन कमतर नहीं, ''खुला अनुभाग'' सैद्धांतिक प्रतिबिम्बों, विशेष रूप से मानवता की प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं के बारे में चिन्तन प्रस्तुत करता है। और साथ ही एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ देखभाल के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में हाल की घटनाओं और समकालीन घटनाक्रमों पर चर्चा करता है। ■

ब्रिजित ऑलनबैकर और **क्लॉस डोरे**
वैश्विक संवाद के संपादक

> वैश्विक संवाद आई.एस.ए. वेबसाइट पर अनेक भाषाओं में देखा जा सकता है।
> प्रस्तुतियाँ <globaldialogue.isa@gmail.com> पर भेजी जा सकती हैं।

International Sociological Association
GLOBAL DIALOGUE

> संपादक मण्डल

संपादक : ब्रिजिट ऑलनबॉकर, क्लॉस डोरे

सह–सम्पादक : जोहाना ग्रबनर, वालिद इब्राहिम

सहयोगी सम्पादक : अर्पणा सुन्दर

प्रबंधन संपादक : लोला बुसुतिल, अगस्त बागा

सलाहकार : माइकल बुरावे

मीडिया सलाहकार : जुआन लेजाररगा

परामर्श संपादक :
साडी हनाफी, ज्योफी प्लीयर्स, फिलोमिन गुतिरेज, एलोइजा मार्टिन, सावाको शिराहेस, इजाबेला बरलिंस्का, तोबा बेन्सकी, चिह–जुए जेचेन, जेन फ्रित्ज, कोइची हासेगावा, हिरोशी इशिदा, ग्रेस खुनो, एलिसन लोकोन्तो, सुसन मेकडेनियल, एलिना ओइनास, लोरा ओसो कैसास, बंडाना पुर्कायस्था, रोह्डा रेडॉक, मौनीर सैदानी, आयसे सकतांबर, सेली स्कालोन, नाजानीन शाहरोकनी।

क्षेत्रीय संपादक

अरब दुनिया : *(ट्यूनिशिया)* मौनीर सैदानी, फातिमा रधौनी, हबीब हज सलेम; *(अल्जीरिया)* सोराया मौलोदजी गराउदजी; *(मोरक्को)* अब्देलहादी एल हालहोली, सालिदा जाइन; *(लेबनान)* साड़ी हनाफी।

अर्जेन्टीना : मैगडालेना लेमस, जुआन परसिआ, मार्टिन उर्टुसन।

बांग्लादेश: हबीबुल खोंड़कर, खैरुल चौधरी, अब्दुर रषीद, अषिस कुमेर बनिक, ए.बी.एम. नजमुस साकिब, बिजॉय कृश्णा बनिक, ईषरत जहान ऑयमून, एकरामुल कबीर राणा, हेलल उद्दीन, जुवेल राणा, एम. ओमर फारुक, मसुदुर रहमान, मोहम्मद षाहीन अख्तर, मोहम्मद जसीम उद्दीन, मोहम्मद जहीरुल इस्लाम, रुमा परवीन सबीना षर्मीन, सालेह अल मॉमून, सरकर सोहेल राणा, सेबक कुमार साहा, षाहिदुल इस्लाम, षम्सूल अरेफिन, षर्मिन अख्तर षप्ला, सैका परवीन, यास्मीन सुल्ताना।

ब्राजील : गुस्तावो तानिगुती, एंजेलो मार्टिन्स जूनियर, एंड्रेजा गली, दिमित्रि सर्बोन्सीनी फर्नांडीस, गुस्तावो दिअस, जोसे गुइराडो नेटो, जेसिका मज़िजनी मेंडिस।

फ्राँस/स्पेन : लोला बुसुतिल

भारत : रश्मि जैन, निधी बंसल, संदीप मील, प्रज्ञा शर्मा, मनीष यादव।

इंडोनेशिया : कमांतो सुनार्तो, हरि नुग्रोहो, लूसिया रतीह कुसुमादेवी, फिना इद्रियती, इंदेरा रत्ना इरावती पट्टिनसारानी, बेनेडिक्टस हरि जूलियावान, मोहम्मद शोहीबुद्दीन, डोमिंगगस एलसीड ली, एंटोनियस एरियो सेतो हार्डजाना, डायना तेरेसा पाकासी, नुरूल ऐनी, गेगेर रियांतो, आदित्य प्रदान सेतियादी।

ईरान : रेयहाने जावदी, नियाश डॉलाती, अब्बास शाहरबी, सैयद मोहम्मद मुतालेबी।

कजाकस्तान : अइगुल जाबिरोवा, बायन स्मागमबेट, आदिल रोदियोनोव, अल्माश त्लेसपयेवा, कुआनिश टेल, अलमागुल मुस्सीना, अकनूर ईमानकुल, मदियार एल्दियारोव।

पौलैंड : जुस्तिना कोसिंस्का, जोनाथन स्कोविल, सारा हरकजिंस्का, वेरोनिका पीक, अलेक्सांद्रा वेगनर, अलेक्सांद्रा बीएरनाका, जेकब बारस्जेवस्की, एडम मुल्लेर, जोफिया पेन्जा–गेबलर, इवोना बोजडजीजेवा।

रोमानिया : रलुका पॉपेस्कू, राइसा–गेब्रियला जमीफिरेस्कू, युलिआन गेबर, मोनिका जोर्जेस्क्यू, इयाना इयानुस, बियांका मिहायला।

रूस : ऐलेना ज्द्रावोम्यस्लोवा, अनास्तासिया दौर।

ताईवान : वान–जू ली, ताओ–युंग लु, त्सुंग–जेन हंग, यू–चिआ चेन, यू–वेन लिओ, पो–शुंग होन्ग, केर्क जी हाओ, यि–शाओ होंग।

तुर्की : गुल कोरबासियोग्लू, इरमक एवरेन।

दास्तेन जूलियन के साथ इस साक्षात्कार *में, हम चिली में एक नए संविधान की स्थापना की प्रक्रिया का अनुगमन करने वाले हाल के बड़े पैमाने पर विरोध और व्यापक अनिश्चितता की स्थिति में समाजशास्त्री यहां क्या भूमिका निभा सकते हैं, पर चर्चा करते हैं।*

कोविड–19 महामारी ने न केवल राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर बल्कि लेकिन विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर धन और आय, लिंग और नस्ल की मौजूदा असमानताओं को उजागर और बढ़ा दिया है। विकास, विपणन, और टीकों की उपलब्धता (कमी), और स्वास्थ्य या शिक्षा के संदर्भ में महामारी के प्रभाव गरीब और अमीर देशों, वैश्विक दक्षिण और वैश्विक उत्तर, पहले से ही पारिस्थितिक या आर्थिक संकट से पीड़ित कमजोर समूहों और वे समूह जो अपनी रक्षा कर सकते हैं के मध्य ***वैश्विक असमानताओं*** *को दिखाते हैं और बढ़ाते हैं।*

यह संगोष्ठी राज्य और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों के बारे में प्रश्नों को सम्बोधित करती है। महामारी के प्रति संबंधित राज्य की प्रतिक्रियाएं भविष्य के शासन के रूपों को कैसे प्रभावित करेंगी और ***राज्य के हस्तक्षेप*** *के पहले से ही देखे जा सकने वाले रूपों को कैसे समझा जा सकता है, को योगदानकर्ता सम्बोधित करते हैं। क्या राज्य के हस्तक्षेप का एक नया रूप बन रहा है, और यदि हां, तो क्या यह सत्तावादी या लोकतांत्रिक विशेषताओं को अपनाएगा?*

GD

सेज प्रकाशन की उदार ग्रांट से
वैश्विक संवाद का प्रकाशन संभव है।

> इस अंक में

सम्पादकीय 2

> समाजशास्त्र पर बातचीत

संकट के क्षणों में समाजशास्त्र : दास्तेन जुलियन के साथ साक्षात्कार
जोहना सिटेल एवं वालिद अब्राहिम, जर्मनी द्वारा 5

> वैश्विक असमानताएँ और महामारी

कोविड–19 एवं वैश्विक असमानताएँ
करीन फिशर, ऑस्ट्रिया द्वारा 9

लाभ के पहले लोग: कोविड–19 में आह्वान
काजल भारद्वाज, भारत द्वारा 10

कोविड–19 वैक्सीन: वैश्विक असमानताओं का खुलासा
केमिला जियानेला, पेरू द्वारा 12

लेनदारों और देनदारों के मध्य विभाजन को बनाये रखना
क्रिस्टीना लस्कारिडिस, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 14

अफ्रीका में निर्धनता और असमानताओं को कम करने की चुनौतियाँ
लकीस्टार मियानदाजी, दक्षिण अफ्रीका द्वारा 16

भारत में जुड़वां आपदाएं : एक अधूरा एजेंडा
ई. वेंकट रमनय्या और विहा इमांदी, भारत द्वारा 18

> राज्य की नयी भूमिका ?

सामाजिक नवीनीकरण की कुंजी के रूप में आधारभूत अर्थव्यवस्था
जूली फ्राउड, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 20

भविष्य–अनुकूल अर्थव्यस्थायें और राज्य
एंड्रियास नोवी और रिचर्ड बार्नथेलर, ऑस्ट्रिया द्वारा 22

कोविड–19: राज्य और अर्थव्यवस्था के नये स्पष्टीकरण
बॉब जेसोप, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 24

लेविआथन वापिस आ गया है! कोरोना राज्य और समाजशास्त्र
क्लॉस डोरे और वालिद इब्राहिम, जर्मनी द्वारा 26

कोविड–19: जर्मनी में असुरक्षित स्थानों का निर्माण
डेनियल मुलीस, जर्मनी द्वारा 28

> सैद्धांतिक परिपेक्ष्य

अवसाद के बाद: एक उत्तर–नवउदारवादी विषय
आर्थर ब्यूनो, जर्मनी द्वारा 30

> समाजशास्त्र का कला से मिलन

अदृश्य कार्य का दृश्य प्रतिनिधित्व
जेनी टिशर, ऑस्ट्रिया द्वारा 33

> कोविड–19: महामारी और संकट

वैश्विक महामारी के दौरान घरेलू हिंसा
मार्गरेट अब्राहम, यूएसए द्वारा 35

कोविड–19 संकट: नए समाजशास्त्र और नारीवाद
करीना बेथयानी, उरुग्वे और एस्तेबान टोर्रेस, अर्जेंटीना द्वारा 37

कोविड–19 का भयावह वैश्विक प्रभाव
महमूद धौदी, ट्यूनीशिया द्वारा 39

महामारी–पश्च परिदृश्य, अनुकूलन से सामूहिक सीख तक
एलेजांद्रो पेल्फिनी, अर्जेंटीना द्वारा 41

> खुला अनुभाग

नागरिक–राजनीतिक क्षेत्र में समाजशास्त्री
फ्रेडी एल्डो मैसेडो हुआमन, मैक्सिको द्वारा 43

त्रिनिदाद और टोबैगो में अंतरंग साथी हिंसा के आसपास चुप्पी
अमांडा चिन पैंग, त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा 45

विश्व की देखभाल करने की क्षमता पर
फ्रांसेस्को लारुफा, स्विटजरलैंड द्वारा 47

होमो कल्चरस के रूप में मनुष्य
महमूद धौदी, ट्यूनीशिया द्वारा 49

22 जुलाई 2011 को नार्वे का आतंकवादी हमला
पॉल हल्वोर्सन, जर्नल्स एडिटर, नार्वे द्वारा 51

"कई मामलों में अर्थव्यवस्था मानव यंत्रणा एवं पर्यावरणीय आपदा के माध्यम से बढ़ती है"

फ्रांसेस्को लारूफा

> संकट के क्षणों में समाजशास्त्र

दास्तेन जुलियन के साथ साक्षात्कार

दास्तेन जूलियन।

डा. दास्तेन जुलियन इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेज, द ऑस्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ चिली में शिक्षाविद और अनुसंधानकर्ता हैं। वर्तमान में वे ''चिली के दक्षिणी वृहद क्षेत्र में कार्य की अनिश्चितताः मौले, नुबले, बिओबिओ एवं ला अराउकान्या क्षेत्रों में परस्परछेदन, क्षेत्र एवं प्रतिरोध'' (2020–2023)पर एक प्रोजेक्ट में प्रमुख अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्यरत है। यह प्रोजेक्ट चिली के नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा वित्तपोषित हैं। वे विटवाटरस्रैंड विश्वविद्यालय, जोहानस्बर्ग (दक्षिण अफ्रीका) के सोसाइटी, वर्क एंड पॉलिटिक्स इंस्टिट्यूट (SWOP) में शोध सहायक भी हैं। दास्तेन जुलियन ने जर्मनी के जेना शहर के फ्रेड्रिख–शिलर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वे कार्य एवं जीवन की अनिश्चितता, यूनियन की रणनीतियां एवं संगठन, निष्कर्षण, जन समाजशास्त्र जैसे विषयों के साथ सामान्य रूप से वैश्विक दक्षिण पर शोध कार्य करते हैं। उनका अनुसंधान कार्य नागरिक समाज, श्रम संघों एवं गैर– सरकारी संगठनों के निकट संपर्क के साथ किया जाता है ।

यहाँ जर्मनी के जेना शहर में फ्रेड्रिख–शिलर विश्वविद्यालय के औद्योगिक एवं आर्थिक समाजशास्त्र के विभाग में शोध सहायक **जोहना सिटेल** एवं **वालिद अब्राहिम** ने डॉ जुलियन का साक्षात्कार आयोजित किया।

चिली में 2019 के सामाजिक प्रतिरोध कैसे प्रारम्भ हुए? ये विरोध प्रदर्शन सार्वजनिक परिवहन के किराये में वृद्धि से भड़के थे। क्या ये सिर्फ एक छोटी चिंगारी थी जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी थी या इसके अलावा और कुछ भी है क्योंकि लोक सेवाओं और संघर्ष की स्थिति समाज की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहती है?

सामाजिक प्रतिरोधों की ऐतिहासिक उत्पत्ति ऑगस्टो पिनोशे (1973–1990) के नागरिक–सैन्य तानाशाही द्वारा लागू संविधान के साथ लोकतान्त्रिक ताकतों के व्यवस्थित विनाश और 1980 में कपटपूर्ण जनमत संग्रह के कार्यान्वयन में निहित थी। लैटिन अमेरिकी स्तर पर, चिली एकमात्र देश है जहाँ सैन्य तानाशाही के तहत बना संविधान बरकरार है। इस तथ्य के कारण कि इसने क्रूर और समग्र तरीके से नवउदार नीतियों के प्रारम्भ का मार्ग प्रशस्त किया था, सामाजिक जीवन में इसकी दृढ़ता की अभिव्यक्तियों की श्रंखला है। इस अर्थ में, पांच दशकों से चिली समाज को एक बेलगाम और अप्रत्याशित वस्तुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से गहन रूप से संकट में लाया गया और लूटा गया है ।

यह 1990 के बाद से चिली पर शासन करने वाले दो गठबंधनों के मध्य राजनैतिक सहमति का भाग रहा है जिसने नवउदार व्यवस्था की प्रधानता को दो अक्षों पर कायम रखा हैः कल्याण आवंटन और सामाजिक एकीकरण की एक इकाई के रूप में बाजार में विश्वास, और राजनैतिक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण में बाधा के रूप में पिनोशे संविधान। इस अवधि (1990–2019) को ''लोकतान्त्रिक संक्रमण'' कहा गया जिसका अर्थ समाज के सहअस्तित्व और लोकतान्त्रिक संगठन के कुछ आधारों को पुनः प्राप्त करने के लिए क्रमिक लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया है। यद्यपि, व्यवस्था और संस्थागत राजनैतिक कर्ताओं ने बहुसंख्यकों द्वारा भागीदारी और सक्रिय निर्णय लेने के चौनलों को अवरुद्ध कर दिया, जबकि आर्थिक मॉडल उच्च वृद्धि दर पर पहुँच गया।

राजनैतिक व्यवस्था के अविश्वास और अवैधीकरण की एक व्यवस्थित

> >

प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जो नागरिकों से बहुत दूर थी। आर्थिक मिलीभगत की प्रक्रियाएं, चुनाव के अभियानों के अनियमित वित्तपोषण के मामले, व्यापारियों के लिए न्यायिक अदालतों में दंड मुक्ति इत्यादि, तानाशाही के दौरान मजबूत किये गए सत्ता के नेटवर्क में फंसे समाज के कुछ लक्षण थे। ''चिली वेक अप'' का नारा विवेक, पहचान और शक्ति के रहस्योद्घाटन और विद्रोह के क्षण को दर्शाता है जैसे सरकार की ''युद्ध की घोषणा'' मानवाधिकारों का उल्लंघन, (न्यायिक अदालतों में 8827 औपचारिक शिकायतें) और प्रदर्शनकारियों (उनमें से 27432 तक) की कैद औपचारिक राजनीति में प्रचलित सत्तावादी, रूढ़िवादी और सैन्य भावना का संश्लेषण करती है।

चिली में विरोध प्रदर्शन भी बहुत विविध विषयों और भोगौलिक क्षेत्रों को मिलाते हैं। युवा लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, स्वदेशी लोग, प्रवासी अदि सहजता और समन्वय में गठबंधन के खजाने को समृद्ध करते हैं। वर्तमान और अतीत निजी और सार्वजनिक स्थानों में राजनीतिक स्मृति की पीढ़ीगत मुठभेड़ के माध्यम से मिलते हैं, राजनैतिक ने खुद को सौन्दयशास्त्र में, कलात्मक रचनात्मकता में, संगीत में, गलियों में, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ विधानसभाओं, वार्तालापों, आभासी स्थानों पर कब्जों में प्रकट किया गया है। एक समाज के रूप में, हमारी एक गहन सांस्कृतिक, राजनैतिक और प्रतीकात्मक पुनः मुठभेड़ हुई है जो एक उद्देश्य के रूप में, एक प्रथा के रूप में ''गरिमा'' के साथ जुडी हुई है। अतः, इस मुठभेड़ में चिली समाज के मूल और संवैधानिक तत्त्व, इसके सामाजिक अनुबंध, इसकी नींव, इसका संविधान उजागर हुए हैं।

इस क्षण में संविधान के विस्तार की प्रक्रिया किस रूप में दिखती है ? क्या कोई ऐसा कर्ता है जो यहाँ सबसे अलग है? क्या समाजविज्ञानी इसमें भूमिका निभाते हैं या विधि विशेषज्ञ हावी हैं?

एक वर्ष पूर्व, 26 अप्रैल 2020 को एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित किया गया। 7 मिलियन से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। 78% से अधिक मतदाताओं, यानि कुछ 5.8 मिलियन लोगों, ने एक नए संविधान की आवश्यकता की पुष्टि की और मत दिया कि इसे कांग्रेस के सदस्यों की भागीदारी के बिना, विधानसभा (विधान सम्मलेन) के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। लगभग 50% पंजीकृत मतदाताओं ने इस प्रक्रिया में मतदान किया और मतदान की स्वैच्छिक प्रकृति के कारण उन्होंने इसमें ऐतिहासिक भागीदारी दर तय की।

वर्तमान में, संविधान–निर्माण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण क्षण पर है, चूँकि संविधान सभा का निर्माण करने वालों के चुनाव 11 अप्रैल[1] को होंगे। रचना में लैंगिक समानता और स्वदेशी लोगों की ''भागीदारी'' के बारे में चर्चाओं की श्रंखला सम्मिलित है जो चुनाव का विषय नहीं था लेकिन सरकारी हस्तक्षेप और राजनैतिक पैरवी के अधीन था। इसके लिए कांग्रेस की निर्णय प्रक्रियाओं की निरंतर निगरानी की आवश्यकता थी। इस सामूहिक निगरानी ने उस सांस्थानिक कब्जे को दर्शाया, जिसके माध्यम से प्रक्रिया को अपनाया गया था, और यह कि निर्वाचन घटना ने एक नया राजैनतिक अर्थ प्राप्त लिया थाः पार्टी व्यवस्था का पुनरुद्धार।

यद्यपि सामूहिक कार्यवाही पर केंद्रित विद्रोह में पार्टी–विरोधी संवेदनशीलता थी, और वह राजनैतिक व्यवस्था की आलोचक थी, ये राज्य के अंग थे जिन्होंने निर्वाचक प्रक्रिया को दिशा देने और आकर देने का कार्य किया। स्वतंत्र ताकतों और उनके उम्मीदवारों को राजनैतिक दलों के सदस्य वाले उम्मीदवारों की तुलना में कई कठिनाइयों और असमानताओं का सामना करना पड़ा जो अन्य के मध्य, उम्मीदवारों के पंजीयन, वित्तपोषण और मीडिया में भागीदारी में बाधाओं में परिलक्षित होता है। इसने स्वतंत्र ताकतों के संगठन को बाधित किया हैं जो पहले से ही व्यापक रूप से बिखरी और खंडित हैं।

महामारी ने प्रस्तावों पर चर्चा और विस्तार के लिए बहस और बैठक के स्थानों को सीमित कर दिया है। समाज विज्ञानों ने प्रक्रिया के आलोचनात्मक एवं चिन्ताशील दृष्टिकोण के साथ प्रक्रिया पर चिंतन को प्रोत्साहित किया है। ऐसा शैक्षणिक हैबिट्स को छोड़ते हुए और समय की चुनौतियों को खोलने के कारण मानवाधिकारों के उल्लघन की निंदा और सामूहिक जागरूकता इत्यादि के द्वारा एक सार्वजनिक भूमिका का निर्वाह किया है। हालाँकि इनमें से अधिकांश हस्तक्षेप आभासी क्षेत्र या पुस्तकों, वैज्ञानिक आलेखों इत्यादि के पारम्परिक मीडिया तक सीमित हैं जिसने उनके प्रभाव और व्यापकता को बाधित किया है। फिर भी, इसने जुड़ाव, विज्ञान(ों) और ज्ञान के मध्य संबंधों की लोक भावना को स्थापित किया है।

हाल ही में चिली को चिन्हित करने वाले राजनैतिक विवादों में आपके सामाजिक वैज्ञानिक कार्य के कौन से भाग ने विशेष भूमिका निभाई हैं? समाज विज्ञान और राजनैतिक कार्यों के संयोजन में क्या कोई विशेष रूप से उपयुक्त क्षेत्र या समस्याएं हैं?

मेरे वैज्ञानिक कार्य ने काम और जीवन की अनिश्चितता पर शोध पर बल दिया है। मैंने अपने आप को चिली समाज में कार्य करने और रहने की विशेषताओं की गणना के लिए समर्पित किया है। ऐसा मैंने सत्ता के परस्परछेदन में अंकित सांस्कृतिक, व्यक्तिपरक, आर्थिक और क्षेत्रीय तत्वों पर विचार करते हुए किया है। मेरा उद्देश्य सामाजिक, पर्यावरणीय और श्रम संघ संगठनों के साथ एक स्थानीय–क्षेत्रीय कार्यमंच स्थापित करना रहा है। ऐसा मैंने वैश्विक अनुसन्धान नेटवर्कों के साथ संपर्क को गतिशील बना कर और श्रम अध्ययनों में राष्ट्रीय सामाजिक वैज्ञानिक समुदाय की एकजुटता को मजबूत कर के किया है।

चूँकि मैं सामाजिक अनिश्चितता की प्रक्रिया और कार्य की दुनिया का अन्वेषण कर रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूँ कि कार्य, रोजगार और बेरोजगारी कैसे लोगों की रहवास की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में पहचाने जाते हैं। रोजगार की गुणवत्ता, मजदूरी, स्वचालन, आय, प्लेटफॉर्मों का प्रारम्भ और सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था की कमजोरी ने लोगों के जीवन पर बहुत अधिक दबाब डाला है। ऋणग्रस्तता, अनौपचारिक नौकरियों की तलाश, या एक से अधिक नौकरी की तलाश, सब गरिमा और जीवन की अनिश्चितता के मध्य इस विवाद का हिस्सा है। इनमें से कई समस्याएं चिली में राजनैतिक और सामाजिक विवादों के मध्य चलने वाली कुछ मूल हैं और वे युवाओं, महिलाओं, प्रवासियों, बुजुर्गों अदि की अनिश्चितता को भी दर्शाती हैं।

क्या समाज विज्ञान को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, विशेषकर जब संघर्ष सामने आते हैं या क्या आपको लगता है कि विज्ञान एक अलग समय सीमा, शायद दीर्घावधि में, कार्य करता है?

ऐसे कई लोग और कार्य समूह हैं जो समाज विज्ञान एवं समाज के मध्य इन पुलों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका

>>

उद्देश्य निर्णय लेने, कार्यों एवं लोकतान्त्रिक विचार विमर्श में वैज्ञानिक ज्ञान के महत्व को उजागर और आलोकित करना है। अनुसन्धान की दुनिया, सार्वजनिक क्षेत्र और विशेष कर सामाजिक आंदोलनों की गतिविधि के मध्य इस अंतर को पाटने की आवश्यकता है। वास्तव में, नारीवादी, पर्यावरणीय और अन्य आंदोलनों जैसे कई आंदोलन पहले से एक उदहारण प्रस्तुत करते हैं और हमें इन अभिव्यक्तियों के विचार रखने की अनुमति देते हैं।

उनके भाग पर, समाज विज्ञानों की जिम्मेदारियाँ संकट के क्षणों में अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। संघर्ष अक्सर संकट के लक्षण होते हैं और साथ ही परिवर्तन के अग्रदूत भी। यह प्रक्रिया अक्सर समाज विज्ञानों में सन्दर्भ का कार्यस्थल होती है। व्यक्तिगत रूप से, समाजशास्त्र का मेरा अभ्यास तात्कालिकता के प्रत्युत्तर में है। समाज के ऊपर लूटपाट और अनिश्चितता के साथ ऐसा युद्ध छेड़ा गया कि मुझे एक बहुत ही वर्तमान अर्थों में कार्य करना पड़ा है जो एक अस्थिर, कमजोर, और अनश्चित सामयिकता की संभावनाओं का भाग है। इसके अपने विरोधाभास और नकारत्मकताएँ है क्योंकि यह भविष्य के विचार (जिसमें यूटोपिया के अभाव को संलग्न किया जा सकता है) को बाधित करता है, लेकिन यह उसी समय में ज्ञान में यूटोपिया बनाने के नए, अधिक व्यावहारिक और सक्रिय तरीके सिखाता है।

क्या आपके अनुसन्धान परिणामों को सार्वजनिक रूप से और विज्ञान के बाहर स्वीकारा जाता है और क्या राजनैतिक कर्त्ता समाज विज्ञान अनुसन्धान के परिणामों में रूचि रखते हैं?

मेरा अनुभव मुझे दिखता है कि यही मामला है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रश्न यह नहीं है कि क्या परिणामों को माना जाता है, अपितु यह है कि क्या उन मार्गों, नेटवर्कों, जिनमें ज्ञान का आदान–प्रदान, संवाद, साँझा और पुनर्निर्माण किया जाता है, के निर्माण का कार्य है। संगठनों, संघों, श्रमसंघों इत्यादि के साथ निरंतर संवाद होता है। संवाद के इन स्थानों में उत्पन्न निदानों के आधार पर जिन समस्याओं को हम यथार्थ में पहचानते हैं के सम्बन्ध में, अपने शोध एजेंडों को जुटाने का प्रयास करते हैं। हम क्षेत्र की वैश्विक वैज्ञानिक चुनौतियों एवं सार्वजनिक समस्याओं के प्रति एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण का लक्ष्य रखते हैं।

इस प्रकार ''ग्रुपो दे एस्तुडियोस देल तरबाजो देसदे एल सुर'' (GETSUR) अस्तित्व में आया। GETSUR एक स्थानीय– क्षेत्रीय कार्यमंच है जो वैश्विक अनुसन्धान नेटवर्कों पर भरोसा करता है और सामाजिक एवं श्रम संघ संगठनों के ताने–बाने को मजबूत करने का प्रयास करता है। हम श्रम संघों की आवश्यकताओं के साथ तालमेल और सहजीवन को प्रोत्साहित करते हैं जिसके लिए हमने विश्विद्यालय को बुनियादी ढांचे और लोजिस्टिक्स और उसके साथ साथ प्रशिक्षण, सूचना, और/या चिंतन में विशिष्ट समस्याओं को सम्बोधित करने के लिए ज्ञान एवं शोध क्षमताओं, को उपलब्ध कराया है।

समाज विज्ञान के लिए अक्टूबर विद्रोह वास्तव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है। वैज्ञानिकों के रूप में हम अपने स्वयं के जागरण को देख रहे हैं और इस जाग्रति में भाग लेने की सम्भावना को और इसमें कर्त्ता बनना भी पुनर्जीवित होने और स्फूर्तिदायक है। मेरा मानना हैं कि अनिश्चितता की अवधारणा और अनिश्चितता हमें इस मार्ग पर चलने की अनुमति देने के लिए बहुल सम्भावनाएं में से एक प्रदान करती है।

आपके शोध विषय अनिश्चितता, श्रम बाजार की असुरक्षा हैं और कैसे वे समाज के पुनरुत्पादन में योगदान देते हैं। हालाँकि, आपने उन प्रोजेक्टों में भी भाग लिया हैं जिनमें पुनर्चक्रण प्रारूपों में तेमुको के पडोसी और सरकारी संस्थाएं भी सम्मिलित हैं। क्या आप हमें इन शोध अनुभवों के बारे में कुछ बता सकते हैं और इस प्रकार के समाजशास्त्रीय शोध की विशेष समस्याओं और चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं ?

बेशक। ये अनुभव मुझे मार्ग में मिलने वाले धागों का अनुसरण करने से उभर रहे हैं और जिज्ञासा, शिक्षाशास्त्र और संवेदनशीलता के मध्य ये स्थानीय स्पेस में अन्य कर्त्ताओं के सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। पुनर्चक्रण के अनुभवों के मध्य मैंने चिली के एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) था, के साथ सहयोग किया। यह संगठन ला आरोकनिआ और वालमापु क्षेत्र के कई सामाजिक आंदोलनों, मापुचे समुदायों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। उनका तेमुको शहर में अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी के लिए एक रणनीति और ''शून्य कचरा'' योजना हैं, जिसके लिए उन्होंने 2017 में पर्यावरण सरंक्षण के लिए एक सार्वजनिक फण्ड के लिए एक प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक प्रस्ताव रखा।

1992 से काम में आने वाले शहर के लैंडफिल के दिसंबर 2016 में बंद होने के बाद हमने इस अनुभव को शुरू किया। लैंडफिल ढह गया था और उसने क्षेत्र के भूजल को दूषित कर दिया था। इसे शहर के पश्चिमी भाग में 22 मापुचे समुदायों के बीच में स्थापित किया गया था। इसके आस पास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर इसके परिणामों की कई जांचों में पुष्टि हुई है और सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी आधारभूत ढांचों में निवेश पर्यावरणीय बलिदान के परिणामों के दोषी शमन के रूप में किया था। संदूषण ने स्थानीय अर्थव्यवस्था, रहवास की स्थिति और पर्यावरण को प्रभावित किया। लेकिन इस अनिश्चितता में कई लोगों ने लैंडफिल में अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और बिक्री के साथ आर्थिक रूप से काम करने की संभावना को देखा।

इस प्रकार हमने 2016 में लैंडफिल पर अनौपचारिक पुनर्चक्रण करने वाले, कचरा एकत्रित करने वालों का एक कडेस्टर आयोजित किया। लैंडफिल बंद करने के पूर्व, मैंने राडा के साथ मिलकर पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के संघ के संगठन में सहयोग किया। संघ में 62 सदस्य थे। कुछ क्षेत्र के मापुचे पुरुष और महिलायें थीं, अन्य तेमुको के गरीब इलाकों के लोग थे। उनमें से अधिकांश ने इसे एक पारिवारिक रोजगार की तरह देखा। इस कार्य में, मेरे साथ एक समाजशास्त्र के छात्र भी था जिसने समापन प्रक्रिया और पुनर्चक्रण के आर्थिक विकल्पों के निर्माण पर शोध किया। जब हमें निर्वाह के लिए आर्थिक स्थान की तलाश करने और उसे तैयार करने के लिए संघ के प्रस्ताव के सामना करना पड़ा तभी और वहीँ हमने पारिस्थितिक तरीके से पर्यावरणीय संरक्षण प्रोजेक्ट के प्रस्ताव के बारे में सोचा।

आपकी राय में, दोनों अनुसन्धान क्षेत्र – अनिश्चितता एवं स्थानीय पारिस्थितिक पहलें, कैसे एक दूसरे से सम्बंधित है?

मुझे लगता हैं कि जिस तरह से वे सम्बंधित हैं उसे जिस अनुभव के बारे में आपको बताया था, के उदाहरण से समझाया जा सकता है। इस अनुभव में हमने अन्तर्सम्बन्ध के पहलें मोड़ पर कार्य करना प्रारम्भ कियाः उनके दैनिक कार्य में पुनर्चक्रणकर्त्ताओं की अनिश्चितता एवं क्षेत्र में रहने वाली मापुचे आबादी की अनिश्चितता

>>

और लैंडफिल के पर्यावरणीय नस्लवाद को सहन करना। दोनों प्रकार की अनिश्चितता विकास, समाज, कार्य, प्रकृति और जीवन को समझने के तरीके आपस में जुडी हुई थीं। वे एक संघर्ष में मौजूद थे : लैंडफिल, उसकी स्थापना और उसका बंद होना।

उपभोग पर केंद्रित समाज के उत्पाद के रूप में और पारिस्थितिक अवहनीयता की भौतिकता के रूप में कचरे ने दर्शाया कि इसके इर्द गिर्द अनिश्चितता किस प्रकार बढ़ी है। श्रमिक कूड़े से निर्वाह कर रहे हैं। लोग कचरे में खाने को ढूंढने और इसका सेवन करने के लिए तैयार हैं। अत्यधिक निर्धनता एवं सामाजिक उपेक्षा। इसलिए, लैंडफिल के बंद होने के पूर्व, पुनर्चक्रण में व्याप्त श्रम अनौपचारिकता ने सामाजिक निष्कासन के एक नए क्षेत्र के नेतृत्व किया, जहाँ दृढ़ता और निर्वाह की रणनीति विकसित करना अत्यंत कठिन है। श्रम संघ का गठन राजनैतिक ताकत की गारंटी नहीं है क्योंकि संस्थागत ढांचे ने श्रमिक संगठनों के लिए क्षण भंगुरता को भड़काया है, लेकिन उसी समय उसने हमें विकल्पों को विस्तृत करने के लिए एक सहयोगी व्यक्ति के बारे में सोचने की अनुमति दी।

मानवीय अस्तित्व को धमकाने वाले संकटों की एक श्रंखला है और इसलिए जोखिम के नहीं अपितु जीवन की अनिश्चितता का बहुलीकरण है। मेरा मानना है कि वर्तमान राजनैतिक विवादों ने एक राजनैतिक संवेदनशीलता, विशेष रूप से नारीवादी, पारिस्थितिक और ज्ञान के गैर–औपनिवेशी आंदोलनों को पेश किया है जो हमें एक भयानक, हिंसक और युद्ध पूंजीवाद के सामने तात्कालिकता, संकट और प्रतिबद्धता की भावना पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। ■

सभी पत्राचार दास्तेन जुलियन को <dasten@gmail.com> पर प्रेषित करें।

1. महामारी के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। वे 15 और 16 मई, 2021 को आयोजित किए जाएंगे।

> कोविड–19 एवं वैश्विक असमानताएँ

करीन फिशर, जोहान्स केपलर विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रिया द्वारा

''कोविड–19 एक वैश्विक चुनौती है। हालाँकि, चुनौती जितनी बड़ी होती जाती है, क्षितिज उतना ही राष्ट्रवादी या उससे भी संकीर्ण दृष्टिकोण तक सीमित होता जाता है।''

कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ता है और किसी राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह नहीं करता है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार, मानव विकास सूचकांक – शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्थितियों का एक मिश्रित माप – 1990 के बाद से पहली बार घटने के मार्ग पर है। इस घटाव की दुनिया भर के अधिकांश देशों – अमीर और गरीब – में होने की अपेक्षा है।

इस अवलोकन से एक ''समतावादी कल्पना'' का आह्वान नहीं होना चाहिए। कोविड–19 दर्शाता है कि हम सब एक ही नाव में सवार नहीं हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस्स ने जैसा कहा, ''जहाँ हम सब एक ही समुद्र में हैं, यह स्पष्ट है कि कुछ बड़े जहाज में हैं, जबकि अन्य बहते अवशेषों से चिपक रहे हैं''। महामारी ने मौजदा धन और आय, लिंग एवं प्रजाति की असमानताओं को राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत प्रकट एवं बढ़ाया है लेकिन वैश्विक स्तर पर विशेष कर इसे बहुत भयावह ढंग से बढ़ाया है।

महामारी के उच्च असमान प्रभावों को कई स्तरों – घरों से उप–राष्ट्र एवं राष्ट्रीय स्तर – पर देखा जा सकता है। इस विशेष अनुभाग के आलेख असमानता के व्यापक परिपेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं– अर्थात उत्तर–दक्षिण विभाजन। अमीर एवं निर्धन देशों के मध्य निहित असमानताओं को दर्शाने के लिए तीन विषयों की थीम हैः कोविड–19 वैक्सीन, चिकित्साशास्त्र एवं प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच; सॉवेरेन ऋण भार एवं असमान वित्तीय सम्बन्ध; और जलवायु परिवर्तन से असमान जोखिम।

काजल भरद्वाज का पहला आलेख मौजूदा विश्व व्यापार शासन के ट्रिप्स (TRIPS) समझौते को उजागर करता है जो स्वास्थ्य के मानवाधिकार से अधिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (IPR) एवं निजी लाभ को महत्व देता है। कंपनियों के एकाधिकार कोविड–19 वैक्सीन के लिए असमान, असमतामूलक एवं आश्चर्यजनक भगदड़ को जन्म देते हैं जिसे ''वैक्सीन रंगभेद'' या ''वैक्सीन औपनिवेशवाद'' के रूप में देखा जाता है। अपने आलेख में कैमिला जिआनेला असमान वैश्विक वैक्सीन प्राप्त करने की लड़ाई के एक स्थान के रूप में पेरू का दौरा करती हैं। वैक्सीन क्रय करार की कुछ शर्तों को स्वीकार नहीं करने के कारण फाइजर ने उनके गृह देश को आपूर्ति सूची में सबसे नीचे रखा। यह इसके बावजूद था कि पेरू में लैटिन अमेरिका के अधिकतम कोविड–19 रोगी एवं मृत्यु दर है।

महामारी एवं उसकी परिणामी वैश्विक मंदी देशों को एक ऋण जाल में धकेल रही है। यह अकेले निर्धन देशों की समस्या नहीं है। वैश्विक सॉवरेन डेब्ट मॉनिटर 2021 के अनुसार, वैश्विक दक्षिण में सर्वे किये गए 148 देशों में 132 गंभीर रूप से ऋणग्रस्त हैं। क्रिस्टीना लास्कारिदिस कोविड–19 के अंतर्गत सॉवरेन ऋण की असमान भौगोलिकता को दिखाती हैं। वे स्पष्ट करती हैं कि ऋण से सम्बंधित नीति रहवास की स्थितियों पर व्यापक प्रभाव के साथ वैश्विक शक्ति का प्रदर्शन भी है। लकीस्टार मियानदाजी इसके साथ लाभ के असमान वैश्विक भौगोलिकता को जोड़ते हैंः अवैध वित्तीय प्रवाह विश्व के निर्धनतम देशों से खींचे जाते हैं और वे वैश्विक उत्तर के व्यक्तियों, व्यापार ''साझेदारों'', पारदेशीय निगमों के मुख्यालयों और टैक्स हेवेन्स के जेबों में पहुँचते हैं। वे लिखती हैं कि हर वर्ष अफ्रीका संयुक्त रूप से आधिकारिक विकास सहायता और विदेशी निवेश के पूर्ण वार्षिक प्रवाह के बराबर खो देता है। इसका अर्थ है कि इन देशों के पास अपनी अर्थव्यवस्था में नकद डालने या कोविड–19 महामारी के प्रत्युत्तर में विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए वित्तीय स्थान नहीं है। ऋण भुगतान दायित्व और अवैध वित्तीय प्रवाह उनकी अर्थव्यवस्था का और गला घोंट देंगे और दीर्घ अवधि के विकास को बाधित करेंगे, जैसा कि वे जाम्बिया के उदहारण से दिखाती हैं।

अंतिम लेकिन कम नहीं, इ. वेंकट रमनैया और विहा इमांदी जिसे वे ''जुड़वां आपदा'' कहते हैं, की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्रों में कोरोनावायरस और पारिस्थितिक भेद्यता दोनों तेजी से बढ़ती हैं। वे दिखाते हैं कि महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जल तनाव, बाढ़ या चक्रवात जैसे पारिस्थितिक आपदाओं से और अधिक उत्तेजित होते हैं। पुनः, पर्यावरणीय आपदाओं के परिणाम असमान रूप से वितरित होते हैं और मुख्य रूप से उन्हें प्रभावित करते हैं जो पहले से ही महामारी से असमान रूप से पीड़ित हैं।

कोविड–19 एक वैश्विक चुनौती है। यद्यपि जितनी समस्याएं निकट आती हैं और चुनौतियां जितनी बड़ी होती जाती हैं, उतना क्षितिज, ऐसा लगता है, एक राष्टवादी या अधिक संकीर्ण परिपेक्ष्य, तक सीमित होता है। लेखकों का आह्वान हैः कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक सब सुरक्षित नहीं हैं! ■

सभी पत्राचार करीन फिशर को <Karin.fischer@jku.at> पर प्रेषित करें।

> लाभ के पहले लोग: कोविड–19 में आह्वान

काजल भारद्वाज, अधिवक्ता, नई दिल्ली, भारत द्वारा

एसोसिएशन फॉर द ब्रिटिश फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री, वेस्टमिंस्टर, लंदन, 2021 के कार्यालयों में वैश्विक वैक्सीन समानता के लिए ग्लोबल जस्टिस नाउ और द पीपल्स वैक्सीन प्रोजेक्शन प्रदर्शन करता हुआ।
साभारः फ्लिकरः जेस हर्ड / ग्लोबल जस्टिस नाउ।

सन् 2001 में विश्व व्यापार संघ (WTO) ने अपने बहुपक्षीय समझौते, ट्रिप्स समझौते, में निहित बौद्धिक सम्पदा (IP) दायित्वों के एचआईवी महामारी को सम्बोधित करने के वैश्विक प्रयासों पर पड़ने वाले प्रभावों का सामना किया। उस समय, बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियों ने एचआईवी के वहनीय जेनेरिक उपचार के आयात की अनुमति देने के कानूनी प्रावधानों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला पर मुकदमा दायर किया। उपचार के पेटेंट धारक के रूप में, ये कम्पनियाँ कई हजारों डॉलर चार्ज कर रही थीं जबकि एचआईवी की जेनेरिक दवाओं की कीमत एक डॉलर प्रतिदिन थी। कंपनियों ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीकी कार्यवाही ने ट्रिप्स समझौते का उल्लंघन किया था। मामला दायर करने के लिए फार्मा कंपनियों के खिलाफ वैश्विक आक्रोश के फलस्वरूप सभी WTO सदस्यों ने ट्रिप्स एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा को अपनाया। इसने पुष्टि की कि देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने एवं सभी के लिए दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के अपने अधिकार के समर्थन में ट्रिप्स समझौते की व्याख्या करने का अधिकार था।

> कोविड–19 एवं ट्रिप्स बाधाएँ

बीस वर्ष बाद, एक और महामारी, कोविड–19, के समय में विश्व व्यापार संगठन के दो–तिहाई सदस्य मांग कर रहे हैं कि ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत आईपी दायित्वों को माफ किया जाए। दोहा घोषणा के द्वारा उजागर ट्रिप्स का लचीलापन– अनिवार्य लाइसेंस, सामानांतर आयात या कड़े पेटेंट योग्यता मानकों– ने देशों को सस्ते एचआईवी, हेपेटाइटिस सी, कैंसर और हृदय रोग उपचार तक पहुँच में मदद की है। लेकिन भारत एवं दक्षिण अफ्रीका का वर्तमान प्रस्ताव तर्क देता है कि कोविड–19 जैसी तेजी से फैलने वाली, तेजी से परिवर्तनशील, संक्रामक बीमारी के लिए आईपी बाधाओं में पूर्ण छूट की आवश्यकता है जिससे सभी देश और प्रतिस्पर्धी कोविड–19 सम्बंधित किसी भी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के अनुसन्धान, विकास और उत्पादन के लिए स्वतंत्र हो सकें। ऐसा जटिल लाइसेंसिंग वार्ताओं में समय गवायें बिना, मल्टी–मिलियन डॉलर के आईपी उल्लंघन के मुकदमों के डर के बिना और अमीर देशों के व्यापार दबाबों के डर के बिना होगा ।

जैसा कि अपेक्षित था, अमीर देश यह तर्क दे रहे हैं कि आईपी अवरोध पैदा नहीं कर रहा है। लेकिन महामारी की बेरंग प्रथम वर्षगांठ पर, सबूत इसके विपरीत हैं। इसके बावजूद कि वैश्विक ध्यान कोविड वैक्सीन की असमान, असमतामूलक एवं चौकाने वाली

> >

भगदड़ जिसे ''वैक्सीन रंगभेद'' के रूप में देखा जा रहा है, पर केंद्रित हैं, असमानता ने प्रारम्भ से ही मास्क, निदान, उपकरणों एवं उपचार तक पहुँच को कम कर दिया था।

व्यापक जनता के लिए, आई पी सुरक्षा की पहुँच और शक्ति का अहसास शायद इस खबर से आया कि वेंटीलेटर वाल्व की 3डी प्रिंटिंग पर काम कर रहे इतालवी शोधकर्ताओं को आईपी धारकों से कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। एक अमेरिकी सीनेटर ने मास्क डिजाइन के सैंकड़ों पेटेंट रखने वाली और उन्हें उग्रता से लागू करने वाली कंपनी 3M को आपूर्ति बढ़ने के लिए अपने पेटेंट छोड़ने को कहा। कानूनी कार्यवाही की धमकियों ने फार्मा कंपनी रोश को नेदरलॅड्स में अपने कोविड–19 परीक्षणों के नुस्खों का खुलासा करने के लिए मजबूर किया। 45 मिनट के कोविड–19 टेस्ट के लिए सेफिड की 19.80 यूएस डॉलर की कीमत 5 यूएस डॉलर जितनी कम हो सकती है और नागरिक समाज संगठनों ने इसकी निंदा की। यूएस की बहुराष्ट्रीय कंपनी गिलियड एंटी–वायरल दवा रेमेडेसिवर को 2340 यूएस डॉलर में बेचती है। विकासशील देशों में आपूर्ति करने वाले इसके कुछ लाइसेंसधारी 320 यूएस डॉलर चार्ज करते हैं। लेकिन लिवरपूल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन से इसकी कीमत 6 यूएस डॉलर से भी कम हो सकती है।

जहाँ अमीर देश प्रति सेकंड एक व्यक्ति को टीका लगा रहे हैं, अधिकांश निर्धन देशों को अभी पहली खुराक भी देनी बाकी है। वैश्विक दक्षिण में वैक्सीन निर्माण की काफी क्षमता है लेकिन पेटेंट, व्यापार सीक्रेट्स और डाटा एकाधिकार सहित आईपी सुरक्षा की विस्फोटक स्थिति हमारे मार्ग में है। यूरोपीय पेटेंट ऑफिस के आंकड़े कोरोनावायरस वैक्सीन से सम्बंधित सैंकड़ों पेटेंट दिखाते हैं। अध्ययन सुझाव देते हैं कि वैक्सीन पेटेंट सामग्री, प्रक्रिया तकनीकों, आयु समूह, एवं खुराक के नियमों को सम्मिलित करते हुए बेहद व्यापक होते हैं। ट्रेड सीक्रेट सुरक्षा वैक्सीन उत्पादकों को उस ज्ञान को अपने पास रखने की अनुमति देता है जो अन्य निर्माताओं को उत्पादन को जल्दी बढ़ने में मदद कर सकता है, जबकि डाटा और बाजार अनन्यता उनके पंजीकरण में और अवरोध पैदा करेगी ।

> गहराता उत्तर–दक्षिण उपचार विभाजन

ऑक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्विद्यालय के मूल वादे के अनुसार उनकी कोविड–19 तकनीकों पर आईपी के गैर–अनन्य लाइसेंसिंग के तहत बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपलब्ध होना चाहिए था। इसके बजाय, एस्ट्राजेनेका के साथ एक विशेष सौदा किया गया जिसने कुछ निर्माताओं के साथ गुप्त उप–लाइसेंस प्रदान किये गए। उत्पादन क्षमता स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है जैसे भारत से खुराक कुछ विकासशील देशों में जाती है। और निर्लाभ कीमत का वादा पूरा नहीं किया गया और निर्धन देश कथित तौर पर 3 यूएस डॉलर और 8 यूएस डॉलर प्रति खुराक के मध्य भुगतान कर रहे हैं।

दिलचस्प बात है, फ्रांस, जर्मनी एवं कनाडा जैसे अमीर देश कोविड–19 के अनिवार्य लाइसेंस को सुविधाजनक बनाने के लिए विधिक उपायों को अपनाने वाले प्रथम देशों में सम्मिलित थे। इजराइल ने एंटी–वायरल लोपिनवीर/रितोनवीर के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी किये। हंगरी और रूस ने रेमेडेसिवेर के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी किये। आईपी अवरोधों को दूर करने की सरकारी कार्यवाही के परिणामस्वरूप अक्सर कम्पनियाँ आईपी के इर्द गिर्द अपने मुनाफाखोरी के व्यवहार को संशोधित करती हैं। इजराइल के अनिवार्य लाइसेंस के परिणामस्वरूप एबवी ने घोषणा की कि वह वैश्विक स्तर पर लोपिनवीर/रितोनवीर पर अपने पेटेंट लागू नहीं करेगी। भारत, थाईलैंड और अर्जेंटीना में मरीजों के समूहों ने रेमेडिसवीर और फेविपिरवीर पर पेटेंट चुनौतियाँ दायर की है। एक कनाडियाई निर्माता ने सार्वजनिक रूप से जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के लिए लाइसेंस माँगा है और वे अनिवार्य लाइसेंस का भी लक्ष्य रख सकते हैं।

अमीर देशों ने कोविड–19 वैक्सीन, परीक्षणों एवं उपचार के विकास में सार्वजनिक धन के रूप में लाखों का निवेश किया है। फिर भी वे उच्च कीमतों का भुगतान कर रहे हैं और आपूर्ति में व्यवधान का सामना कर रहे हैं। आईपी अवरोधों को दूर करने के लिए विधिक उपायों को काम में लेने, जानकारी के आदान–प्रदान को खोलने और उत्पादन बढ़ने के बजाय, वे उपलब्ध आपूर्ति को उठा रहे हैं और निर्यात प्रतिबंधों को लागू कर रहे हैं। इससे भी बुरा यह है कि, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता, अपनी कीमतों या अपनी समझौते के बारे में पारदर्शी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ वार्ताओं ने कथित तौर पर ये मांग करी कि दुष्प्रभावों प्रभावों के लिए देश कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर दूतावास जैसी सरकारी संपत्ति को जमानत के रूप में रखते हैं। जहाँ कंपनियों ने WHO के टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल के साथ जुड़ने से इंकार करके या कोविड–19 वैक्सीन के उचित वितरण के उद्देश्य वाली कोवेक्स सुविधा को आपूर्ति की प्राथमिकता से हटाकर स्वैच्छिक तंत्रों को कमतर किया हैं। फार्मा संघ आईपी अवरोधों को दूर करने के प्रयास करने वाली सरकारी एवं यूएन एजेंसीज के खिलाफ अपनी पैरवी बढ़ा रहे हैं। WHO और यूएन एजेंसीज ट्रिप्स से छूट के समर्थन में मुखर रूप से सामने आयी हैं। लेकिन WTO सचिवालय आँख मूंद कर बैठा है और हठधर्मिता से स्वैच्छिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। इन दृष्टिकोणों के अधिकाधिक मजबूत होने के साथ, कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रिप्स छूट के लिए अभियानों के बाद 5 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव ने ट्रिप्स छूट, यद्यपि केवल कोविड–19 वैक्सीन तक सीमित, के समर्थन की आश्चर्यजनक घोषणा की।

चाहे अमेरिका का दबाब वार्ताओं को ट्रिप्स छूट के निकट ला रहा है, यह स्पष्ट है कि हमने कंपनियों के सही कार्य करने के इंतजार में पिछला वर्ष बर्बाद कर दिया। ''पीपल्स वैक्सीन'' का आह्वान तीव्र होता जा रहा है। जैसे जैसे नए वैरिएंट सामने आ रहे हैं, मेरे देश जैसे, विनाशकारी अनुक्रमिक लहरों का सामना कर रहे हैं और कोविड–19 से होने वाली मौतों और बीमारी रोगियों, परिवारों एवं स्वास्थ्य प्रणाली पर अपना कहर ढाहती हैं। हमारे पास उन जटिल ट्रेड नियमों, जो लोगों के ऊपर लाभ को रखते हैं, को देखने के लिए बर्बाद करने का और समय नहीं है। सभी के लिए, हर जगह कोविड–19 स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मार्ग को साफ करने के लिए ट्रिप्स से छूट एक आवश्यक पहला कदम होगा। ■

सभी पत्राचार काजल भारद्वाज को <k0b0@yahoo.com> पर प्रेषित करें।

कोविड–19 वैक्सीन: वैश्विक असमानताओं का खुलासा

केमिला जियानेला, पोंटिफेसिया यूनिवर्सिदाद केटोलिका देल पेरू–सिसेपा, पेरू द्वारा

वैक्सीन वितरण उसी असमान पैटर्न का अनुसरण करता है जैसा कि वैश्विक असमानताओं ने महामारी से पहले किया था।
साभारः फ्रेंकीडेमेयर/गेटी इमेजेज/आईस्टॉकफोटो।

कोविड–19 महामारी के दुनिया भर में विनाशकारी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव हो रहे हैं। हालाँकि, इस वैश्विक संकट से जो खतरनाक सन्देश उभरा है, वह है कि हम सब एक समान संकट का सामना सब जगह कर रहे हैं (हम सब एक ही नाव में सवार हैं), जैसे कि बर्गेन, नॉर्वे में लॉकडाउन का सामना वैसा ही है जैसा लीमा, पेरू में; या लीमा के अमीर इलाकों में लॉक डाउन का सामना करना वैसा ही है जैसा उसी शहर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों के द्वारा लॉक डाउन की चुनौतियाँ का सामना करना।

राज्यों में समान पहुँच की गॉरन्टी देने के कुछ आह्वान देने के बावजूद इस समरूप कल्पना ने कोविड–19 वैक्सीन के असमान वितरण की अनुमति दी है। सच यह है कि अमीर देश यह दौड़

>>

जीत गए: वे पहले थे जिनके पास वैक्सीन खरीदने की क्षमता थी और इसके परिणामस्वरूप अपनी आबादी के टीकाकरण में भी। जहाँ यह सच है कि नॉर्वे जैसे कुछ अमीर देशों ने जनवरी 2021 से गरीब देशों के टीके के खुराकों को साझा करने की प्रतिबद्धता का वादा किया है, टीकों तक पहुँच देश की धन सम्पदा से निध ारित हो रही है।

> निजीकृत ड्रग नवोन्मेष व्यवस्था

दुनिया भर में वैक्सीन तक पहुँच की जिस स्थिति का सामना हम कर रहे हैं वह विशिष्ट देशों की (केवल) कंजूसी का परिणाम नहीं है, अपितु यह समस्याग्रस्त वैश्विक ड्रग नवोन्मेष व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है। अमीर देशों ने वैक्सीन के अविष्कार के लिए सार्वनजिक निधि का आवंटन किया है। फाइजर के मामले में भी, जो अपनी वैक्सीन के अविष्कार में सार्वजनिक निधि की भागीदारी से इंकार करता है, रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि उसकी सहयोगी कंपनियां जिन्होंने वैक्सीन का सह–विकास किया है उन्हें सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ है। अमीर देशों द्वारा वैक्सीन विकास में भागीदारी उन्हें ''बेहतर कीमत'' के लिए मांग करने की अनुमति देती है लेकिन यह निजी कंपनियों द्वारा वैक्सीन से लाभ कमाने के अधिकार से इंकार नहीं करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान नियमों के तहत, और रोग एवं उसने नए रूपों के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका की आबादी का टीकाकरण करने की तत्काल आवश्यकता के बावजूद दक्षिण अफ्रीका को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड–19 वैक्सीन लिए अधिकांश यूरोपीय देशों की तुलना में लगभग 2.5 गुणा अधिक भुगतान करना पड़ा है।

सार्वजनिक निधि की भागीदारी ने निजी वैक्सीन निर्माताओं को गोपनीयता की शर्तों और उसके साथ यदि कोविड–19 टीकों के अप्रत्याशित दुष्प्रभाव हों, तो मुकदमों से बचने के लिए कानूनी सुधारों के बारे में मांग करने से नहीं रोका है। वैक्सीन की आवश्यकता, और कोविड–19 वैक्सीन के व्यापार पर कुछ न्यूनतम शर्तें लागू करने के लिए वैश्विक नेतृत्व के अभाव ने वैक्सीन निर्माताओं को बहुत शक्ति प्रदान दी है। वे उन देशों के साथ वार्ता करने में देरी कर रहे हैं या उन्हें अवरुद्ध कर रहे हैं जिन्हे टीकों की आवश्यकता हैं। इस प्रकार वे इन तक पहुँच में देरी कर रहे है और अंततः और मौतें और वायरस के नए रूपों के विकास (और प्रसार) में योगदान दे रहे हैं।

इसका एक उदहारण पेरू और फाइजर के साथ उसकी असफल वार्ता है। लैटिन अमेरिका एवं केरीबियन के साथ, पेरू वैश्विक स्तर पर उच्चतम कोविड–19 घटनाओं और मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। जनवरी 2021 तक, जब देश द्वितीय लहर के प्रारम्भ को अनुभव कर रहा था, स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही चरमरा चुकी थी। 2020 में, पेरू सरकार ने फाइजर के साथ बातचीत शुरू की थी, लेकिन कंपनी द्वारा गैर–देयता से सम्बंधित कुछ शर्तों को स्वीकार करने से उन्होंने इंकार कर दिया था। परिणामस्वरूप, देश में कोविड–19 के विनाशकारी प्रभावों के बावजूद पेरू को सूची में सबसे नीचे रखा गया। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका और टीकों की कीमतों के मामले में हुआ, इसे पूरी छूट के साथ किया गया हैय वैक्सीन निर्माता नियम लागू कर रहे हैं, और एक वैश्विक इमरजेंसी के मध्य वे यह तय कर रहे हैं कि किस को किस कीमत तक पहुँच मिलेगी।

> वैक्सीन तक पहुँच और स्वास्थ्य का अधिकार

टीकों जैसे दवाओं तक पहुँच शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के लिए सभी के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति के लिए मूलभूत तत्वों में से एक है। दवाओं में नवोन्मेष और इस नवोन्मेष तक पहुँच, दवाइयों तक पहुँच का एक प्रमुख तत्त्व है, और इसके फलस्वरूप, दवा नवोन्मेष तक पहुँच को विनियमित करने वाले कानून एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के केंद्रीय तत्त्व हैं। कोविड–19 महामारी ने वैश्विक नेतृत्व के अभाव की कमी और मूल्यवान वस्तुओं के निर्माताओं पर शर्तें लागू करने में राज्यों की कमजोरी के साथ साथ वर्तमान चिकित्सा नवोन्मेष योजनाओं की सीमाओं का भी खुलासा किया है। निजी कंपनियों को सार्वजनिक निधि का आवंटन स्पष्ट रूप से दवाओं तक सर्वभौमिक पहुँच की गारंटी के लिए पर्याप्त नहीं है। ■

सभी पत्राचार केमिला जियानेला को <gianella.c@pucp.edu.pe> पर प्रेषित करें।

> लेनदारों और देनदारों के मध्य विभाजन को बनाये रखना

क्रिस्टीना लस्कारिडिस, द ओपन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम द्वारा

अरबु द्वारा चित्रण।

अमीर देश आर्थिक मंदी का मुकाबला ऋण–वित्तपोषित खर्च एवं आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से करते हैं, जबकि वैश्विक दक्षिण में निम्न और मध्यम आय वाले देश एक उभरते ऋण जाल में फँस जाते हैं। वैश्विक दक्षिण में ऋण राहत पर लेनदारों के हितों को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण को प्रोत्साहित करने वाले दीर्घकालिक दृष्टिकोण कोविड के समय उपनिवेशवाद और संप्रभु ऋण की पूर्व भौगोलिकता से पुनः प्रबलित हो रहे हैं।

> उत्तर–दक्षिण असमानता तथा वैश्विक ऋण–वित्तपोषित

डेविड ग्रेबर उन लोगों में से थे जिन्होंने यह खुलासा किया कि निर्भरता और असमान शक्ति संबंधों के ऐतिहासिक संबंधों को ढंकने में ऋण कैसे प्रभावी है। उन्होंने तर्क दिया कि बारम्बार ऋण की भाषा में फ्रेम किये हिंसा के संबंधों के कमजोर स्थिति में होने वाले के गलत दिखाई देने के तात्कालिक प्रभाव होते हैं। अंतराष्ट्रीय ऋण औपनिवेशिक प्रोजेक्टों का भाग थे, और चुकौती में कठिनाइयों ने लेनदारों एवं देनदारों के मध्य संघर्ष को उत्पन्न किया जिसका परिणाम प्रत्यक्ष विदेशी पर्यवेक्षी तंत्र और सैन्य हस्तक्षेप में हुआ, लेकिन ऐसा विरले ही होता था कि देनदार भुगतान को सफलतापूर्वक निलंबित कर पाते और ऋण वसूली को रोक पाते थे। हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऋण में वैश्विक असमानताओं को नव–उपनिवेशवाद और वित्तीयकरण असमान ऋण संबंधों की विशेषता है। अधीनस्थ वित्तीयकरण विकास की संरचनात्मक बाधाओं के साथ असमान ऋण संबंधों की विशेषता है जो कोर के साथ अधीनस्थ भूमिका में होने से आती है।

इसका एक पहलू अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली से सम्बंधित है। जैसा कीन्स ने और बाद में कई उत्तर– कीन्सवादियों ने माना, तरलता की वरीयता वित्तीय परिसम्पत्तियों में एक पदानुक्रम को प्रकट करती है जो अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थितियों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आगामी ऋण जाल की चेतावनियाँ महामारी की पूर्व संध्या तक बढ़ रही थीं। वैश्विक उत्तर में संकट के प्रत्युत्तर में जन्मी अमेरिका में वर्षों से ढीली मौद्रिक नीति के साथ वित्तीय फर्मों की कार्यवाहियों ने वैश्विक तरलता में वृद्धि की जिसका वर्तमान ऋण संकट पर प्रारंभिक प्रभाव पड़ा। इसने विकासशील दुनिया भर में लाभ के लिए वैश्विक खोज को अग्रेषित किया जिसने कई निम्न एवं निम्न–मध्यम आय वाले देशों के लिए एक बदलते लेनदार परिदृश्य का नेतृत्व किया जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अत्यधिक असमान पहुँच और वित्त की लागत थीं। एक देश की स्वयं को वित्त पोषित करने और पुनर्वित्त करने की क्षमता के साथ अपने नियंत्रण से परे कारकों पर अत्यधिक निर्भर होने ने "बाजार जोखिम" के प्रति निहित संरचनात्मक भेद्यता को निर्मित किया। साथ ही इसने वस्तु निर्भरता से उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा विनिमय की दीर्घकालिक चिंता को भी जोड़ा।

ऋण चुकौती की समस्याएं, विकास की बाधाओं और उत्पादन की वैश्विक संरचनाओं जो स्वयं औपनिवेशिक अतीत की उत्पाद हैं, से उभरती हैं और सार्वजनिक वित्त के घरेलू कुप्रबंधन के बारे में अन्तर्निहित संस्थागत विफलताओं से कम सम्बंधित हैं। जब ऋण चुकौती समस्याएँ आती हैं, देशों को विकास योजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर होने के साथ लेनदार मंचों, असमान कानूनी वातावरण,

> >

पूंजी बाजारों से बहिष्कार और लेनदार मुकदमों के जोखिम जैसे मिश्रण का सामना करना पड़ता है। यह अक्सर संकुचनकारी आईएमएफ कार्यक्रमों के साथ–साथ होता है जो ऋण समस्याओं के न्यायसंगत और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने में विफल रहते हैं और वे कमजोर आबादी की रक्षा करने की राज्य की क्षमता को कमजोर करते हैं। जैसा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, ऋण संकटों को ''बहुत कम, बहुत देर से'' की विशेषता वाले तरीकों से निपटाया जाता है, जो अक्सर ऋण स्थिरता को पुनः–स्थापित करने में विफल रहते हैं और ऐसा देनदार देश के लिए बड़ी सामाजिक लागत पर होता है।

> कोविड–19 का ऋण पर प्रभाव

महामारी की शुरुआत के साथ, वैश्विक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक असमानताएँ उजागर एवं तीव्र हुईं हैं। व्यापार, जिस पर देश विदेशी मुद्रा के स्त्रोत के रूप में निर्भर हैं, में व्यवधानों और वित्तीय बाजारों में निर्धारित प्रमुख वस्तुओं की कीमत में गिरावट के साथ साथ, 2020 के बसंत में पूंजी प्रवाह का उलटाव अब तक के रिकॉर्ड का सबसे बड़ा था। इस के कारण देशों की मुद्राओं का मूल्यह्रास हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा ऋण चुकौती का बोझ और भी बढ़ गया। संकट के दौरान हार्ड मुद्रा तक पहुँच की कमी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में असमान एकीकरण और अधीनस्थ स्थिति को दर्शाती है और प्रतिक्रिया करने की असमान क्षमता का निर्माण करती है। जहाँ यह आय समूहों के लिए राजकोषीय सहायता उपायों के स्पष्ट रूप से भिन्न पैमानों में काफी स्पष्ट है, आवश्यक तरलता तक असममित पहुँच शक्तिशाली कर्ताओं द्वारा की गयी कार्यवाहियों से पुनः प्रबलित होती है।

केवल कुछ बड़े देशों के पास यूएस फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भ की गयी बढ़ी हुईं डॉलर स्वैप लाइन्स तक पहुँच है, और क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था ज्यादातर निष्क्रिय रही है, जिसने वैश्विक ऋण मुद्दों पर मुख्य नीति प्रतिक्रिया का जी 20 और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से आने के लिए छोड़ा है। फिर भी, बिना शर्त और ऋण मुक्त वित्तपोषण के लिए आवश्यक $2.5 ट्रिलियन के अनुमान के साथ आय समूहों में, $1 ट्रिलियन अनुमानित ऋण–निरस्तीकरण और ऋण–संरचना के लम्बे समय से अतिदेय बदलाव के बावजूद, प्रत्युत्तर ने क्षेत्रों और आय समूहों के पार महंगे ऋणों तक पहुँच में वृद्धि पर भरोसा किया है, ऐसा अक्सर उन देशों को जो पहले से ही ऋण भुगतान/चुकौती में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कुछ देश पहले से ही सार्वजनिक राजस्व की राशि ऋण– सेवा पर खर्च करते हैं जो स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च की तुलना में कई गुना अधिक है। अप्रैल 2020 में जी 20 द्वारा स्थापित डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव (DSSI) के माध्यम से आईएमएफ ऋण और द्विपक्षीय ऋण–सेवा का अस्थायी स्थगन, मौजूदा ऋण समस्याओं को और खराब करता है और, ये अप्रत्यक्ष रूप से गैर–भाग लेने वाले निजी और बहपक्षीय लेनदारों को भुगतान के लिए सक्षम बनाते हुए कई वर्षों की भावी मितव्यतता को अग्रेषित करने का संकेत है। DSSI के स्वैच्छिक पहलू का अर्थ है कि ऋण–सेवा राहत आंशिक है, और गैर–भाग लेने वाले लेनदारों के लिए भुगतान अनुकूल है और डिलीवरी महँगी शर्तों पर है और उसकी आवश्यकता से बहुत कम है। पुनर्गठन को सम्बोधित करने के लिए नवंबर 2020 में स्थापित कॉमन फ्रेमवर्क इन ज्ञात संस्थागत विफलताओं को दर्शाता है।

> एक विषम अंतर्राष्ट्रीय ऋण संरचना

लेनदारों के पूरे समग्र को प्रशासित करने, सामूहिक कार्यवाही समस्याओं को रोकने, अंतर–लेनदार समानता सुनिश्चित करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह सुनश्चित करना कि ऋण चुकौती कठिनाइयों को तेजी से, पारदर्शिता से, स्वतंत्रता से और व्यापक रूप से इस तरह निपटाया जाये कि ऋण संकट का देशों की आबादी पर न्यूनतम प्रभाव पड़े के सन्दर्भ में यह महामारी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय ऋण संरचना की लम्बे समय से ज्ञान अक्षमता को उजागर करती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा दृष्टिकोण अपने हितों के अनुसार ऋण संकट का प्रबंधन करने के लिए लेनदारों के लगातार प्रयासों का परिणाम है और ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों द्वारा सम्बोधित करने के प्रस्ताव और कोशिशों को लगातार अस्वीकार करते हैं। इस व्यवस्था का एक केंद्रीय तत्त्व विश्व बैंक और आईएमएफ का मितव्यतता कार्यक्रम है जो अक्सर मानवाधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव में फलता है और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया जो '' ऋण बोझ को बढ़ाते हुए समस्या के विस्तार को कम आंक और आवश्यक राहत को कमतर कर ऋण को ''धारणीय'' के रूप में अंकित करते हैं। इस दौरान, जैसा कि कुछ उच्च आय वाले देशों में निरंतर प्रोत्साहन की घंटी तेज बजती है, वैश्विक ऋण समस्याओं की प्रतिक्रिया इस धारणा पर आधारित है कि विकास महामारी–पूर्व के स्तर पर वापस आ जायेगा और यह कि अस्थायी घाटे के खर्च के बाद, निवेश को छोड़ते हुए और सरकारी खर्चों को कम करने के लिए आवश्यक सामाजिक खर्च और निवेश को छोड़ते हुए देश राजकोषीय मितव्यतता की महामारी को गले लगायेंगे।

हम जानते हैं कि आईएमएफ की शर्तें और मितव्यतता वृद्धि की संभावनाओं को बिगाड़ती हैं, इनका स्वास्थ्य, असमानता और निर्धनता, पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है और ऋण चुकाने का एक खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ यह अल्प वित्तपोषित, कमजोर, सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं का पुनरुत्पादन करता है, यह इन संस्थाओं द्वारा सामना की जाने वाली वैधता की कमी को भी पुष्ट करता है। प्रत्युत्तर ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि संस्थागत प्रक्रियाएँ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण के ऐतिहासिक तत्वों को पुष्ट करती हैं। ऋण अनुमोदन प्रक्रिया देनदारों और लेनदारों के मध्य असमान शक्ति का परिचायक है जो ज्ञान की राजनीति पर प्रकाश डालती है कि कौन तय करेगा कि किस का भुगतान किया जा सकता है और किसका नहीं। यह लेनदारों को देनदारों की स्थिति को बेहतर करने के लिए ऋण के पुनर्गठन की विफलता के ऊपर ऋण पुनर्गठन को प्राथमिकता देने के लिए सक्षम बनाता है। ■

सभी पत्राचार क्रिस्टीना लस्कारिडिस को <christina.laskaridis@open.ac.uk> पर प्रेषित करें।

> अफ्रीका में निर्धनता और असमानताओं को कम करने की चुनौतिया

लकीस्टार मियानदाजी, प्रोग्राम विशेषज्ञ, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एवं अफ्रीका के लिए समन्यवक, यूएनडीपी अफ्रीका फिनान्शियल सेक्टर हब, दक्षिण अफ्रीका द्वारा

मार्च 2020 में, दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के आने से पहले ही अधिकांश संकेतकों द्वारा मापी गयी असमानता दशकों से बढ़ रही थी। कोविड–19 महामारी और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इसके अप्रत्याशित परिणामों ने राष्ट्रीयता, आयु, लिंग, प्रजाति, राष्ट्रीय या नस्लीय मूल, धर्म, आर्थिक स्थिति और अन्य आयामों में अंतर के कारण असमानता के बहुआयामी पहलुओं को और अधिक बढ़ा दिया है।

> निर्धनता और असमानता पर पीछे खिसकना

हालाँकि अफ्रीका में कोविड–19 का प्रसार और मृत्यु दर अभी भी कम हैं, लेकिन इस महाद्वीप को अब महामारी से और बिगड़े गंभीर ऋण एवं वित्तीय संकट से उबरने की चुनौती दी जा रही है। यह विशेष रूप से बेहतर स्वस्थ्य देखभाल, भोजन एवं शिक्षा तक पहुँच जैसे क्षेत्रों में 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की उपलब्धि की दिशा में अफ्रीका के पूर्व के प्रयासों को कमजोर कर रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि यह 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनायी गई SDGs में इस स्वीकारोक्ति को कमजोर करता है कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए असमानता को कम करने की आवश्यकता है। महाद्वीपीय स्तर पर, एजेंडा 2063 के तहत अफ्रीका की आकांक्षाएं, समावेशी आर्थिक वृद्धि और धारणीय विकास को बढ़ावा देने की महाद्वीप की दीर्घकालिक परिवर्तनकारी दूरदृष्टि भी निर्धनता और असमानता को समाप्त करने को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार, असमानता विकास और आर्थिक वृद्धि से घनिष्ठता से जुडी हुई है और विश्व स्तर पर एक प्रमुख नीतिगत मुद्दा बन गई है।

दुर्भाग्य से, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने भविष्यवाणी की कि 2020 में सब–सहारा अफ्रीका में अत्यधिक निर्धनता में सबसे अधिक वृद्धि होगी जिसमें महामारी के कारण 26 मिलियन अतिरिक्त लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे होंगे। यह आंकड़ा सब–सहारा अफ्रीका को 2015 के निर्धनता स्तर पर ले जाता है, जिसका अर्थ इस क्षेत्र में 5 साल की प्रगति का नुकसान होना है। इसलिए, पहले से कहीं अधिक, अफ्रीका के लिए निर्धनतम और सबसे अधिक हाशिये के लोगों के जीवन के सभी पहलुओं में धारणीय, न्यायसंगत, और समतामूलक समाज का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

कई अफ्रीकी देशों के लिए, आर्थिक असमानता– समाज के विभिन्न समूहों के मध्य आय और अवसर का असमान वितरण – सबसे अधिक चिंता का विषय है। उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाले अफ्रीकी देश जैसे नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को और अंगोला भी निर्धनता और असमानता के उच्चतम स्तरों में से कुछ को दर्ज कराते हैं।

असमानता को कम करने और वृद्धि एवं विकास में निवेश करने के प्रयासों में अफ्रीकी देश दो और चुनौतियों का सामना करते हैं: अवैध वित्तीय प्रवाह (IFFs) और बढ़ते ऋण संकट।

> अवैध वित्तीय (IFFs) प्रवाह

IFFs वह धन है जिसे अवैध तरीके से अर्जित, स्थानांतरित या कुछ व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से काम में लिया जाता है जैसे कि अवैध शैल कंपनियों के माध्यम से कंपनी के वास्तविक मालिकों को छिपाना; अवैध शिकार, ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी, तेल एवं खनिज की चोरी जैसी संगठित आपराधिक गतिविधियाँ और भ्रष्ट आचरण जो इन बहिर्वाह को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमीर बहुराष्ट्रीय निगम, टैक्स हेवेन्स, और व्यक्ति दुनिया के निर्धनतम देशों से अधिकांश IFFs के लिए उत्तरदायी हैं। कुछ क्षेत्रों में IFFs की उच्च सांद्रता है, विशेष रूप से खनिज उद्योग जिनकी प्रकृति अमीर विकसित देशों और अफ्रीका के व्यापार भागीदारों में जाने की है। पिछले दो दशकों पर दृष्टि डालते हुए, अन्य के मध्य, लुआंडा लीक्स, मॉरीशस लीक्स, लक्स लीक्स, स्विस लीक्स, द पनामा पेपर्स और पैराडाइस पेपर्स ने IFFs के मुद्दे को उजागर किया है और उनसे निपटने के सार्वजनिक और राजनैतिक चिंताओं को उठाया है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन (UNCTAD) से उपलब्ध सूचना दिखाती है कि IFFs के माध्यम से अफ्रीका अनुमानित $88.6 बिलियन– उसके एक वर्ष के घरेलू सकल उत्पाद के 3.7% के बराबर का नुकसान हो रहा है। ये बहिर्वाह अफ्रीकी देशों द्वारा प्राप्त आधिकारिक विकास सहायता और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लगभग बराबर ही है। यदि IFFs के माध्यम से खोये धन को महाद्वीप के विकास में लगाने में सक्षम हों तो यह बिना विदेशी सहायता के अफ्रीका को चलाने की क्षमता को दर्शाता है।

यह वो धन है जो एक ऐसे महाद्वीप पर खो रहा है जो पहले से ही राजस्व की कमी से पीड़ित है। इसलिए IFFs ''एक पीड़ित–विहीन अपराध'' नहीं है– यह व्यक्तियों एवं समाज के लिए हानिकारक है। इसका उल्लेखनीय विकासात्मक प्रभाव भी है चूँकि यह अफ्रीका में सामाजिक आर्थिक असमानता की डिग्री को बढ़ाने में मुख्य भूमिका

>>

" अवैध वित्तीय प्रवाह 'पीड़ित-विहीन अपराध' नहीं हैं, वे व्यक्तियों और समाज के लिए हानिकारक हैं।"

निभाता है और स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचे और अन्य सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं से आवश्यक धन को खींचता है।

> बढ़ता कर्ज

अफ्रीका दोनों सार्वजनिक और निजी लेनदारों से उधार लेने के कारण बढ़ती समस्याओं से उत्पन्न एक आसन्न वित्तीय संकट का सामना भी कर रहा है। कोविड–19 के साथ, कुछ अफ्रीकी देशों ने महामारी के विनाशकारी स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए ऋण रद्द करने और ऋण राहत के लिए मांग की है।

हालाँकि, उदाहरण के लिए, एक भू–आबद्ध, संसाधन समृद्ध देश जाम्बिया, जिसने निम्न मध्यम–आय प्रस्थिति 2011 में ही हासिल की थी, के लिए बढ़ता हुए बाहरी ऋण बोझ और इसके ऋण चुकौती में हालिया चूक के लिए कुछ नागरिकों ने राजनैतिक अभिजनों द्वारा कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और खराब नीतिगत प्रतिक्रियों को दोषी ठहराया है जो केवल निर्धनता और असमानता दर को बढ़ावा देने की तरफ जाती है। 2020 में, जाम्बिया अपने $42.5 मिलियन के यूरोबॉन्ड ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करने वाला प्रथम अफ्रीकी राष्ट्र बन गया। जाम्बिया ने चीन जैसी सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों और ऋण और बॉन्ड सहित बाहरी निजी लेनदारों को अपने बाहरी ऋण भुगतान को बनाये रखने के लिए संघर्ष किया है। कोविड–19 ने, अन्य बातों के मध्य, स्वास्थ्य प्रणाली पर अत्यधिक दबाव डाल कर मानवीय और आर्थिक संकट को बढ़ा दिया है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे खनन, कृषि और पर्यटन पर महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसने नौकरियों की हानि और उच्च बेरोजगारी दरों को अग्रेषित किया है। सामाजिक सुरक्षा जाल में अधिक निवेश को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करने वाली राजकोषीय स्पेस ऋण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिए गए अनेक कर प्रोत्साहनों के कारण सीमित है।

> निर्धन समर्थक नीतियों की आवश्यकता

कराधान और निर्धन समर्थक राष्ट्रीय कर नीतियों के माध्यम से डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन (DRM) कई अफ्रीकी समाजों और विश्व स्तर पर आर्थिक असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उदाहरण के लिए, कराधान राजस्व को बढाकर और समानता को प्रभावित कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो फिर शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी अत्यावश्यक सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए खर्च किया जाता है। प्रगितशील करों का उपयोग आय, धन के पुनर्वितरण और सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए एक साधन के रूप में काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सकता है। कर एक शक्तिशाली सामाजिक साधन हों सकता है जो स्वास्थ्य परिणामों, लैंगिक समानता और पर्यावरण के लिए निहितार्थ के साथ विकल्पों और व्यवहार के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रतिनिधित्व एवं जवाबदेही के लिए भी कर एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं के निधीयन के लिए बेहतर कर आवंटन लागू करने से विशेष रूप से निर्धनों को लाभ हों सकता है।

यह स्पष्ट है कि विकास उदेश्यों की प्राप्ति के लिए कर एक आवश्यक संसाधन हैं और यह अफ्रीका और वैश्विक स्तर पर असमानता में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कर की भूमिका को एक पक्षीय नहीं समझाना चाहिए; यह महामारी के प्रत्युयत्तर और स्वास्थ्य लाभ/बहाली के लिए फंडिंग से कहीं अधिक न्यायसंगत और समतामूलक समाजों के निर्माण की ओर ले जाती है। ■

सभी पत्राचार लकीस्टार मियानदाजी को <AzreeStar@gmail.com> पर प्रेषित।

> भारत में जुड़वां आपदाएं
एक अधूरा एजेंडा

ई. वेंकट रमनय्या और **विहा इमांदी**, यूथ फॉर एक्शन, भारत द्वारा

पर्यावरणीय आपदाओं के परिणाम मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो पहले से ही महामारी से असमान रूप से पीड़ित हैं। उदाहरण के लिए, भारत के हैदराबाद में कोरोनावायरस रोगियों के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल में 2020 में भारी बारिश के कारण पानी भर गया था। साभार: Twitter@UttamTPCC.

यदि और जब महामारी समाप्त होगी, तो जीवन सामान्य से बहुत दूर होगा। मानव, आजीविका और संपत्ति का नुकसान बहुत बड़ा होगा जैसा कि भारत में साबित हो चुका है जब लोगों को कोविड–19 और बाढ़ की दोहरी आपदाओं का सामना करना पड़ा। 2020 में, कोविड–19 के बीच, भारत को प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जब भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और चक्रवात आए, जिसके परिणामस्वरूप आजीविका का नुकसान, फसल का नुकसान और मानव जीवन का नुकसान हुआ। इसने उन लाखों प्रवासियों पर प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया जो कोविड–19 के मद्देनजर अपने गाँव वापस लौटे थे और खुद को संभाल नहीं पाए। सरकार और नागरिक समाज संगठनों द्वारा राहत कार्य इस तरह की भीषण जुड़वां आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। प्रकृति ने आखिरकार हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। कोविड–19 निस्संदेह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने का आह्वान करती है। लेकिन, मौलिक रूप से, महामारी पारिस्थितिक असमानता को दर्शाती है। इस के प्रमाण एकत्रित हो गए हैं कि जैव विविधता के नुकसान और प्राकृतिक दुनिया में लगातार बढ़ती मानव घुसपैठ ने कोविड–19 जैसी महामारी रोगों के प्रकोप और प्रसार में भारी योगदान दिया है। भविष्य की संभावित महामारियों की पहचान करने के लिए पारिस्थितिकी को समझना और पर्यावरण परिवर्तन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होगा। कोविड–19 कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण को आधार बनाने वाले जैव विज्ञान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को भी पुष्ट करता है।

> महामारी लश्चकडाउन और उल्टा प्रवास

भारत में, प्रवासियों और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कमजोर समुदायों को कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ा। यह ज्ञात है कि अधिकांश महिलाएं अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैंय जब उल्टा प्रवास हुआ, तो तालाबंदी के कारण शहरों से लौटने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने गांव में कोई रोजगार नहीं मिला। इसने महिलाओं के अवसाद, निराशा और आर्थिक अनिश्चितता में योगदान दिया। इसी अवधि के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों में 100% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि महिलाओं को सामाजिक संस्थाओं से कोई सामाजिक सहायता नहीं मिल सकी। स्मार्ट फोन तक सीमित पहुंच और औपचारिक समर्थन की अनुपलब्धता के कारण अपने जन्म के परिवार के साथ सीमित संपर्क ने महिलाओं में चिंता और आत्मघाती व्यवहार को बढ़ाने में योगदान दिया। बड़ी संख्या में किशोर लड़कियों और युवतियों ने शारीरिक और मानसिक शोषण से सुरक्षा के लिए बाल हेल्पलाइन सहायता केंद्र 1098 पर कॉल किया। स्वास्थ्य देखभाल संस्थान कोविड–19 के अलावा अन्य समस्याओं का समाधान नहीं कर सके और गरीब महिलाओं को अपने स्वयं के साधनों पर निर्भर रहना पड़ा, और उन्होंने कोविड के उपचार और प्रसव दोनों पर बड़ी रकम खर्च की। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण व्याप्त था क्योंकि सरकारी राहत पर्याप्त नहीं थी और स्कूल बंद होने का मतलब था कि बच्चों को स्कूल मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) नहीं मिला। परिवारों की आंशिक भुखमरी

>>

दिखाई दे रही थी, रोजगार की अनुपस्थिति के कारण उनकी जीवित रहने के लिए उनकी अल्प बचत में कमी हुई ।

> बाढ़

हैदराबाद शहर जैसे शहरी इलाकों में भी, झुग्गियों और छोटी बस्तियों में कमजोर आबादी को अपने घरों को छोड़ना पड़ा क्योंकि बाढ़ का पानी उनमें प्रवेश कर गया था। इनमें से कई गरीब समुदायों ने अपना रोजगार और घरेलू सामान खो दिया है, और उन्हें अस्थायी रूप से नए स्थानों पर स्थानांतरित होना पड़ा और एक भयानक मात्रा में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक तनाव से गुजरना पड़ा है। बाढ़ दोषपूर्ण नियोजन का परिणाम है। जल निकासी नहरों और पानी की टंकियों पर निर्माण को बढ़ावा देने से शहरी पर्यावरण की वहन क्षमता और कम हो गई है। इसके अलावा, 2014 के बाद से भारत में आए चक्रवातों और बाढ़ों की श्रृंखला न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में मानवजनित उत्सर्जन के साथ–साथ देश में अनियोजित विकासात्मक गतिविधियों का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर, अगस्त 2014 में बिहार के पूर्वी राज्य में कोसी नदी की भारी बाढ़ नेपाल में भारी वर्षा का परिणाम थी, जहां से नदी का उद्‌गम होता है और वहां 28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। कोसी के तटबंधों में बाढ़ के परिणामस्वरूप लगभग 2,25,000 लोग प्रभावित हुए, जिन्होंने जान, फसल, पशुधन और संपत्ति खो दी।

> सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए

नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन की स्थिति के प्रति जागने का समय आ गया है और उन्हें सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी और पर्यावरण की बहाली की दिशा में काम करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका इस पर नई प्रतिबद्ध ता जताएगा। नवंबर 2020 में पंद्रहवें जी–20 शिखर सम्मेलन में, भारतीय प्रधान मंत्री ने कोविड–पश्चात की दुनिया के लिए एक नए वैश्विक सूचकांक का आह्‌वान किया, जिसमें ''धरती माता'' की ट्रस्टीशिप की भावना के साथ प्रकृति का सम्मान करने पर जोर दिया जाएगा। एक दूसरा अव्यव एक विशाल प्रतिभा पूल का निर्माण होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रौद्योगिकी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और अधिक महत्वपूर्ण रूप से ''शासन में पारदर्शिता'' हो। 18 देशों और चार अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्यों के साथ कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन की स्थापना से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर पहले से अधिक ध्यान जायेगा जो आपदाओं से असमान रूप से प्रभावित गरीब देशों में जीवन और आजीविका बचाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा।

वैश्विक नीतियों में समय लग सकता है, लेकिन भारत में आगे का रास्ता यह होना चाहिए कि ''गरीबी रेखा'' की अवधारणा को पुनःपरिभाषित किया जाए और ''सशक्तिकरण सूचकांक'' प्राप्त करने की दिशा में काम किया जाए। सशक्तिकरण सूचकांक में आठ बुनियादी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति निहित होगीः स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, आवास, बुनियादी पोषण, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल और सामाजिक सुरक्षा। इन बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र को सरकार का समर्थन करना चाहिएय वैक्सीन विकास के लिए अनुबंध जीतने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय, कंपनियों को गुणात्मक परिणाम उत्पन्न करने के लिए सतत विकास की दिशा में काम करना चाहिए ताकि वैक्सीन तक पहुंच कमजोर आबादी का ''पहला अधिकार'' हो सके। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, टीकों तक पहुंच और कोविड–19 और जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए गतिविधियों को अपनाने और शमन गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। भारत सरकार को कोविड–19 स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने स्वास्थ्य बजट को वर्तमान 1% से बढ़ाकर जीडीपी के कम से कम 5% करना चाहिए। जिन स्वयं सहायता समूहों के साथ हमारा संगठन काम करता है उसकी महिला सदस्यों के शब्दों में, सरकार को उन्हें ''रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान, बुनियादी जरूरतों तक बेहतर पहुँच, और उनकी तात्कालिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकस्मिक उपायों की शुरुआत'' प्रदान करनी चाहिए।■

सभी पत्राचार ई. वेंकट रामनय्या को <vedvon@yahoo.co.in> पर और विहा इमांदी को <viha.emandi@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> सामाजिक नवीनीकरण की कुंजी के रूप में आधारभूत अर्थव्यवस्था

जूली फ्राउड, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचैस्टर, यूके, फांउडेशनल इकॉनामी कलेक्टिव के लिये, द्वारा

अक्सर कोरोना संकट के दौरान तथाकथित "अति–आवश्यक कामगारों" के प्रति आभार व्यक्त किया गया था, जबकि यह स्पष्ट है कि उनमें से अधिकांश को खराब तरह से भुगतान किया जाता है और वे अनिश्चित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ कोविड–19 से नए कार्य–संबंधी जोखिमों के संपर्क में हैं। साभारः फ्लिकर / क्रिएटिव कॉमन्स।

वर्तमान महामारी आधारभूत अर्थव्यवस्था के महत्ता की एक तीव्र याद दिलाती है – दैनिक आधार पर उपभोग की जाने वाली वे वस्तुऐं और सेवायें जो एक सुरक्षित और सभ्य जीवन को संभव बनाती हैं। इनमें पाइप और केबल नेटवर्ककी आधारभूत संरचनायें जो उपयोगिताओं, संचार, परिवहन, और खाद्य आपूर्ति के साथ ही स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और आय सहायता जैसी आवश्यक[1] सेवायें भी प्रदान करती हैं।[2] सेवाओं और श्रमिकों जों उन्हें प्रदान करते हैं, दोनों को कम आंकते हुये, यहां इनका महत्व नहीं समझने की एक प्रवृति है जब तक एक गंभीर व्यवधान, असुविधा या बड़े खतरे को पैदा नहीं होता। कोविड–19 के दौरान, कई नागरिकों ने महसूस किया कि खाद्य वितरण व्यवस्था अनिश्चित हैं जैसे कि बिजली आपूर्ति में रूकावट या सूखा हमें अनवरत बिजली और जल पर हमारी निर्भरता की याद दिलाता है। महामारी ने हमें "प्रमुख श्रमिक" और "अति–आवश्यक श्रमिक" जैसे शब्द दिये हैं ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तियों ने संकट के समय में दैनिक आधारभूत संरचनाओं को बनाये रखने के लिये "काम पर जाना" जारी रखा। उसी समय, यह स्पष्ट है कि कई ऐसे अति–आवश्यक श्रमिकों में से कइयों को न्यून भुगतान किया जाता है और वे अनिश्चित परिस्थितियों में कार्य करते हैं, उसके साथ वे कोविड–19 के नये कार्य–संबंधित जोखिमों के संपर्क में भी आये।

आधारभूत अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रकृति के इस सामयिक याद दिलाने वाले के परे, संकट सामूहिक संगठन, प्रावधानों और कुछ मामलों में उपभोग की महत्ता को रेखांकित करता है। उच्च आय वाले लोग अभी भी परिवहन व्यवस्था की गुणवत्ता या अस्पतालों में गहन देखभाल पर निर्भर हैं; एक उच्च निजी आय ना एक अच्छे वाई–फाई सिग्नल की और ना ही स्वच्छ हवा और अच्छी गुणवत्ता के सार्वजनिक उद्यानों की गारंटी दे सकती है। इसी तरह, एक महामारी में हमारी व्यैक्तिक सुरक्षा दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और विस्तार पर निर्भर करती है। यह सब आर्थिक प्रगतिके मानक परिमाणों की सीमाओं की पुष्टि करता है (जैसे कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद), जो विभिन्न प्रकार के मूल्यों की श्रृंखला को व्यक्त करने में विफल है जो एक अच्छे जीवन के लिये योगदान देती हैं, और अक्सर पर्याप्त रूप से उन्हें पुरस्कृत नहीं करते जो अति आवश्यक कार्य करते हैं।

> प्रावधानों और आधारभूत सरंचनाओं का नवीनीकरण

इन भौतिक और अवसरानुकूल सेवाओं की महत्ता को पहचानने के लिये वर्तमान क्षणों के द्वारा प्रदत्त अवसरों के बारे में स्पष्ट सोच की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, यहां आधारभूत अर्थव्यवस्था पर नीति और राजनीतिक ध्यान के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की पीढीयों की बेहतर सेहत को सुरक्षित करने की दोहरी चुनौती है। आधारभूत सेवा प्रावधानों की कमियां कई देशों में कोविड–19

>>

के आने से पहले ही अल्पनिवेश, निजिकरण, बाजारीकरण, और वित्तियकरण के विविध संयोजनों के माध्यम से उजागर हो गयी थी। बुनियादी ढांचा जो कि एकदम चरमरा गया है, बूढे होते समाजों में अल्प–वित्तपोषित देखभाल, "खाद्य रेगिस्तान" जहां नागरिक आसानी से अच्छी गुणवत्ता वाले ताजे भोजन तक नहीं पहुंच सकते हैं: ये सभी आधारभूत प्रावधानों की विफलताओं के उदाहरण हैं, जहां सुधार नागरिकों की खुशहाली को बढायेंगें।

कई मामलों में, वर्तमान पीढीयों की सेहत के लिये आधारभूत नवीनीकरण के लिये पूंजी और राजस्व अनुदान दोनों के लिये अतिरिक्त वित्तिय संसाधनों की आवश्यकता होती है। यहां तक कि जर्मनी जैसे उच्च आय वाले देशों में भी, परिवहन और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में गिरावट गहन वाद–विवाद का विषय रही है। हालांकि, अपने आप में निवेश उन समस्याओं का समाधान नहीं करेगा जो इसका परिणाम भी है कि ये सेवायें कैसे संगठित और प्रदान की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि नवीनीकरण को अक्सर खराब व्यापार मॉडलों में सुधार को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये, एक अल्प–वित्तपोषित देखभाल व्यवस्था को वृद्ध तथा कमजोर लोगों के बढते समूह की स्वास्थ्य और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक संसाधनों की जरूरत होती है। हालांकि, यदि देखभाल प्रदाता निजी इक्विटी या अन्य प्राप्ति मालिकाना रूपों के स्वामित्व में हैं, तो अतिरिक्त संसाधन उच्च लाभ की ओर निर्देशित किये जा सकते हैं, ना कि अधिक लोगों को काम पर रखने या देखभाल को बेहतर बनाने की ओर। या, अगर देखभाल प्राप्तकर्ताओं से बहुत कम निवेश के साथ, देखभाल बडे नौकरशाहों द्वारा आयोजित है तब प्रावधानों को स्थानीय बनाने और हितधारकों को अधिक आवाज देने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को सुधारों के साथ संयोजित किया जाना चाहिये।

बुनियादी ढांचे और सेवाओं के पुनर्निर्माण के माध्यम से नागरिकों के लिये सेवाओं में सुधार करते हुये, आधारभूत नवीनीकरण की राजनीतिक चुनौती में, भविष्य की पीढीयों की भलाई के लिये जलवायु और प्रकृति के संकट को संबोधित करना भी सम्मिलित है।[3] उदाहरण के लिये, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवास, परिवहन और भोजन जैसी आधारभूत अर्थव्यवस्था की गतिविधियों से महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता होगी।[4] चूँकि ये सभी अति–आवश्यक हैं, उत्सर्जन में कटौती ना सिर्फ परहेज से बल्कि नये नियमों और व्यवहारिक परिवर्तनों के द्वारा प्रोत्साहित उत्पादन और खपत में बदलाव से परिणित होगी। इसमें विभिन्न निर्माण तकनीकें और मौजूदा इमारतों को अधिक ऊर्जा–कुशल बनाने के लिये उनमें नये साजो–सामान लगाना, उपभोग किये जा रहे भोजन की संरचना में परिवर्तनों, और निजी वाहनों के स्थान पर सक्रिय यात्रा और सार्वजनिक परिवहन को प्रतिस्थापित करना शामिल है।

> राज्य के लिये एक स्पष्ट भूमिका

इन नवीनीकरण प्रक्रियाओं में राज्य के लिये एक स्पष्ट भूमिका है। यह केवल ऐसा मामला नहीं है कि राज्य द्वारा कुछ हद तक कई आधारभूत सेवायें प्रदान और/या वित्तपोषित होती हैं, परंतु दैनिक जीवन में इन आधारभूत संरचनाओं की पहुंच के माध्यम से सक्षम होने वाली सामाजिक नागरिकता को एक ऐसे राज्य की जरूरत होती है जो जवाबदेह और उत्तरदायी हो। पानी और सीवर व्यवस्था, बिजली ग्रिड, या सार्वजनिक अस्पतालों जैसे कई मूल बुनियादी ढांचे एक शीर्ष–पाद आधार पर बनायी योजना और इंजिनियरिंग के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं। नये बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और प्रावधान को नागरिक भागीदारी के लिये एक अधिक मजबूत भूमिका प्रदान करने की भी आवश्यकता है, विशेषकर जहां अदला–बदली हैं (जैसे कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना या बजट के अंतर्गत काम करना) या जहां समुदायों और स्थानीय–आधारित संगठनों में विशेषज्ञता पहले से ही समझती हैं कि जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में कैसे सामाजिक परिणामों मे सुधार किया जा सकता है ।

आधारभूत अर्थव्यवस्था का नवीनीकरण सार्वभौमिक मूल आय और सार्वभौमिक मूल सेवाओं को बढावा देने वाली अन्य नीतियों के लिये एक महत्वपूर्ण पूर्व–शर्त है। नागरिकों को केवल नकद देने से उनकी सेहत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता सामूहिक रूप से प्रदान की गयी सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, ब्रॉडबैंड, सामाजिक आवास, एकीकृत तथा किफायती सार्वजनिक परिवहन, और हरित स्थान, तक पहंच पर निर्भर करती है। यदि महामारी से एक सार्थक विरासत प्राप्त करनी है तो इसमें आधारभूत अर्थव्यवस्था का नवीनीकरण सम्मिलित होना चाहिये, जो सामाजिक और पारिस्थितिकीय रूप से सतत तरीके से वर्तमान जीवन क्षमता को बढाता है। ■

सभी पत्राचार जूली फ्राउड <julie.froud@manchester.ac.uk> को प्रेषित करें।

1. प्रावधानों शब्द का प्रयोग यहां प्रावधान, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। यह शब्द प्रावधानिक समाजों को प्रतिध्वनित करता है, जो लोगों को भविष्य में बीमारी आदि का भुगतान करने के लिये बचत करने की अनुमति देने के लिये स्थापित किये गये थे। यह शब्द सार्वजनिक और कल्याणकारी सेवाओं को शामिल करता है।

2. अधिक जानकारी के लिये, देखें: https://foundationaleconomy.com/introduction/.

3. अधिक जानकारी के लिये, देखें: https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2021/01/fe-wp8-meeting-social-needs-on-a-damaged-planet.pdf.

4. उदाहरण के लिये, स्टॉकहोम संस्था का अनुमान है कि वेल्स में पारिस्थितिकीय पदचिन्ह के 59% के लिये खाद्य खपत (28%), आवास (20%) और परिवहन (11%) को जिम्मेदार माना जा सकता है। https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/ecological-and-carbon-footprint-of-wales-report.pdf.

> भविष्य–अनुकूल अर्थव्यवस्थायें और राज्य

एंड्रियास नोवी और **रिचर्ड बार्नथेलर**, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकनोमिक्स एंड बिजनेस, ऑस्ट्रिया, द्वारा

यह कि हम वर्तमान में गहन उथल–पुथल के समय में जी रहे हैं, व्यापक रूप से स्वीकृत है। अब प्रश्न यह नहीं है कि *क्या* इक्कींसवीं सदी में गहन परिवर्तन होंगे, परंतु ये परिवर्तन *कैसे* घटित होंगें – एक अराजक तरीके से, जैसा कि हम वर्तमान में महामारी से निपटने में अनुभव कर रहे हैं, या जिसे सामूहिक रूप से आकार दिया गया है। बाद वाले दो पूर्वापेक्षाओं पर निर्भर करता है: अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पुनर्विचार, और सार्वजनिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़िकरण।

> बींसवी सदी के आर्थिक विचारों की सीमायें

पिछले दशकों में, बाजार उदारवादी विचार, जो कि उन्नीसवीं सदी में पहले से ही प्रभावशाली था, ने एक पुनर्जागरण का अनुभव किया है। नवउदारवाद के रूप में अक्सर आलोचित, यह दक्षिणपंथी नीति–निर्माण के परे राजनीतिक सोच और कार्य में समा गया है। दक्षता(इको–) को बढाने और दुर्लभ संसाधनों के आवंटन को सुधारने में बाजार की ताकतें एक सिद्धांत बन गयीं हैं, जो यूरोपीय संघ और अमेरिका में मुख्यधारा को अनुशासित करती हैं। बाजारों को सुधारना, हालांकि, हमें ग्रह की सीमाओं के अंदर रखने के लिये पर्याप्त नहीं होगा– न केवल इसलिये कि हरित विकास (जो, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय दवाबों के बीच पूर्ण विच्छेदन के अभाव में, वास्तव में बिल्कुल हरित नहीं है) बढती खपत से दक्षता लाभों की भरपाई करने का प्रयास करता है, बल्कि इसलिये भी क्योंकि बाजार उदारवाद प्रबल अवहनीय दिनचर्याओं, प्रथाओं और आदतों की उपेक्षा करता है। यह व्यैक्तिक बाजार चुनाव के माध्यम से जलवायु संकट को "हल" करने के लिये जानकार, तार्किक उपभोक्ताओं की ताकत पर लगभग धार्मिक विश्वास रखता है। बाजार समाधानों को दी गयी यह प्राथमिकता न केवल उपभोग की असमान पहुंच को प्रबलित करती है, बल्कि यह लोकतंत्र के लिये खतरा है। बाजार उदारवाद में, राज्य न तो कमजोर है ना ही अहस्तक्षेप तक सीमित है, परंतु अनुबंधों को लागू करने और निजी संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने के लिये मजबूत जनाधार रखता है। हालांकि, एक ऐसी दुनिया में, जहां संपत्ति अधिकार व्यावसायिक निगमों में संकेद्रित है, बाजार–उदार राज्य ने नयी, अलोकतांत्रिक, और अत्यधिक असमान शक्ति संरचनाओं को जन्म दिया है। बहुराष्ट्रीय निगम वैश्विक नियम और निर्णायक बन गये हैं, जो समाज और पर्यावरण पर लागत को बहीवर्ती करने में और इस बाह्यीकरण को निजीकृत शेयरधारक मूल्य में परिवर्तित करने में सक्षम है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण दोनों के विकासवादी राज्यों में, कल्याणकारी पूंजीवाद पर आधारित एक "युद्ध–पश्चात् की आम सहमति" पैदा हुयी। सार्वजनिक प्राधिकारियों के लिये बुनियादी प्रावधान करना एक मूलभूत कार्य माना जाता था: स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच से लेकर ऊर्जा, आवास और गतिशीलता के प्रावधानों के महत्वपूर्ण नगरपालिकाकरण या राष्ट्रीयकरण तक। उपकरणों का एक बडा खजाना – वृहद–आर्थिक हस्तक्षेप, बाजारों के दायरों की सीमाएँ, और पुनर्वितरण उपाय –बहुल आर्थिक संस्थाओं में परिणित हुए, जिन्होंने पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में समृद्धि के साथ–साथ वैश्विक दक्षिण में राष्ट्रीय विकास को सक्षम बनाया। जब बीसवीं सदी के अंत में, इस आर्थिक सहमति ने शैक्षिक और नीति–निर्माण में गंभीर झटके झेले, इसने 2008 के महान वित्तिय संकट के परिणामों में अपने प्रभाव को पुनः हासिल किया। कल्याणकारी पूंजीवाद का इक्कीसवीं सदी का संस्करण सामाजिक–पारिस्थितिकीय परिवर्तन के एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, पारिस्थितिकीय आधुनिकीकरण को बढावा देता है और नवाचार और औद्योगिक नीतियों में राज्य की एक अधिक सक्रिय भूमिका को स्वीकार करता है, परंतु इस बात की उपेक्षा करता है कि कैसे लाभ और वृद्धि अनिवार्यतायें और उपभोक्तावाद उन तरीकों की संरचना बनाते हैं जिसमें हम उत्पादन करते हैं और रहते हैं। नतीजतन, असमानता अधिक बनी रहती हैं और जलवायु तबाही बढ जाती है। इसके अलावा, स्थानीय रूप से संगठित "कल्याणकारी और नियामक राज्य" की प्रभावशीलता एक अधिकाधिक गैर.स्थानिकृत अर्थव्यवस्था के द्वारा कमजोर होती जाती है, जिससे बहुराष्ट्रीय निगम राष्ट्रीय कानून से बचने और धन इकठ्ठा करने के लिये समर्थ बन जाते है।

> एक उभरता हुआ ढांचा

बढते संकट को देखते हुये, आर्थिक विचार की एक प्रारंभिक तीसरी शाखा उभरी है। यह निम्नलिखित में अंतर करने के लिये मार्क्स, कीन्स, ब्रॉडल, नारीवादी अर्थशास्त्र, और फाउंडेशनल इकोनॉमी कलैक्टिव से अंतर्दृष्टि लेती है: (i) दैनिक गतिविधियों के आधारभूत आर्थिक क्षेत्र, जिसमें अस्तित्ववादी और स्थानीय प्रावधानों के साथ साथ अवैतनिक देखभाल कार्य सम्मिलित है; (ii) मूल्य–निर्माण करने वाली बाजार अर्थव्यवस्था, जिसमें गैर–आवश्यक स्थानीय प्रावधान और निर्यात–उन्मुख गतिविधियां सम्मिलित हैं; और (iii) मूल्य लेने वाली किरायेदार अर्थव्यवस्था। आजीविका को व्यवस्थित करने वाली एक प्रणाली के रूप में अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल पोल्यनी की समझ सामाजिक–पारिस्थितिकीय परिवर्तन की चुनौतियों को सामना करने के लिये सबसे उपयुक्त है। यह आधारभूत अर्थव्यवस्था (सर्वोच्च प्राथमिकता) के साथ साथ गैर–आवश्यक स्थानीय प्रावधानों (दूसरी प्राथमिकता) को विस्तार देने और मजबूत करने की आवश्यकता, निर्यात–उन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने, और किरायेदार अर्थव्यवस्था को सिकोड़ने पर प्रकाश डालती है।

यह स्वीकार करते हुये कि इस ग्रह की सीमाओं के भीतर सभी के लिये एक अच्छे जीवन को सिर्फ उत्पादन और जीवन के उत्तर–पूंजीवादी तरीकों की ओर परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण में लोकतांत्रित तरीकों से ये जरूरी परिवर्तनों को कैसे लाया जाये पर एक रणनीति का अभाव है। कुछ प्रस्तावक राज्य को अस्वीकार करने और जमीनी स्तर के आंदोलनों और नागरिक समाज की सक्रियता को विशेषाधिकार देने की ओर प्रवृत होते हैं, जिससे बाजार–उदार राज्यवाद–विरोधी और राजनीतिक भाग्यवाद मजबूत होते हैं और पिछले दशकों

>>

''भविष्य–अनुकूल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी रणनीतियों के लिए चुनिंदा आर्थिक वि–वैश्वीकरण के माध्यम से उलझे हुए, लेकिन उचित नीतिगत स्थानों की विविधता को सशक्त करके आत्मनिर्णय के परस्पर क्षेत्रीय रूपों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है''

की मुख्यधारायी उत्तर–राजनीतिक नीतिनिर्माण को सामान्य रूप से राज्य एजेंसी से मिलाते हैं। हालांकि, सत्तावादी सरकारों की एक श्रृंखला का उदय राज्य संस्थाओं की संभावित शक्ति को प्रदर्शित करता है। जबकि उनमें से कोई भी, चाहे वे समकालीन ब्राजील, भारत, या चीन में रोल मॉडल नहीं हैं, वे राज्य में निहित संभावनाओं को प्रादेशिक संप्रभुता वाली सीमावर्ती न्याय क्षेत्राधिकार इकाई के रूप में दिखाते हैं: वह चाहे नगरपालिका–राज्य हो, राष्ट्र–राज्य हो या यूरोपीय–राज्य। वैध नियम–निर्माण के ऊपर राज्य के एकाधिकारों में निहित क्षमता को अनदेखा करना न सिर्फ अनुभवहीन और खतरनाक है, बल्कि, सबसे अधिक, यह संभावित आधिपत्य–विरोधी परियोजनाओं की कीमत पर आला–खेलों में फंसी रहती है।

> गैर–पूंजीवादी राज्य संस्थाओं की आवश्यकता

एक भविष्य–अनुकूल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रभावशाली रणनीतियों के लिये आत्म–निर्णय के परस्पर जुड़े प्रादेशिक रूपों को आगे बढाने की जरूरत है। ऐसा चुनिंदा आर्थिक वि–वैश्वीकरण के माध्यम से उलझे उचित नीति स्थानों की विविधता – उदाहरण के लिये शहर, क्षेत्र, राष्ट्र, और आगे को आगे बढ़ा कर करते हैं। सार्वजनिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से एक क्षेत्र पर शासन करने वाले राज्यों को, न तो राष्ट्र–राज्य तक सीमित किया जाना चाहिये, और न ही केंद्रीय नौकरशाही तक। नवाचार करने वाले राज्य स्वरूपों को अधिक विकेंद्रीकृत होना होगा, जो मध्यस्थ संस्थानों के साथ–साथ काम करने और रहने की स्वप्रबंधित गैर–वस्तुकरण वाले क्षेत्रों को सशक्त और सुरक्षित करते हों। हालांकि, एक विवेकशील राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने पूंजीवाद में ऐसी प्रगतिशील राज्य एजेंसी की सीमाओं पर बल दिया है, और इस बात पर आग्रह किया है कि पूंजीवाद में राज्य एक पूंजीवादी राज्य है।

हम इस बात से सहमत हैं कि सार्वजनिक और लोकतांत्रिक राज्य संस्थायें केवल पूंजीवाद से परे आर्थिक व्यवस्था में ही फल–फूल सकती हैं। हालांकि, जैसे गैर–पूंजीवादी क्षेत्र हमेशा पूंजीवाद के अंदर ही मौजूद रहते हैं, गैर–पूंजीवादी राज्य संस्थायें भी पूंजीवाद के अंदर मौजूद रह सकती हैं: चाहे वह सहकारी समितियां हों, नगरपालिका कंपनियां हों, या सार्वजनिक पेंशन प्रणालियां। और चूँकि पूंजीवाद आधारभूत आर्थिक क्षेत्र (विशेषतः देखभाल और बुनियादी ढांचे) पर निर्भर रहता है, गैर–पूंजीवादी राज्य संस्थायें पूंजीवाद की वैधता और प्रभावशीलता को बनाये रखती हैं। क्योंकि पूंजीवाद अपने स्वयं के प्रतिवाद पर निर्भर करता है, राज्य एजेंसी आधारभूत आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत बना सकती है जो सभी निवासियों के लिए एक सभ्य जीवन को सक्षम बनाती है। किफायती सामूहिक प्रावधान प्रणालियों (देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, गतिशीलता) के लिये समावेशी पहुंच को अवहनीय विकल्पों (उदाहरण के लिये कम दूरी की उडानों पर प्रतिबंध) के अपवर्जन और सतत आर्थिक गतिविधियों (उदाहरण के लिये सब्सिडी, प्रत्यक्ष निवेश, कराधान व्यवस्था, सामाजिक लाइसेंस, पुर्नप्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से) में निवेश के संचालन के साथ जोडा जा सकता है, जो सामाजिक–पारिस्थितिकीय सार्वभौमिकता को सुनिश्चित करता है। अल्पावधि में, यह नवउदारवाद से आगे बढने की एक व्यवहार्य नीति है जो हरित, गैर–पूंजीवादी राज्य स्वरूपों को पूंजीवाद के अंदर मजबूत बनाती है।

हालांकि, दीर्घावधि में, उत्पादन का एक पूंजीवादी तरीका ग्रह की सीमाओं के भीतर एक अच्छे जीवन के साथ असंगत रहता है। इसलिये, पूंजीवाद के आगे जाने के लिये, राज्य के नये स्वरूपों को पूंजी के पुनरूत्पादन के लिये उनकी कार्यक्षमता के परे जीवन की गैर–वस्तुकरण किये गये क्षेत्रों के समृद्ध होने के आसपास विकसित होना चाहिये। यह परिवर्तित नागरिक समाज राज्य संबंधों का गठन कर सकता है जिसमें आधारभूत प्रावधानों में निवेश और उनका संचालन अधिक सामाजिक बन जाता है और श्रम बाजार आय पर निर्भरता घटती है। भलाई को बढावा देने से मजदूरी में वृद्धि के बजाय अधिक खाली समय होगा, निजी वस्तुओं को प्राप्त करने से अधिक सार्वजनिक वस्तुओं की पहुंच पसंद होगी, क्रय शक्ति बढाने से अधिक जीवन की लागत (उदाहरण के लिये किफायती सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आवास) कम करने को प्राथमिकता दी जायेगी। ■

सभी पत्राचार एंड्रियास नोवी को <Andreas.novy@wu.ac.at> और
रिचर्ड बार्नथेलर को <richard.baernthaler@wu.ac.at> पर प्रेषित करें।

> कोविड–19 :
राज्य और अर्थव्यवस्था के नये स्पष्टीकरण

बॉब जेसोप, लंकास्टर विश्विद्यालय, यूके द्वारा

कोविड–19 महामारी का महत्व अभी भी सामने आ रहा है। यदि खत्म नहीं तो, जब तक वायरस को नियंत्रित नहीं किया जाता, हमें यह पूर्ण तरीके से पता नहीं चलेगा कि कौनसे प्रत्युत्तरों ने अच्छे से काम किया। परंतु यह पहले से ही स्पष्ट है कि मामलों को नियंत्रित करने और किन्हीं भी कारणों से बढती मौतों को कम करने में कुछ देश अधिक सफल रहें हैं। यह भी स्पष्ट है कि महामारी ने पारस्परिक सहायता के साथ–साथ निजी व्यवसायों के समर्थन की ओर उन्मुख राज्य के हस्तक्षेप का नया तर्क पैदा किया है। यह आलेख महामारी के इस पहलू को संबोधित करता है।

महामारी को एक वैश्विक संकट के रूप में देखा जा सकता है। संकट दुनिया के स्वीकृत विचारों और इसमें कैसे "चलना" है को अस्तव्यस्त कर देता है, और सैद्धांतिक और नीतिगत प्रतिमानों के साथ–साथ दैनिक दिनचर्या पर प्रश्न उठाता है। यद्यपि महामारियों को लंबे समय से एक संभावित खतरे के रूप में देखा जाता रहा है, कोविड–19 महामारी को प्रारम्भ में काफी हद तक एक बहिर्जातीय, आकस्मिक झटके की तरह समझा गया जो मानव जाति के लिये खतरनाक है। यह आबादी की सुरक्षा के लिये सुरक्षा के जैव–राजनीतिक संभाषणों में और आंतरिक खतरों (जैसे प्रवासी श्रमिकों, रोमा जनसंख्या) के खिलाफ निर्देशित उग्रवादी संभाषणों में परिलक्षित होता है। इसके विपरीत, महामारी संकट को पूंजीवादी कृषि के प्राकृतिक दुनिया में घुसपैठ करने और जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के फैलाने की परिस्थितियां पैदा करने से लगाया जा सकता है। कोविड–19 का प्रसार वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, जिसने देशों और महाद्वीपों मेंजाना आसान कर दिया है, को भी दर्शाता है। महामारी की घटना फिर भी असमान है: जैव–राजनीतिक सुरक्षा, आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा, या धन से अधिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुये विभिन्न राजनीतिक शासन इसका अलग तरह से अर्थ लगाते हैं।

> यूके की कमजोर प्रतिक्रिया की व्याख्या

यह आलेख यूरोप और उत्तरी अमेरिका पर केंद्रित है, जहां खराब प्रदर्शन राजनीति को अधिक प्रत्यक्ष और स्थायी रूप से "वैश्वीकरण" की "अनिवार्यताओं" के प्रति अधीन करने की रणनीति से उपजा हो सकता है जैसा कि नवउदारवादी संभाषणों में निर्मित किया गया है। यह रणनीति समाज में धन की बढती असमानता और वर्गों के मध्य अधिक स्तरीकरण के साथ, दैनिक जीवन में वित्तियकरण को सुदृढ करने के लिये एक अनुशासनात्मक उपकरण के रूप में "अनिश्चितता" को बढावा देती हैं। यह कल्याणकारी राज्यों से साझा नागरिकता अधिकारों वाले कल्याणकारी राज्यों से एक बलपूर्वक कामकारी शासन और, विशेषकर यूएसए में, कारावास की संभावना की ओर परिवर्तन को गति भी देती है। नवउदारवाद बाजार ताकतों को विशेषाधिकार देता है और राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल उनके विस्तार के लिये करता है। इसके विपरीत, कोविड–19 राज्य को एक प्रमुख कारक की तरह, निजी–सार्वजनिक भागीदारियों, और बिना शर्त की एकजुटता (आपसी सहायता) को विशेषाधिकार देता है, और देखभाल करने वाले समाज को पुनर्जीवित करता है।

यूके एक ऐसा नवउदारवादी राजनीतिक शासन है जो सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के संगठनात्मक रूप से खंडित, विकेंद्रीकृत, और घटिया समन्वित इकाईयों के संदर्भ में महामारी के लिये खराब तरीके से तैयार था। एक नये प्रधानमंत्री के साथ जो अपनी जनमत रेटिंग की ओर उन्मुख थे के साथ ब्रेक्सिट को लागू करने की आवश्यकता के कारण सरकार का भी ध्यान बंटा हुआ था। इस प्रकार, ब्रिटिश स्वास्थ्य प्रणाली महामारी के लिये तैयार नहीं थी। 2009 से 2018 तक 1.2% की औसत वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च घटा दिया गया था, जो स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों में वृद्धि से मेल नहीं खाता था। यहां पर 40,000 नर्सों, 2,500 सामान्य चिकित्सकों, और 9,000 अस्पताल के चिकित्सकों की कमी के साथ–साथ गहन देखभाल उपकरणों की कमी है।

पिछली सरकारों ने एक महामारी रणनीति तैयार की थी जो एक तकनीकी खाका थी जो वेंटीलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों सहित स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति, और श्रमिकों और सीमांत समूहों की अनिश्चितता को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। अपनी 2011 की इन्फ्लुएंजा महामारी तत्परता रणनीति पर चिंतन करते हुये, ब्रिटिश सरकार की नीति ने "विज्ञान का अनुसरण" किया जैसा कि आपातकाल पर वैज्ञानिक सलाहकार समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया। विज्ञान इन्फ्लुएंजा महामारी के साथ एक भ्रामक सदृश्यता पर आधारित था, यह दर्शाते हुये कि वायरस 2,50,000 अतिरिक्त मौतों का कारण बन सकता है जिसे ट्रायेज (बुजुर्गों को मरने देकर, बीमारों को देखभाल केंद्रों में भेजकर) के माध्यम से नियंत्रित किया जायेगा। जब जनमत ने इसे खारिज कर दिया, तो सरकार ने वायरस के प्रसार को टालने के लिये बढते संक्रमणों के वक्र को समतल करने का प्रयास किया और कुछ विकेन्द्रीकरण के साथ राष्ट्रीय रणनीतियां थोप दी। इसके बाद लॉकडाउन के स्तरों को स्थापित किया, अक्सर बहुत कम और बहुत देरी से। वास्तव में, रुग्ण की छुटटी के निम्न स्तरों का अर्थ है कि आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति, अस्वस्थ होने पर भी, काम करना जारी रखता है। इसने संक्रमण की उच्च स्तरों और मृत्यु संख्या में योगदान दिया।

सरकार एक कार्यकारी परीक्षण–निशानदेही–पृथक्करण की व्यवस्था को स्थापित करने में विफल रही है और, निजी क्षेत्र के प्रति अपने जुनून के कारण, सरकार ने स्थानीय सेवाओं और राष्ट्रीय एजेंसीयों को एक सुसंगत प्रतिक्रिया देने के लिये नहीं जोडा।

>>

"महामारी ने पारस्परिक सहायता के साथ-साथ निजी व्यवसाय का समर्थन करने के लिए उन्मुख राज्य हस्तक्षेप के लिए एक नया तर्क दिया है।"

निर्दिष्ट देशों से लौटने वाले यात्रियों के अलावा, पृथक या क्वारेंटीन किये गये लोगों के लिए कोई व्यस्थित फोलोअप नहीं थे। यूके में समुदाय में कोरोना वायरस का परीक्षण अन्य जगहों (उदाहरण के लिये जर्मनी, आयरलैंड, और दक्षिण कोरिया) में दृष्टिगोचर अच्छे चिकित्सीय पर्यवेक्षण के बिना सामान्य एनएचएस संरचनाओं के बाहर प्रदान किया गया। हालांकि टीकाकरण नीति को स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से अच्छी तरह से संभाला गया है।

यूके ने कोविड–19 की प्रतिक्रिया में स्वास्थ्य के ऊपर धन को प्राथमिकता दी, जिसका उलटा असर हुआ। वास्तव में, अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में स्वास्थ्य की सुरक्षा करना भी बहुत प्रभावी है। यूएस, यूके, स्वीडन, और ब्राजील में सरकारों ने पहले कोविड–19 की घातक प्रवृति पर और जीवन की रक्षा करने पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। व्यवसायों (बड़े) को चलाये रखना अधिक मायने रखता था। इसके कारण लॉकडाउन और सामाजिक पृथक्करण के उपायों में देरी हुयी, फिर "हल्का" लॉकडाउन जो वायरस को दबा नहीं पाया; और फिर बहुत जल्दी छूट, जिसने महामारी को पुनर्जीवन तक ला दिया।

> मजबूत राज्य कार्यवाही की सफलता

जहाँ कोविड–19 एक वैश्विक महामारी है, तथापि, वैज्ञानिकों के विपरीत राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रियाओं के बीच बहुत कम समन्वय है। इसके बजाय, महामारी और टीकों के राष्ट्रवादी समाधान विकसित पूंजीवादी समाजों में प्रचलित है और वैश्विक टीकाकरण अभियान के समन्वय में बहुत कम प्रयास या धन खर्च किया गया। विशेष तौर पर यह वैश्विक उत्तर में स्पष्ट है, जिसने महामारियों के वैश्विक दक्षिण को प्रभावित करने की अपेक्षा की थी। फिर भी, चाहे कोई देश लोकतांत्रिक हो या सत्तावादी, एक द्वीप या महाद्वीपीय, कन्फ्यूशियस या बौद्ध, समुदायवादी या व्यक्तिवादी, यदि यह पूर्वी एशियाई, दक्षिणपूर्वी एशियाई, या ऑस्ट्रेलियन हो, इसने कोविड–19 का किसी भी यूरोपीय या उत्तरी अमेरिकी राज्य से बेहतर ढंग से प्रबंधन किया। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया में जहां मजबूत राज्य कार्यवाही और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों ने काम किया, जीरो–कोविड नीतियां उन समूह प्रतिरक्षा नीतियों से बेहतर हैं जो सहनीय मौतों, प्रतिरक्षा के उत्तरोतर निर्माण, और/या व्यापक टीकाकरण नीतियों पर निर्भर रहती हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोविड–19 के बाद की पूछताछ नवउदारवादी प्रतिक्रिया की आलोचना करेगी और प्रभावी राज्य कार्यवाई के मजबूत समर्थन के साथ पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य और देखभाल बुनियादी ढांचे में अच्छे निवेश की सिफारिश करेगी। ■

सभी पत्राचार बॉब जेसोप <b.jessop@lancaster.ac.uk> को प्रेषित करें।

> लेविआथन वापिस आ गया है!

कोरोना राज्य और समाजशास्त्र

क्लॉस डोरे और **वालिद इब्राहिम**, फ्रेडरिक–शिलर–यूनिवर्सिटाट जेना, जर्मनी द्वारा

एरफर्ट, जर्मनी में टीकाकरण केंद्र। "कोरोना राज्य" का देखभाल करने वाला पक्ष या आर्थिक सुधार के लिए एक आवश्यक उपाय? साभारः वालिद इब्राहिम।

लेविआथन वापिस आ गया है! कोरोना महामारी के कारण दुनिया के कुछ हिस्सों में वर्तमान में क्या हो रहा है को हम इस तरह संक्षेप में बता सकते हैं। अपनी महत्वपूर्ण कृति *लेविआथन ऑर द मैटर, फॉर्मे एंड पॉवर ऑफ ए कॉमनवेल्थ एक्लेसियस्टिकॉल एंड सिविल*, में थॉमस हॉब्स ने आधुनिक राज्य की विरोधाभासी प्रकृति को व्यक्त करने के लिये समुद्री राक्षस की सदृश्यता का चुनाव किया। नवउदारवाद के युग के दौरान, ऐसा लगा कि लेविआथन पीछे हट रहा है। यह वास्तव में कभी सच नहीं था, चिली में भी सिर्फ एक अत्याचारी राज्य ने शिकागो बॉयज के बाजार–कटटरपंथी प्रयोंगों को संभव बनाया। फिर भी, समाजशास्त्रीय सामाजिक समालोचना का अर्थ सभी बाजार समालोचना से ऊपर था। यह किसी भी तरह का संयोग नहीं था कि कार्ल पोलन्यी एक दोहरे आंदोलन के लिये अकादमिक मुख्य गवाह बन गये, जिसने शुरूआत में बाजारों के एक दूरगामी विघटन में योगदान दिया। कोरोना महामारी के बाद से, पेंडुलम वापिस लहराने लगा। लेविआथन हस्तक्षेप करता है – महामारी से लडने के उददेश्य से आपातकाल की एक स्थिति के रूप में और *उसी समय* एक आर्थिक हस्तक्षेप करने वाले राज्य के रूप में जो खरबों डॉलर उन देशों और क्षेत्रों में निवेश कर करते हैं जो इसे अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और अगर जरूरत हो तो, पुनर्निर्माण के लिये जुटा सकते है।

> कोरोना राज्य का आकलन

इस *राज्य* का आकलन कैसे किया जाता है? व्यवस्था सिद्धांतकार चिढ गये हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभावी रूप से प्रत्येक सामाजिक उपव्यवस्था में हस्तक्षेप करने वाले एक कर्ता राज्य की संभावना से इंकार कर दिया था। कीनेसियन अर्थशास्त्री खुश हैं क्योंकि सरकारी ऋण अब अर्थव्यवस्था को उददीप्त करने के विकल्प का साधन है। दूसरी ओर, उदारवादी पत्रकारों को मौलिक अधिकारों की चिंता है जिन्हें "कोरोना राज्य" द्वारा अनेक लॉकडाउन और बंद के दौरान निलंबित किया जायेगा। तो हमें इस नये राज्य हस्तक्षेपवाद का आकलन कैसे करना चाहिये? प्रारंभिक उत्तर के रूप में, हम इस थीसिस को आगे बढाते हैं कि राज्य हस्तक्षेपवाद "एक नये चेहरे के साथ पूंजीवाद" की धात्री बन सकता है। हालांकि, कोरोना राज्य एक संकर है, चूँकि यह महामारी और मंदी को से राज्य गतिविधि के दो मौलिक रूप से भिन्न प्रकारों से प्रतिक्रिया देता है जो एक दूसरे से बहुत हल्के से जुडे होते हैं। कोविड–19 को आपातकाल स्थिति के द्वारा संभाला जा रहा है जो एक ओर संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत काम करती है और दूसरी ओर मौलिक अधिकारों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर संविधान पर अधिरोहण करता है। अपवाद की स्थिति की एकमात्र वैद्यता महामारी

>>

के खिलाफ लडाई है। राज्य बीमारी के तेज प्रसार को रोकने के लिये सामाजिक दूरी के नियम की बाध्यता को लागू करता है। ऐसा करने में यह एक चिकित्सा आपदा को जवाब दे रहा है; फिर भी जैसे ही महामारी अधिक प्रबंधनीय हो जाएगी, यह अपनी वैद्यता खो देगा। वे सभी रूझान जिनका कुछ विश्लेषक अपवाद की वर्तमान स्थिति में स्वागत करते हैं–दैनिक जीवन का धीमा पडना, उपभोग का त्याग, यात्रा से परिवर्जन, अपनी और दूसरों की देखभाल के लिये समय निकालना– को महामारी के अंत के बाद सिर्फ स्वैच्छिक आधार पर बनाये रखा जा सकता है। कोविड–19 पूर्व की सामान्यता को बहाल करने की पहचानने योग्य आग्रह इस बात की ओर संकेत देता है कि ये विश्लेषण सच्चाई से कितने दूर हैं।

आर्थिक हस्तक्षेपवादी राज्य का भिन्न तरीके से आकलन किया जाना चाहिये। राजकोषीय मितव्ययता, संतुलित बजट, ''Schwarze Null''[1] से धीर–धीरे दूर होते हुये और – अब तक इसका केवल संकेत दिया गया– बडी संपत्ति और उच्च आय पर उच्चतर कराधान, पहले के बाजार कट्टरवाद की तुलना में प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, कोरोना राज्य एक सामाजिक–पारिस्थितिकीय परिवर्तन की गारंटी नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करते हैं। राजनीतिक–आर्थिक अर्थों में, यह नाजुक मोड़ पर है, क्योंकि अमीर देशों में भी, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण तब तक ही काम करता है जब तक केंद्रीय बैंक और वित्तिय बाजार साथ रहते हैं और कम ब्याज दरों की नीति की गारंटी देते हैं। यह इसे और अधिक गंभीर बनाता है कि जिम्मेदार राज्य तंत्र अक्सर आर्थिक और औद्योगिक नीति में कल्पना की कमी से चिन्हित होते हैं। विवेकपूर्ण हस्तक्षेपवाद से अलग हो कर, वे इस निवेश और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों से प्राप्त अप्रत्याशित लाभ के साथ क्या करना है के बारे में कम जानते हैं ।

> आर्थिक हस्तक्षेप की सीमायें

इस कारण से, भी, किसी को कोरोना राज्य के पारिस्थितिकीय सतत प्रभाव से ऊंची उम्मीदें नहीं रखनी चाहिये। हस्तक्षेपवादी आर्थिक राज्य का उद्देश्य आर्थिक गतिविधि के संकुचन का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकार करना है। ऋण–वित्तपोषित पुनर्निर्माण कार्यक्रमों की वैद्यता को विकास की सफलता से मापा जा सकता है। इस संबंध में, कोरोना राज्य एक द्वेधवृत्तिक इकाई है। आर्थिक हस्तक्षेपवादी राज्य का कार्य एक ऐसा सूप परोसना है जिसे इसके असमान जुडवा, महामारी आपातकाल की स्थिति, ने इसके लिये पकाया है। इस प्रक्रिया में, पारिस्थितिकीय सततता लक्ष्य पटरी से उतर जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन एक निष्पक्ष सबक प्रदान करता है। केवल पहली नजर में कोविड–19 पारिस्थितिकीय रूप से लाभदायक दिखाई देता है। 2007 की दुर्घटना की तरह, लॉकडाउन और आर्थिक संकट "आपदा से डीग्रोथ" का कारण बनते हैं। यह सच है कि प्रतिबंधित गतिशीलता और अस्थायी औद्योगिक पतन ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को उस हद तक कम कर दिया जो दशकों में नहीं देखा गया। परंतु अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार के साथ, उत्सर्जन अपेक्षा से अधिक तेजी से बढा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की गणनाओं ने 2020 के प्राम्भिक तीन महीनों में दुनियाभर के उत्सर्जन में 5.8% की गिरावट दर्ज की; जो कि पूरे यूरोपीय संघ के उत्सर्जन के बराबर है। परंतु अप्रेल 2020 के बाद से, वैश्विक उत्सर्जन फिर से बढ गया है; दिसंबर में, वे पहले ही पिछले साल के तुलनात्मक मासिक स्तर से ऊपर थे। 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग परिदृश्य जिसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अभी भी यथोचित नियंत्रित करने योग्य मानता है, को प्राप्त करने के लिये वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष औसतन 7.6% की गिरावट करनी होगी–परंतु ऐसा लगातार करना होगा और न कि अस्थायी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप। आईईए को डर है कि 2019 में दुनिया के चरम वैश्विक उत्सर्जन तक पहुंचने का ऐतिहासिक अवसर बर्बाद हो रहा है। कठिन वितरण–संबंधी संघर्ष, जिनका उच्च ऋण स्तरों और घटते कर राजस्व के परिणामस्वरूप, सभी समाजों को सामना करना पडता है, इस रूझान को और अधिक बढ़ा सकते हैं।

अंत में, किसी को ध्यान देना चाहिये कि यद्यपि हस्तक्षेपवादी राज्य एक लेविआथन है, इस राक्षस के लाभदायक प्रभाव हो सकते हैं। यह मानव जीवन को आर्थिक हितों के ऊपर रखते हुये अपनी राष्ट्रीय आबादी की रक्षा करता है। बेशक इसका दूसरा पहलू यह है कि यह महामारी के खिलाफ लडाई को यह साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता का उद्देश्य बना देता है। केवल वे राज्य जिनके पास पर्याप्त टीके हैं और वे अपने टीकाकरण अभियानों को तेजी से क्रियान्वित कर सकते हैं, उनके पास तीव्र आर्थिक सुधार का मौका होगा। इसके परिणामस्वरूप, एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरे का मुकाबला वैक्सीन राष्ट्रवाद के साथ किया जा रहा है। एकजुटता की सभी अभिव्यक्यिों के बावजूद, 2021 के वसंत तक, पूरे 10 देशों ने उपलब्ध टीकों का 76% हासिल कर लिया था। कम आय वाले 85 देशों को अपनी आबादी के लिये टीकाकरण शुरू करने में सालों लग सकते हैं। इससे म्यूटेशन का खतरा बढ जाता है जो टीकों से प्रतिरोधी साबित होते हैं। स्पष्ट है, पूंजीवादी–प्रभुत्व वाली राज्य व्यवस्थायें टीकों को सार्वजनिक वस्तु के रूप में मानने में असमर्थ हैं और इस तरह सभी के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा (एसडीजी 3) के सततता लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अतः अपने प्रमुख रूप में, कोरोना राज्य अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय सततता में प्रगति की गारंटी देने वालों के बजाय कुछ भी है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण और समालोचना के लिये, इसका अर्थ है कि हमें हमारी विषयवस्तु को फिर से परिभाषित करना चाहिये। राज्य को एक बार फिर से समाजशास्त्रीय विशेषज्ञता का केंद्र बनना चाहिये। इसका वास्तव में कि कोरोना राज्य क्या है और यह कैसे संचालित होता है, का वास्तव में आकलन करने के लिये हमें बडे, विश्व स्तर पर केंद्रित, अंतर–अनुशासनात्मक शोध कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय समुदाय के लिये इन कार्यों को शीघ्रता और निर्णायक रूप से निपटाने का समय आ गया है।■

सभी पत्राचार क्लॉउस डोरे को <klaus.doerre@uni-jena.de> और वालिद इब्राहिम को <walid.ibrahim@uni-jena.de> पर प्रेषित करें।

1. ''ब्लैक जीरो'' संतुलित बजट को इंगित करता है।

> कोविड–19 : जर्मनी में असुरक्षित स्थानों का निर्माण

डेनियल मुलीस, पीस रिसर्च इंस्टीटयूट फ्रेंकफर्ट (पीआरआईएफ), जर्मनी द्वारा

परित्यक्त उत्पादन हॉल। क्रेडिटः डैनियल मुलिस।

रोजमैरी क्लेयर कॉलार्ड तर्क देती हैं, निश्चित तौर पर "वे और जिनकी जिंदगियो का ध्यान रखा जाता है या जिन्हें सुरक्षित बनाया जाता है" वही जैव–राजनैतिक गणनाओं को परिभाषित करते हैं। फूको का अनुसरण करते हुए जैव–राजनीति जनसंख्या की सेहत से संबधित राजनीति है। यह "जीवन बनाने" और "मरने देने" की क्षमता है। मैथ्यू हनाह, जेन साइमन हट्टा, और क्रिस्टोफ शेमन तर्क देते हैं कि कोविड–19 के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया "जनसंख्या के 'पुर्नजैवीकरण' द्वारा जैव–राजनैतिक अर्थों में न्यायसंगत रही हैं, और अधिक से अधिक लोंगों को जीवित रखने के लिये एक कथित व्यापक अनिवार्यता है।" परंतु स्पष्ट रूप से कुछ जीवन दूसरों की तुलना में अधिक मायने रखते हैं। वैश्विक स्तर पर, विभिन्न जनसंख्या को दिया गया असमान सम्मान मौतों की संख्या के साथ साथ टीकों तक पहुंच के स्तर में स्पष्ट है। पूरे उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, कोविड–19 से संक्रमण का स्तर वर्ग, नस्ल, और लिंग के संदर्भ में हाशियाकरण के साथ बढ़ता है। महामारी का एक विशिष्ट भूगोल है जो समाज के उपेक्षित हिस्सों पर प्रकाश डालता है, ऐसे स्थान जिन्हें राज्य सुरक्षित बनाने के लिये इच्छुक नहीं है। मैं इस तर्क पर जर्मनी के विशेष संदर्भ में विस्तार से बताऊंगा।

> परिधीयकरण

समांथा बिगलिरी, लारेंजो दे विदोविच और रोजर कील तर्क देते हैं ''जहां वायरस संकेंद्रित होता है, आप शहर में, और समाज में परिधिय को पायेंगे। जनवरी 2011 के प्रारम्भ में रोजर कील परिधीयकरण के तीन संबंधित विन्यासों की पहचान करते हैं: *स्थानिक परिधीयकरण* में ऐसे स्थान सम्मिलित हैं जो समकालीन समाजों में केंद्रीय नहीं है; *संस्थागत परिधीयकरण* राज्य द्वारा चलाई जा रही प्रथाओं से उत्पन्न होता है जो समाज को ऐसे तरीकों से संगठित करती हैं जो लोगों को हाशिये पर धकेल देते हैं; और *सामाजिक परिधीयकरण* समाज के नस्लीय विभाजन को संबोधित करता है– एक परिप्रेक्ष्य जिसे मैं नस्ल के साथ वर्ग और लिंग के आयामों को जोडकर व्यापक बनाना चाहता हूं।

कोविड–19 की भौगोलिकताओं के बारे में, रॉबर्ट कॉच इंस्टीटयूट ने दिखाया है कि 2020/21 की सर्दियों में निम्न सामाजिक–आर्थिक अभाव वाले क्षेत्रों की तुलना में उच्च सामाजिक–आर्थिक अभाव वाले क्षेत्रों में मृत्यु दर 50 से 70 प्रतिशत अधिक थी। शहरी क्षेत्रों के आंकडें इंगित करते हैं कि महामारी उन जिलों को सबसे अधिक प्रभावित करती है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, लोगों की औसत आय कम है, और गरीबी दर अधिक है। राज्य (–गैर) हस्तक्षेप पर चर्चा करते समय, परिधीयकरण के तीनों विन्यासों में *संस्थागत परिधीयकरण* सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। अन्य दो, उदाहरण के लिये, गरीबी के उत्पादन के साथ साथ एक स्थानिक परिधी में स्पष्ट हो जाते हैं।

>>

पहले विन्यास के संबंध में, एजेंडा 2010 के रूप में इंगित किये जाने वाली जर्मन कल्याण प्रणाली के कार्यान्वन के माध्यम से गरीबी को अधिक प्रमुखता मिली है। अन्य बातों के साथ, एक अल्पवेतन क्षेत्र लागू किया गया था और बुनियादी सामाजिक सहायता को पुनर्गठित किया गया था। गरीबी स्वाभाविक रूप से विद्यमान नहीं होती हैः यह अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से पुनः/उत्पादित होती है, और इसे कानून और राज्य शक्ति द्वारा सहायता मिलती है। परिणाम स्पष्ट हैं। आंकडे दर्शाते हैं कि समाज के संपन्न वर्गों के लोंगों की तुलना में बुनियादी सामाजिक सहायता पर निर्भर लोग कोविड–19 से कहीं ज्यादा प्रभावित हुये हैं। रोजगार वाले लोंगों की तुलना में लगभग दुगुने दीर्घकालिक बेरोजगार अस्पताल में भर्ती हुये हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी वाले लोग ज्यादा भीडभाड वाले या तंग निवासों में रहते है, अक्सर सामाजिक आवास में परिधीयकृत; वे अनिश्चित परिस्थितियों में काम करते हैं; और वे डिजिटल आधारभूत ढांचे से कटे हुये होते हैं, जो उचित होमस्कूलिंग को असंभव बनाता है। ये सभी पहलू उच्च भेद्यता और एक बढते हुये सामाजिक विभाजन में परिणित होतें हैं। महामारी के दौरान कम अमीरों की आय कम हो गयी है, जबकि मध्यम वर्ग ने अपनी स्थिति को बनाये रखा है, और अमीर अधिक अमीर हो गये हैं।

चर्चित दूसरा विन्यास–स्थानिक परिधीयकरण का उत्पादन समाज के केंद्र से लागू एक राजनीतिक प्रकिया है। एक ओर, पूंजीवादी राज्यवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत राजनीतिक निर्णय केंद्रीयता और परिधि के परिदृश्य बनाते हैं। इसके उत्पादों में सामाजिक आवास, शरणार्थी शिविरों, बेघरों के लिये आश्रयों, और नर्सिंग होम्स में अपवर्जन के विन्यास के साथ अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियों के लिये सौपें गये काम भी सम्मिलित है। महामारी के दौरान ये सभी सामाजिक पृष्ठभूमि कोविड–19 का हॉटस्पाट बन गयी हैं। इसी समय, आवासीय इलाके और विशेष रूप से शहरी जिले राजनीतिक संभाषणों में खतरनाक स्थानों की तरह चित्रित किये जातें हैं, ताकि महामारी को मुख्यधारा समाज से अलग किया जा सके। यह रणनीति पहले से ही बस्तियों के बारे में संभाषणों से जानी जा चुकी है। पहले महामारी का स्थानिकरण किया जाता है, फिर स्थान के एक भाग को "प्रवासी", "गरीब", "अनियंत्रित" आदि का नाम दिया जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपने निवासियों के साथ, ये स्थान वास्तविक समस्या है।

> केंद्रीयता

यह स्पष्ट हो जाता है कि अ/सुरक्षित स्थानों को बनाना शक्तिशाली लोगों के द्वारा लागू की जाने वाली एक राजनीतिक प्रक्रिया है। फूको तर्क देतें हैं कि नवउदारीकरण के दौरान राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सरकारी निर्णयों के लिये परिभाषित तर्क बन जाती है। वेंडी ब्राउन आगे बताती हैं कि "राज्य का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुविधा प्रदान करना होता है, और राज्य की वैद्यता अर्थव्यवस्था के विकास से जुडी होती है।" कोविड–19 को रोकने के प्रति लक्षित जर्मन उपायों ने इस सिद्धांत की पालना की। उपलब्ध आंकडों के अनुसार, सकल मूल्य वर्धित का सिर्फ 12.8 प्रतिशत महामारी–संबंधी प्रतिबंधों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थाः इन प्रभावों को खुदरा व्यापार, आहार प्रबंध, शिक्षा, यात्रा तथा मनोरंजन उद्योग और संस्कृति में सबसे अधिक महसूस किया गया। अर्थव्यवस्था के बाकी 87.2 प्रतिशत ने कमोबेश बिना प्रभावित हुये काम करना जारी रखा। अनिश्चित श्रम शक्ति को संक्रमण से बचाने के लिये अर्थव्यवस्था को बंद करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया।

इसका अर्थ यह है कि परिधीय स्थानों में बड़े पैमाने पर प्रकोप भी केंद्रीयता की ओर इंगित करता है। बूचड़खानों, रसद केंद्रों और विद्यालयों में उच्च संक्रमण दर से यह प्रमाणित होता है। जर्मनी में मांस उद्योग एक महत्वपूर्ण निर्यात–उन्मुख क्षेत्र है, जिसके उत्पादन को रूकने की अनुमति नहीं दी गयी। रसद केंद्रों के मामले में, एग्निएज्का मोरज, पौलैंड की एक अमेजॅन कार्यकर्ता, ने यह बिंदु तीक्ष्णता से उठाया जब उसने कहा कि वह और उसकी साथी पीड़ित नहीं थे, परंतु वैश्विक पूंजीवाद के केंद्रिय हब में काम करते थे, जो कि वस्तुओं के अबाधित प्रवाह के लिये महत्वपूर्ण थे। विद्यालयों के मामले में, यह स्पष्ट है कि, बाल अधिकारों की बहुत बातें करने के बावजूद भी, महामारी के दौरान बच्चों को कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। विद्यालय मुख्य रूप से माता–पिता को श्रमशक्ति के लिये उपलब्ध कराने के लिए खोले गए, न कि शैक्षिक न्याय के लिये।

> राज्य के (गैर–)हस्तक्षेपवाद के विन्यास

कोविड–19 कई स्थानिक, संस्थागत, और सामाजिक परीधियों को चिन्हित करता है, और ये वे स्थान हैं जहां वायरस और सामाजिक परिणामों का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामाजिक–आर्थिक अभाव ने लोगों को जानलेवा जोखिमों और गरीबी से सामना कराया। राज्य के हस्तक्षेप के संबंध में, एकजुटता और न्याय पर आधारित स्वतंत्रता को रोकने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने की बजाय, सत्तावादी और सुरक्षा–उन्मुख रास्तों को उजागर करना बहुत महत्वपूर्ण है जिसे अधिकतर सरकारों ने वायरस का सामना करने के लिये चुना है। परंतु यहां ज्यादा सावधानी से विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है जहां राज्य ने कार्यवाई न करने का, और स्थानों को सुरक्षित नहीं बनाने का फैसला लिया। और जहां, इसके बजाय, उन लोगों की सुरक्षा करने के लिये जिनसे हाशियाकृत लोग अलग किये जाते हैं, राजनीतिक निर्णयों ने वर्ग, नस्ल, और लिंग की रेखाओं पर बाहयीकरण, अपवर्जनीकरण, और परिधियकरण के विन्यासों को गहरा कर दिया है। ■

सभी पत्राचार डेनियल मुलीस को <mullis@hsfk.de> पर प्रेषित करें।

> अवसाद के बाद : एक उत्तर–नवउदारवादी विषय

आर्थर ब्यूनो, फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय, जर्मनी एवं कनसेपचुअल एंड टर्मिनोलॉजिकल एनालिसिस (आरसी 35) पर आईएसए की शोध समिति के सदस्य द्वारा

इक्कीसवीं सदी का मोड़ मुख्य रूप से मंदी के संकेत के तहत हुआ, और इसने मुख्य रूप से थकावट, खालीपन और कार्य करने में असमर्थता की भावनाओं को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया। साभारः अनस्प्लाश पर एहिमेटलर अखेरे उनुआबोना।

हम महान परिवर्तनों के समय में जी रहे हैं। 2008 के वित्तीय ध्वंस के बाद के वर्षों में उभरे राजनैतिक प्रतिरोधों की लहर तक, नए चरम–दक्षिणपंथी आंदोलनों के उदय से महामारी के वर्तमान प्रभावों तक, घटनाओं की एक श्रंखला सन्देश देती है कि हम एक ऐतिहासिक चौराहे पर हैंः एक दुनिया मरती दिखाई दे रही है जबकि दूसरी का जन्म होना बाकी है। ये प्रक्रियाएं न सिर्फ स्थापित सामाजिक संस्थाओं के लिए बल्कि उसे भी जो हमें सबसे घनिष्ठ लगता है के लिए नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। वे, पिछले दशकों में प्रचलित भावनाओं, सोच और कार्य करने के तरीकों की थकावट को प्रकट करती हैं। हमारा संकट भी व्यक्तिपरकता के एक स्वरुप का संकट है। उत्तरार्ध की संरचना और उसके वर्तमान रूपांतरणों को ध्यान में रखे बिना, हम वर्तमान के खतरों और संभावनाओं को ठीक से आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में संकट में इस विषय का कोई कैसे वर्णन कर सकता है ?

> उद्यमी–अवदासग्रस्त विषय

इक्कीसवीं सदी का मोड़ काफी हद तक अवसाद के संकेत के तहत हुआ। इसलिए तब मनोवैज्ञानिक पीड़ा फ्रायड के समय के शास्त्रीय न्यूरोटिक लक्षणों में मुख्य रूप से प्रदर्शित नहीं होती थी, बल्कि यह थकावट, खालीपन और कार्य करने में असमर्थता की भावनाओं में दिखाई देती है। फ्रायड के न्युरोसिस में *अपराधबोध* की बीमारी सम्मिलित थी जिसमें व्यक्ति अनुमत और निषिद्ध, कानून की शक्ति और दमित इच्छाओं के मध्य खिंचा हुआ महसूस करता है। इसके बदले में, अवसाद को *अपर्याप्तता* की बीमारी के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अनुमत है पर व्यक्ति उपलब्ध संभावनाओं की पूरी श्रंखला को मापने में असमर्थ महसूस करता है। एक व्यक्ति अवसाद में इसलिए आ जाता है क्योंकि उसे उस भ्रम का भार सहन करना पड़ता है कि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता हैः संभव और असंभव, अंतहीन रूप से उपलब्ध और जो व्यक्ति वास्तव में पूरा करने में सक्षम है के मध्य बंटा अवसाद ग्रस्त व्यक्ति ''आउट ऑफ गैस'' व्यक्ति है।

नैदानिक निरूपण में न्युरोसिस से अवसाद में इस तरह का परिवर्तन केवल पीड़ा के विशेष अनुभवों से सम्बंधित नहीं है। इसके बजाय, इसे 1960 के दशक के बाद से स्थापित नई सामाजिक व्यवस्था के संकेत के रूप में व्यापक रूप से देखा जा सकता हैः वह जिसमें व्यक्तियों को गिरते सामाजिक समर्थन और बढ़ती असमानता, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता के सन्दर्भ में आत्म–जिम्मेदारी और आत्मानुभव सामना होता है। संग्रहण की पोस्ट–फॉर्डिस्ट व्यवस्था के विकास और व्यक्तिगत प्रमाणिकता के रूमानी आदर्शों के प्रसार के मध्य एक ''वैकल्पिक आत्मीयता'' के परिणामस्वरूप एक नए विषय ने अहम् स्थान ग्रहण कियाः कथित रूप से नवउदार ''स्वयं के उद्यमी'' जिन्हे बाजार की सफलता ''स्वयं होने'' की मांग को उपयुक्त रूप से जवाब दे कर या जैसा कि एक लोकप्रिय स्वयं–सहायता पुस्तक, *वन्स बेस्ट सेल्फः बी यू, ओनली बेटर* ने सुझाया, से मिलनी थी। वैषयिक आज्ञाकारिकता के बजाय इस उद्यमी विषय से स्व–खोज और प्रयोगात्मक दोनों रूप से सृजित भावनात्मक रूप से संचारी और बदलती बाजार स्थितियों से लचीले ढंग से अनुकूल विलक्षण जीवन का निर्वाह की आवश्यकता है।

अवसाद ग्रस्त व्यक्ति उस बिंदु को चिन्हित करता है जहाँ पर स्वयं के उद्यमी होने की आवश्यकता विषयगत रूप से समस्या बन जाती हैः जब प्रामाणिक आत्मबोध की सम्भावना शून्य और थकावट

> >

में बदल जाती है, जब स्वायत्त आत्मनिर्णय की खोज अलगाव की भावना में समाप्त होती है। केवल एक नैदानिक निरूपण से कहीं अधिक, बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में संस्थागत मानदण्डीय अपेक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की व्यक्तिपरक विफलता के लिए अवसाद एक प्रमुख शब्द बन गया है।

> संकट एवं थकावट की राजनीति

यह सामाजिक विन्यास– जिसे हम सामान्य रूप से *अवसाद ग्रस्त समाज* के रूप में चिन्हित कर सकते हैं– बढ़ते तनावों से व्याप्त है और फिर भी इसने पिछले दशकों में काफी हद तक स्थिरता बनाये रखने में कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं, इक्कीसवीं सदी के मोड़ पर, यह संस्थागत व्यवस्था, अपने ही तर्क से स्पष्ट राजनैतिक दावों और संगठित सामाजिक संघर्षों के सन्दर्भ में अवसादग्रस्तता के लक्षणों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करती प्रतीत हो रही थी। आज हालाँकि, इस व्यवस्था के दबाब इस हद तक तीव्र हो गए हैं कि इसकी अटलता गंभीर रूप से जोखिम में लगती है: अवसादग्रस्त थकावट अपने आप में थकावट के बिंदु तक आ गयी है। इस सन्दर्भ में मेरा सुझाव है कि हम एक *अवसाद–पश्चात् पुंज* के बारे में बात करें : एक स्थिति जिसमें अवसादग्रस्त व्यवस्था के सामाजिक–मनोवैज्ञानिक तनाव चरम पर पहुँच गए हैं, जिसने कई तरह की प्रतिक्रियाएँ और संघर्ष को अग्रेषित किया है लेकिन अभी तक एक नए मतैक्य और स्थिर संस्थागत ढांचे की स्थापना नहीं हुई है।

मेरा तर्क है, इस तरह का वर्णन इस बात से आधार पाता है कि पिछले वर्षों में प्रमुख हुए राजनैतिक संघर्षों के प्रकारों को नवउदार, उद्यमी–अवसादग्रस्त व्यक्तित्व में निहित दो प्रमुख तनावों की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है।

स्वायत्ता के मुद्दे के सम्बन्ध में, व्यक्तिपरकता के इस रूप का वादा यह है कि एक व्यक्ति उद्यमी पहलों के माध्यम से आत्म–निर्णय तक पहुँच सकता है: सामाजिक जीवन जिन विभिन्न बाजारों में समाविष्ट है उनमें से किसी एक में नवोन्मेषी उत्पाद की पेशकश कर, व्यक्ति उन पर अपनी निजी छाप छोड़ने में सफल होगा और उन्हें अपनी छवि और समानता में बदल सकेगा। तथापि इस वादे को पूरा करने में बार बार विफलता एक मजबूत भावना की तरफ ले जाती है कि व्यक्ति पूर्व–निर्धारित नियमों के एक समूह के अधीन होता है जिन्हें अक्सर समझना और संशोधित करना कठिन होता है: ''कोई विकल्प नहीं है''। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि फिर हमारे समय के कई आंदोलन शासक अभिजनों के प्रति एक चिन्हित नाराजगी प्रकट करते हैं और अधिक भागीदारी के लिए दावा करते हैं: उन्हें सामाजिक विनियमन के प्रचलित स्वरूपों के *भाग्यवाद* की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।

नवउदारवादी व्यक्तिपरकता एक दूसरे तनाव से भी चिन्हित होती है, इस बार यह प्रमाणिकता के प्रश्न से सम्बंधित है: अन्य के साथ, स्नेहपूर्ण सम्बन्ध के वादे और एकल व्यक्तियों के मध्य सामाजिक जीवन की बाजार रूपी प्रतिस्पर्धा (थैचर के नारों में से एक में से संश्लेषित: ''समाज जैसी कोई चीज नहीं है'') के रूप में संरचना। हालाँकि, यह मांग कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए ने पृथक्करण और सामाजिक विखंडन की बढ़ती हुई भावनाओं को बढ़ाया है। फिर यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे समय के कई राजनैतिक आंदोलन भावात्मक एकता के अनुभवों की इच्छा को प्रकट करते हैं: इस सम्बन्ध में उन्हें सामाजिक *विघटन* के प्रचलित रूपों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।

और फिर भी, अवसाद–पश्चात की स्थिति राजनैतिक कार्यवाही या संगठन के एक भी एकजुट रूप की विशेषता नहीं है। हम एक नई व्यवस्था के साथ उतना काम नहीं कर रहे जितना एक नए पुंज, भिन्न प्रतिक्रियाओं एवं राजनैतिक क्षितिजों के एक कुलक के साथ। निम्नलिखित में, मैं, दो राजनैतिक रुखों को सम्बोधित करूँगा जो विगत वर्षों में प्रमुख हो गए हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान संकट में उभरने वाले एकमात्र के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हमारा वर्तमान एक केंद्रीय प्रश्न द्वारा आकारित है – अवसाद के बाद क्या आता है? – अभी तक इसका कोई एक या प्रचलित उत्तर नहीं है।

> अवसाद पश्चात उत्साह

2010 के दशक से कई राजनैतिक विद्रोह– अरब स्प्रिंग से लेकर ऑक्युपाइ वाल स्ट्रीट, ब्राजील में जून 2013 से फ्रांस में *गिलेट जोंस* तक– अपने निर्णायक क्षणों में एक अस्पष्ट संरचित सामूहिकता में स्नेहपूर्ण मग्नता के अनुभवों के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों की अनुपस्थिति से अंकित थे। ये दो विशेषताएँ यह समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें अवसाद–पश्चात स्थिति की अभिव्यक्ति के रूप में क्यों देखा जा सकता है।

इन आंदोलनों की मानक और भावात्मक अस्पष्टता, जिसके लिए इनकी अक्सर आलोचना की गई थी, उनकी अपील का आधार भी थी : इसने एक साझा माहौल में भागीदारी पर आधारित एकजुटता की भावना को अनुमति दी, यह धारणा कि सामाजिक और राजनैतिक मतभेद अब बेमेल नहीं थे अपितु ये विविधता में और उसके बाहर स्थापित भावत्मक एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। उन आंदोलनों के दबाब को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है। स्व–उद्यमी की आत्म–निर्भरता और अवसादग्रस्त विषय के अलगाव की तुलना में स्वयं को कई लोगों के साथ सड़कों पर पाने के अनुभव को कई लोगों द्वारा भावात्मक रूप से मुक्त करना था या '' भेदक'' के रूप में महसूस किया गया था।

अब यह स्पष्ट है कि भावनात्मक एकजुटता की यह भावना (कुछ अनिश्चित), एक आम (यद्यपि काफी मोटे तौर पर परिभाषित) विरोधी के साथ टकराव के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई है: राजनैतिक व्यवस्था, प्रचलित संस्थाएँ, ''वो सब कुछ जो वहां हैं''। स्थापित मानदंडों को चुनौती देने के लिए सामाजिक उत्साह के अनुभवों का कट्टरपंथी के साथ संयोजन, चाहे क्षणिक रूप से ही, स्थापित मान्यताओं के लिए चुनौतीपूर्ण था। पुलिस के साथ टकराव, सड़कों को अवरुद्ध करना, सार्वनजिक संस्थानों पर कब्जा: अचानक जिंदगी अब अपरिवर्तनीय, घातक, कानूनों के समूह से बाधित प्रतीत नहीं हो रही थी। पूर्व–प्रदत्त मानदंडों से स्व–उद्यमी का अनुकूलन और अवसाद ग्रस्त व्यक्ति की शक्तिहीनता की भावना के विपरीत प्रतिकूल स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने का अनुभव किसी को प्रभावी सामूहिक *आत्म–निर्णय* की क्षमता को प्राप्त करने की भावना दे सकता है।

हालाँकि ऐसे क्षण अंतनिहित रूप से अस्थिर साबित हुए हैं। जल्दी ही यह धारणा पैदा हुई कि एकजुटता की यह भावना विषम तत्वों से बनी है जो आसानी से मेल नहीं खाते हैं; जल्द ही इसमें सम्मिलित लोगों ने महसूस किया कि उनके मानदण्डीय नियामक दृष्टिकोण मौलिक रूप से भिन्न राजनैतिक व्यवस्थाओं को जन्म दे सकते हैं। इन आंदोलनों की मानदण्डीय अस्पष्टता और भावात्मक अनिश्चितता से सटीक रूप से तनावों का एक नया कुलक पनपा। उन्होंने काफी दुविधापूर्ण सामूहिक अनुभव के राजनैतिक अर्थ और संस्थागत अभिव्यक्ति से सम्बंधित संघर्षों की शुरुआत को चिन्हित किया– जहाँ से, अन्य राजनैतिक दृष्टिकोणों के मध्य, अति–दक्षिणपंथी आंदोलनों की नई लहर उभरी।

>>

> अवसाद–पश्चात सत्तावाद

सामाजिक विखंडन की बढ़ती धारणा शायद यह व्याख्या कर सकती है कि 2010 के दशक के आंदोलनों में जो हुआ उसके समान नए दक्षिणपंथ के हालिया उभार भावनात्मक एकता की तीव्र अपेक्षाओं द्वारा चिन्हित है। हालाँकि, एक विजातीय/विषम बहुलता में डूबे रहने का अनुभव, एक अनिश्चित ''आम'' ने यहाँ एक समागम (राष्ट्रीय) की अधिक सार्वभौम और अपवर्जित धारणाओं को रास्ता दिया– जैसा कि ट्रम्प की '' मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'' या बोल्सनारो का ''ब्राजील अबव एवरीथिंग, गॉड अबव एवरीवन'' में ।

इस राजनैतिक रुख को इस प्रकार सामाजिक विघटन के लिए एक आक्रामक *रक्षात्मक* तरीके से जवाब देने के लिए देखा जा सकता हैः भावात्मक एकजुटता को संभव बनाने के लिए बाह्य और भ्रष्ट तत्वों के अपवर्जन और उन्मूलन की आवश्यकता होती है – चाहे वे ''साम्यवादी'' (वामपंथ से जुड़े), ''अपराधी'' (नस्लीय गरीबों से जुड़े), ''परिवार के शत्रु'' (नारीवादी और LGBTQI+ आंदोलनों से जुड़े) इत्यादि हों।

फिर भी नए चरम दक्षिणपंथ ने न केवल भावात्मक विखंडन की धारणा के प्रति विभिन्न प्रकार के नैतिक धर्मयुद्ध को आगे बढाकर प्रतिक्रिया दी है; इसने 2008 के संकट और 2010 के दशक के राजनैतिक प्रतिरोधों के मद्देनजर मानदण्डीय अवैधकरण की भावना के लिए एक विशेष तरीके से प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में जो समस्यागत महसूस किया गया है वह यह नहीं है कि वे कठोर ''प्रकृति के नियमों'' (अवसाद ग्रस्त व्यवस्था में जैसे) को मूर्त रूप देते हैं बल्कि यह कि हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जिसमें ''प्राकृतिक'' मानदंडों ने अपनी प्रभावशीलता खो दी है। सत्तावादी व्यक्ति *मानकहीनता* की कथित स्थिति की तुलना में भाग्यवाद की स्थिति पर कम प्रतिक्रिया देता है, अर्थात, ऐसी भावना जो व्यवस्था और स्थिरता के साथ सामाजिक सम्बन्ध प्रदान करने वाले नियमों के स्वरुप के अब पकड़ में नहीं हैं।

यह व्याख्या देता है कि इस तरह का राजनैतिक दृष्टिकोण क्यों प्रचलित मानदंडों के निलंबन की तरफ अभिमुखित नहीं है, जैसा कि सामूहिक उत्साह के पूर्व के अनुभवों में था। इसके बजाय यह दमनकारी व्यवस्था स्थापना की ओर अभिमुखित है। सामाजिक रूप से विघटित ओर अनियत रूप से विनियंत्रित माने जाने वाले समाज की प्रतिक्रिया में, सत्तावादी दावा करते हैं कि एक राजनैतिक समुदाय जो विघटनकारी तत्वों को समाप्त कर सकता है ओर अपनी प्रभावशीलता को बनाये रखने के लिए बाध्यकारी ओर हिंसक मानदंडों को लागू कर सकता है।

तथापि, सत्तावादी होने के साथ, नव चरम दक्षिणपंथ अक्सर (ब्राजील के मामले में विशेष स्पष्टता के साथ) नवउदारवादी प्रोजेक्ट के और अधिक कट्टरपंथीकरण के दावों द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह अवसाद–पश्चात् सत्तावाद का विरोधाभास हैः नवउदार व्यक्तिपरकता के संकट पर, प्रतिक्रिया करते समय और उससे अपनी विपक्षी ताकत को पाते हुए, यह हर तरह से उसी प्रकार की विषयपरकता को जारी रखने और यहाँ तक कि कट्टरपंथी बनाने के लिए सभी साधनों से प्रयास करता है। हूबहू इसी विरोधाभासी संरचना में – अवसाद की स्थितियों को बहाल कर के अवसाद के आगे बढ़ने का प्रयास– इसकी विशाल विनाशकारी क्षमता के स्त्रोतों में से एक है।

सत्तावाद और कट्टरपंथी नवउदारवाद इस प्रकार एक अजीबोगरीब (हम कह सकते हैंः अवसाद–पश्चात्) तरीके से संयोजित है। एक तरफ उनके राजनैतिक गठजोड़ इस धारणा की और ले जाते हैं कि प्रत्येक और वे सब जो तथाकथित अभ्रष्ट स्व–उद्यमी के आदर्श अच्छा नागरिक को अस्वीकार करते हैं, के अपवर्जन और उन्मूलन द्वारा भावात्मक समागम स्थापित किया जा सकता है। दूसरी तरफ, यह उस विचार को भी अग्रेषित करता है कि एक पर्याप्त रूप से एकजुट मानदण्डीय व्यवस्था केवल अडिग और यदि आवश्यक हो तो हिंसक साधनों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो ''बाजार के कानूनों'' को लागू करनाः कोई भी विकल्प नहीं होगा।

> अवसाद से परे ?

नव–अधिनायकवाद और कट्टरपंथी नवउदारवाद के इस प्रकार के संयोजन पर विचार को हमारी वर्तमान स्थिति द्वारा खोले गए एकमात्र या मुख्य क्षितिज के रूप में समझना निश्चित रूप से भ्रामक होगा। एक अधिक व्यापक विश्लेषण, जिसे मैं यहाँ नहीं कह सकता, को उन तरीकों के बारे में सोचना चाहिए जिनमें अन्य राजनैतिक प्रोजेक्ट उद्यमी–अवसादग्रस्त वैषयिकता का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। इनके अन्तर्निहित तनावों को महामारी के प्रकोप के साथ और मजबूत होते देखा जा सकता है। फिर भी, इस सम्बन्ध में हम सामूहिक रूप से जो भी मार्ग अपनाए, वह इस तरह के समागम द्वारा उत्पन्न तनावों और संघर्षों को खुलने से नहीं आ सकता है। ■

सभी पत्राचार आर्थर ब्यूनो को <oliveira@normativeorders.net> पर प्रेषित करें।

> अदृश्य कार्य का दृश्य प्रतिनिधित्व

जेनी टिशर, अप्लाइड आर्ट्स विश्वविद्यालय, वियना, ऑस्ट्रिया द्वारा

कोविड–19 से निपटने के लिए प्रारम्भ किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, हममें से कुछ लोग विभिन्न वातावरणों में सामाजिक दूरी, दूरस्थ शिक्षा, विच्छेद और पृथक्करण का अनुभव कर रहे हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि लोग ''हम'', ''हमारे'', यहां तक कि एक सामूहिक अनुभव के बारे में बात कर सकते हैं, या इससे भी आगे जाकर एक वैश्विक सामूहिकता के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि, वियना में अलाइड आर्ट्स विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता के रूप में मेरे अनुभव को लेते हुए मैं पूर्णतया इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऐसा संभव है। सार्वजनिक स्थानों में आने–जाने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध के समय में, इस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राजनीतिक और सामाजिक विकल्पों की विशाल श्रृंखला अधिक स्पष्ट होती जा रही है।

सीखने और अनुभव के सामूहिक स्थान जैसे स्कूल और विश्वविद्यालय, साथ ही सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क और खेल के मैदान, अभी भी केवल आंशिक रूप से सुलभ है, फलस्वरूप, ये जीवन के फोकस को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर रहे हैं। जब नौकरियां चली जाती हैं और बच्चों को चाइल्ड केयर सुविधाओं में नहीं भेजा जा सकता–एक बगीचे वाले वीकेंड होम की पहुँच के बिना, लोग अपने घरों के छोटे स्थानों तक ही सीमित रह जाते हैं। आंकड़ों से पता चला है कि मनोवैज्ञानिक और घरेलू शारीरिक शोषण में वृद्धि हुई है, और लिंग–आधारित विशिष्ट श्रम विभाजन का मुद्दा (पुनः) एजेंडे में शामिल हो गया है। कोविड–19 मौलिक रूप से उस प्रकार के कार्य को प्रदर्शित करता है जिस पर हमारा समाज निर्भर करता है: व्यवस्था– प्रासंगिक एवं पुनरुत्पादक श्रम। हम सभी सवैतनिक और अवैतनिक देखभाल कर्मियों पर निर्भर हैं, जैसे कि अन्य के मध्य सेक्स वर्कर, दोस्त, प्रेमी व बच्चे। प्रत्येक शरीर और उसके पर्यावरण को पोषित करने, तैयार, साफ–सफाई, खिलाने प्रेम करने, देखभाल करने, साथ रहने, चंगा और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि ''व्यवस्था–प्रासंगिक'' की धारणा विशेष रूप से विवादास्पद है, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि कुछ कार्य ''व्यवस्था'' के लिए (उतने) प्रासंगिक नहीं है।

जैसा कि हम सभी ने अनुभव किया है, मीडिया का ध्यान उन नौकरियों पर बढ़ा है जो हमारी बुनियादी और अस्तित्व संबंधी जरूरतों को सुनिश्चित करते हैं, और सुपरमार्केट में कर्मचारियों की अचानक दृश्यता ने, लोगों को प्रशंसा के संकेत के रूप में ताली बजाने जैसे कार्यों के लिए प्रेरित किया है। मेरे छात्रों में से एक, नोरा लिका ने सामूहिक रूप से किए जाने वाले सार्वजनिक कृत्य और राजनीतिक कृत्य के रूप में एकजुटता के मध्य के अंतर के बारे में एक शोध पत्र लिखा था। उसका निष्कर्ष यह था कि सार्वजनिक रूप से प्रशंसा का सामूहिक कृत्य एक मजबूत –भाव प्रदर्शन करता है ,जो लोगों के सोचने के तरीकों को बदल सकता है और उन्हें आगे बढ़ने की आशा और शक्ति दे सकता है। अंततः, हालांकि, यह सुपरमार्केट, अस्पतालों डे–केयर सेंटर आदि में कामगारों के लिए बेहतर और सुरक्षित काम करने की स्थिति में या समान और बेहतर वेतन और काम के घंटों में कमी में योगदान नहीं देगा। इसके अलावा, जब हम इस प्रश्न पर वापस जाते हैं कि प्रथम रूप से व्यवस्था–प्रासंगिक के रूप में क्या वर्गीकृत है, तो हम इस बात के प्रति जागरूक होते हैं कि अदृश्य (और अवैतनिक) काम हमेशा रहा है और रहेगा, क्योंकि या तो यह निजी, घरेलू क्षेत्र में होता है अथवा चूँकि यह रात के दौरान किया जाता है।

इस पृष्ठभूमि में, मैं 2020 के अपने दो कोलाजों का परिचय देना और उन पर चर्चा करना चाहूंगी, जो इस लेख के साथ हैं: ''नाइटक्लीनर'' और ''सेवा''। ''नाइटक्लीनर्स'' कोलाज में आप द बेरविक स्ट्रीट फिल्म कलेक्टिव द्वारा प्रायोगिक वृत्त चित्र नाइटक्लीनरस (1972–75) में से लिए गए एक कटआउट और डुप्लीकेट फिगर्स को देख सकते हैं, और एक चलचित्र *हॉटफोर्ड वॉश: वाशिंग/ट्रैक्स/मेंटेनेंस: इनसाइड* (1973) में प्रदर्शित करी हुई संगमरमर की दो मूर्तियों को – कलाकार मिर्ले लैडरमैन उकेलेस का एक प्रदर्शन जो हार्टफोर्ड में वर्ड्सवर्थ एथेनेम संग्रहालय में हुआ था – देख सकते हैं। बेरविक स्ट्रीट फिल्म कलेक्टिव का प्रारंभिक विचार नारीवादी कार्यकर्ताओं के एक समूह के साथ में शामिल होने के लिए अप्रवासी और कामकाजी महिलाओं के समूह को जोड़ना था ताकि एक संघ का निर्माण कर सकें। कलाकारों में से एक मेरी केली, फिल्म की टीम का हिस्सा थी और एक नारीवादी कार्यकर्ता के रूप में नाईट क्लीनरस के अभियान में भी सम्मिलित थी। सर्वप्रथम विचारों में से एक यह था कि, एक वास्तविक समय के वृत्तचित्र को लगभग 8 घंटे तक चलने वाली एक अवधि की फिल्म के रूप में दिखाया जाए जो केवल एक शौचालय की सफाई दिखाती है। फिल्म *नाइटक्लीनर्स* का पोस्टर जो शौचालय की सफाई करने वाली महिला के दृश्य को दर्शाता है, की तरफ इशारा करते हुए कोलाज के चित्र रात्रि काल में कार्यालय कर्मचारियों के अवशेषों की सफाई की संभावित अंतहीन, दोहराव वाली गतिविधियों का प्रतिधिनित्व करते हैं। महिला के पैरों में हम जमीन पर पड़ी एक महिला की सफेद संगमरमर की दोहरी छवि देखते हैं, जो तथाकथित आराम मुद्रा में है।

इस शिल्प को अमेरिकी कलाकार मैरेले लैडरमैन उकेलेस के प्रदर्शन का संलेख करने के लिए ली गई एक तस्वीर की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है, जिसमें वह संग्रहालय के फर्श को साफ करती है। 1969 में लिखा गया *मेनिफेस्टो फॉर मेंटेनेंस आर्ट* के लिए उनका लिखा गया मैनिफेस्टो और उसका संपूर्ण कार्य घरेलूता, पुनरुत्पादन– श्रम और स्वच्छता कार्य के गैर–मान्यता प्राप्त और अवमूल्यन क्षेत्रों को संबोधित करता है। घरेलू कार्यों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने से यह गोचर हो जाता है। और इस काम को कला घोषित और प्रदर्शित करके [''मैं बहुत धुलाई सफाई, खाना पकाने, नवीनीकरण, संरक्षण, रखरखाव आदि करती हूँ, साथ ही (अब तक अलग से) मैं कला 'करती' हूँ। मैं बस इन रोजमर्रा की रखरखाव संबंधी चीजें करुँगी और उन्हें चेतना

>>

जेनी टिशर, कागज पर ''नाइटक्लीनर्स'' कोलाज, 30 x 40 सेमी।

जेनी टिशर, कागज पर ''सेवा,'' कोलाज, 30 x 40 सेमी।

में प्रवाहित करुँगी और उन्हें कला के रूप में प्रदर्शित करुँगी''] और साथ ही इसे प्रदर्शित करते हुए लैडरमैन उकेलेस ने न केवल प्रजनन कार्य की दृश्यता और मूल्य के बारे में प्रश्न उठाएं, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे भौतिक समर्थन के प्रणालीगत सब–स्ट्रेटस (जब कला की भी बात आती है) अनिवार्य रूप से मूल्य उत्पादन के साथ उलझे हुए हैं, खासकर अगर प्रक्रिया सारहीन लगती हो। कोलाज में प्रतिनिधित्व का उल्टा निर्माण क्लासिकवाद के भीतर बनाई गई एक आइकोनोग्राफी द्वारा दर्शाए गए श्वेतता के पदानुक्रम पर सवाल उठाता है, जितने मूर्तिकला में किसी भी बहुरंग संयोजन की अवहेलना करते हुए शुद्ध एकल रंग संयोजन और शुद्ध श्वेतता के आधार पर एक नस्लवादी विचारधारा का निर्माण किया जो पहले प्राचीन दुनिया में कभी मौजूद नहीं था।

''सेवा'' अखबार से तस्वीरों की प्रतियों से बना एक कोलाज है जिसमें एक महिला, हेडसेट के साथ एक महिला को चित्रित करने वाले पोस्टर के सामने सफाई कर रही है। फर्श की सफाई करने वाली महिला को पीछे से दिखाया गया है, और उसने नीली वर्दी पहनी है। इसके विपरीत, पोस्टर की महिला हमें मुस्कुराती हुई नजर आती है और वह सुखद और मैत्रीपूर्ण सर्विस ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करती है। कोलाज इस बात पर प्रकाश डालता है कि भले ही तकनीकी उपकरण बदल सकते हैं– जैसे कोलाज पर पंख झाड़ू और रोबोट वेक्यूम जुड़ते नजर आते हैं– एक अलग छवि या अलग उपकरणों का उपयोग करके सेवा क्षेत्र में श्रम के मूल्य को बदलना संभव नहीं है। वर्ग, नस्ल और लिंग की रेखाओं में विभाजित ''गंदे काम'' की व्यक्त छिपी संरचना को संबोधित करने के लिए प्रतिनिधित्व, मूल्य वृद्धि और अदृश्य कार्य के उलझाव को अभी भी उजागर और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ■

सभी पत्राचार जेनी टिशर को <jenni.tischer@uni-ak.ac.at> पर प्रेषित करें।

> वैश्विक महामारी के दौरान घरेलू हिंसा

मार्गरेट अब्राहम, हॉफस्ट्रा विश्वविद्यालय, यूएसए, आईएसए की पूर्व अध्यक्ष (2014–18) और आईएसए की प्रजातिवाद, राष्ट्रवाद, स्वदेशीयता और जातीयता (आरसी 05), प्रवासन का समाजशास्त्र (आरसी 31), महिला, लिंग और समाज (आरसी 32), मानवाधिकार और वैश्विक न्याय (आरसी 03) और हिंसा व समाज (टीजी 11) अनुसंधान समितियों की सदस्य द्वारा

साभारः फ्लिकर/जेन फॉक्स।

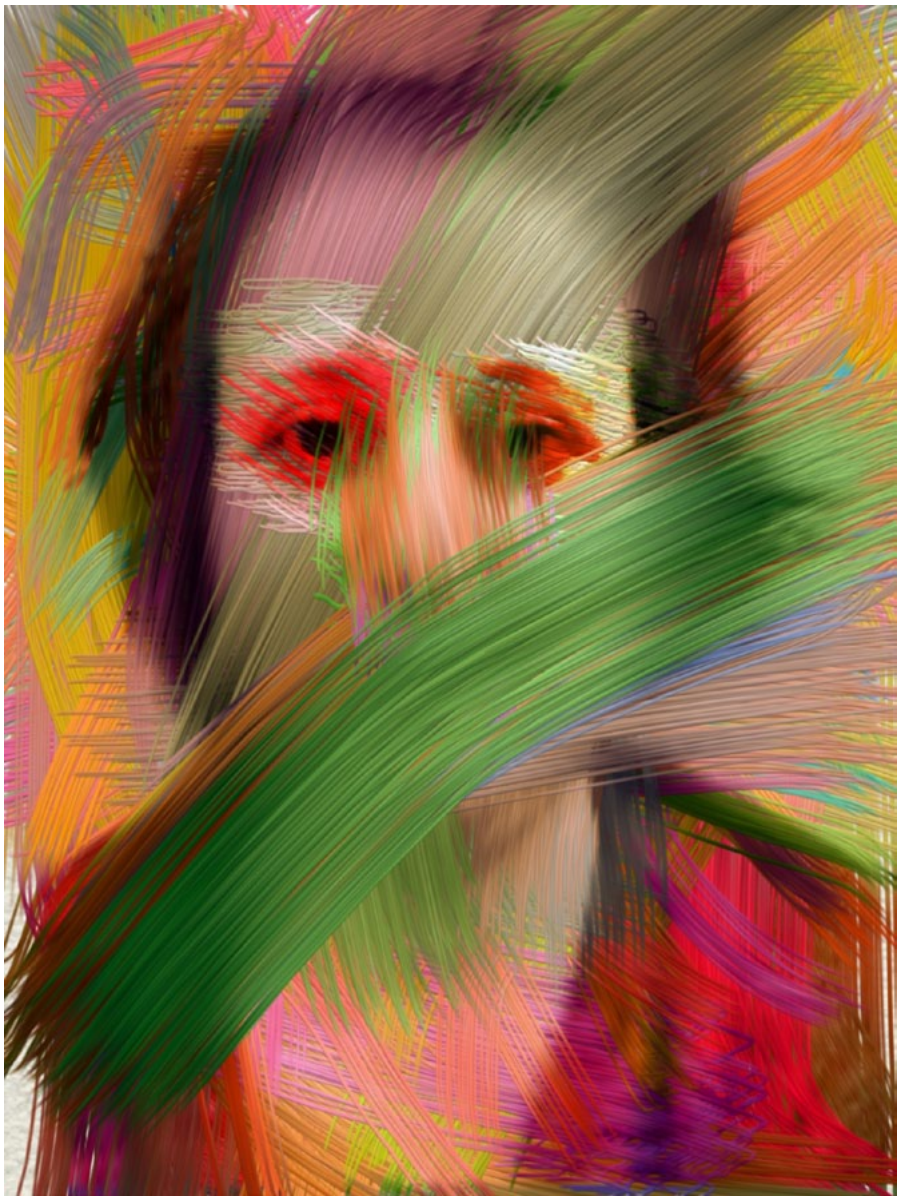

संकट और अनिश्चितता के समय में घरेलू हिंसा में वृद्धि होती है, इस तथ्य को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। वर्तमान कोविड–19 वैश्विक महामारी कोई अपवाद नहीं है। मार्च 2020 के बाद से, कोरोनावायरस ने दुनिया भर में ''लॉकडाउन'', ''घर–पर–रहे'', और ''शेल्टर–इन–प्लेस'' आदेशों का नेतृत्व किया है, जिसने लोगों की गतिविधियों पर सरकार द्वारा अनिवार्य प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहाँ, यह वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए एक आवश्यक कदम साबित हुआ है, यह, जैसा कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है, घरेलू हिंसा की ''छाया महामारी'' का कारक है। सामाजिक पृथक्करण और दूरी संबंधी नीतियां, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, विडंबनापूर्ण रूप में अप्रकार्यात्मक व अपमानजनक संबंधों में बंधे लोगों के लिए कम सुरक्षा की स्थिति पैदा करती हैं। महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय और मानसिक तनाव की स्थिति ने कुछ परिवारों में, जहाँ पहले मौजूद नहीं था, दुर्व्यवहार को जन्म दिया है। वे लोग जो पहले से ही दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं, इसने हिंसा को जटिल और उत्तेजित किया है और कुछ मामलों में मौत का कारण भी बना है।

घरेलू हिंसा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर शक्ति और नियंत्रण के बारे में हैं और यह विभिन्न तरीकोंः शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक यौन, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप में प्रकट हो सकती हैं। जहाँ, घरेलू हिंसा सभी समुदायों में होती है, लेकिन इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक दृष्टांत और संबंध का शक्ति, विशेषाधिकार और नियंत्रण के अंतरों का अपना संदर्भ होता है। प्रजाति, जातीयता वर्ग, लिंग, यौन अभिविन्यास, जाति, संस्कृति, आयु, क्षेत्र, धर्म और अप्रवासी स्थिति के प्रतिच्छेदन के आधार पर जटिल समानताएं और अनुभवों के अंतर भी मौजूद हैं। अनुसंधान इंगित करता है कि घरेलू हिंसा का सूक्ष्म, मध्य और स्थूल स्तरों पर हाशिये के समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोविड–19 महामारी ने इसे सच साबित कर दिया है, क्योंकि हाशिये के समूह नौकरी छूटने, वित्तीय कठिनाई और संक्रमण के मामले में अधिक बोझ उठाते हैं (उदाहरण के लिए, अति–आवश्यक सेवा कार्य के माध्यम से अधिक जोखिम के कारण, औरध्या स्वास्थ्य सेवा तक कम पहुंच के कारण)।

> महामारी की स्थितियां

मार्च 2020 से, कई देशों की रिपोर्टों से पता चला है कि लॉकडाउन और विभिन्न प्रतिबंधों ने लिंग आधारित हिंसा, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ

>>

हिंसा, को बढ़ाया है और इसे तेज किया है। दुर्व्यवहार का सामना करने वालों के लिए अपने घर की सीमाओं से बचने और छोड़ने की असमर्थता तथा कम विकल्प उपलब्ध होने के कारण मित्रों, परिवारों, कार्यस्थलों और अन्य समर्थन नेटवर्क से अलगाव को अग्रेषित किया है। इसके बाद ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जहां दुर्व्यवहार करने वाले अपने पीड़ितों पर लगातार और अधिक निगरानी और नियंत्रण में लगे हुए है तथा वे भोजन, कपड़ों, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता उत्पादों तक सीमित पहुंच के माध्यम से उनके व्यवहार की निगरानी और उसमें बाधा डालने में सक्षम हैं। महामारी ने, अनजाने में ही, अति–आवश्यक सामुदायिक और मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता में भी बाधाएं पैदा कर दी हैं। न केवल डर, बल्कि व्यवहारिक वैकल्पिक सुरक्षित विकल्पों की कमी ने भी दुर्व्यवहार के शिकार लोगों को अपने दुर्व्यव्यहारियों के साथ रहने के लिए मजबूर किया है।

कोरोनावायरस द्वारा निर्मित परिस्थितियों ने हम सभी के लिए संस्थागत और सामाजिक समर्थन के कई स्वरूपों को कम कर दिया है। शक्ति और नियंत्रण का घरेलू हिंसा के केंद्र में रहना जारी है, खाद्य असुरक्षा, बेरोजगारी, भय और चिंता, हताशा ,अवसाद, अलगाव और शोक सहित महामारी से संबंधित तनावों और कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप, कारक कारणों में वृद्धि हुई है। स्कूलों और चाइल्डकेयर सुविधाओं के बंद होने से कई मामलों में यह तनाव और बढ़ गया है और सभी स्तरों पर पारिवारिक संसाधनों पर दबाव पड़ा है; साथ ही इसने दुराचारी घरों में बच्चों के लिए जोखिम भी बढ़ाया है। घर की सीमा के भीतर संवाद करना और मदद मांगना; और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, विशेष रूप से तब जब सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के कारण संगठनों को वास्तविक कार्यालयों को बंद करने और ऑनलाइन स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, कोविड–19 ने कुछ संगठनों को बहुत आवश्यक सहायता सेवाओं तक पहुंचने और प्रदान करने के लिए नए तरीकों के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने का अवसर दिया है।

महामारी के प्रारम्भ में इस मुद्दे को स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटिरेज ने सरकारों से महामारी से बचाव के उपायों के साथ ''घरेलू हिंसा में भयावह वैश्विक उछाल'' को संबोधित करने और महिलाओं की सुरक्षा को संबोधित करने के उपायों का आह्वान किया। घरेलू हिंसा का सामना करने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए समूह और समुदाय–आधारित संगठन और हिंसा विरोधी संगठन कई तरह से प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉटलाइन ने 2019 में इसी अवधि की तुलना में 16 मार्च और 16 मई 2020 के मध्य प्राप्त कुल कॉलों में 9.5% की वृद्धि दर्ज की। इसने यह भी प्रलेखित किया कि दुर्व्यवहार करने वाले अधिक नियंत्रण और दुर्व्यवहार के लिए किस प्रकार कोविड–19 का उपयोग कर रहे थे। अपराधियों द्वारा दुर्व्यवहार और नियंत्रण व्यवहार के प्रकटीकरण में अब भोजन देने से इंकार करने के साथ–साथ, आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा वस्तुओं जैसे साबुन, कीटाणुनाशक और सुरक्षात्मक मास्क को रोकना शामिल है। कई देशों में दुर्व्यवहार करने वालों की एजेंसी में वृद्धि हुई है क्योंकि कानूनी प्रणाली और अन्य सहायता प्रणालियों जैसे पुलिस, आश्रयों और अदालतों तक पहुंच सीमित हो गई है, और मामलों में देरी हुई है। आप्रवासियों के लिए निर्वासन के डर से यह और भी बढ़ जाता है। आंतरिक और बाहरी प्रवास के मुद्दों के आसपास महामारी के दौरान राज्य और सरकारों की नीतियों और कृत्यों की भूमिका घरेलू और लिंग–आधारित हिंसा का सामना करने वालों के लिए निहितार्थ है, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है।

घरेलू हिंसा को संबोधित करने वाले संगठनों को महामारी के समय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के कारण उन तरीकों को बदलना पड़ा है जो वे जीवित बचे लोगों का समर्थन करने के लिए काम में लेते हैं। न्यूयॉर्क में दक्षिण एशियाई महिलाओं के लिए सखी की कार्यकारी निदेशक कविता मेहरा बताती हैं:

मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान, जब न्यूयॉर्क शहर में शेल्टर–इन–प्लेस के आदेश प्रभावी थे, दक्षिण एशियाई महिलाओं के लिए सखी एक ऐसे समुदाय की सेवा कर रही थी जो केंद्र के भी केंद्र में रह रहा था। उत्तरजीवियों से, विशेषरुप से ब्रूकलिन, क्वींस और ब्रोंक्स में रहने वालों से, हमारी टीम की जो बातचीत हो रही थी, से पता चलता है कि वे हिंसा के रूपों को तेजी से बढ़ते और अधिक गहन होते देख रहे थे। इसके साथ ही वे महामारी से अप्रत्याशित आर्थिक गिरावट का भी प्रबंधन कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप आवास, भोजन और उपयोगी और असुरक्षा की अप्रत्याशित दरें सामने आई। संघीय पैकेज के सीमित समर्थन ने कुछ लोगों के लिए राहत के रूप में कार्य किया, परंतु अप्रलेखित उत्तरजीवी या वे जिनके पास अभी भी अपने दुराचारियों के साथ एक सयुंक्त बैंक खाता था, वे बिना सुरक्षा के छोड़ दिए गए थे। हमारे समुदाय का समर्थन करने के लिए सखी ने मार्च से अक्टूबर 2020 के महीनों में आपातकालीन सहायता में $1,30,000 से अधिक और लगभग 16,000 पाउंड का भोजन वितरित किया।

लोगों द्वारा घर की सीमाओं और बंधनों की चुनौतियों, भय और गोपनीयता की कमी का सामना करने के कारण कुछ घरेलू हिंसा संगठनों द्वारा स्वयं को अधिक कॉल नहीं मिलते पाया है।

> समाजशास्त्री क्या कर सकते हैं?

घरेलू हिंसा को संबोधित करना इस महामारी के गुजरने का इंतजार नहीं कर सकता। समाजशास्त्रियों के रूप में हमें एक प्रासंगिक वैश्विक समाजशास्त्र की ओर देखना चाहिए और वैज्ञानिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों, नीति–निर्माताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य हित धारकों के साथ मिलकर लिंग संबंधी हिंसा को समाप्त करने और संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक एजेंडा विकसित करना चाहिए। हमें आंकड़ों के संग्रहण और रिपोर्टिंग के लिए बेहतर तरीकों की आवश्यकता है। हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता को समझने की जरूरत है, जो कोविड–19 के दौरान घरेलू हिंसा के अनुभवों को प्रभावित कर रहे हैं, और हमें उस समझ का उपयोग सूचित कार्यवाही के लिए करना चाहिए। आपदाओं के दौरान महिलाओं और बच्चों को दुर्व्यवहार संबंधों से बाहर निकालने से क्या रोकता है और क्या सहायता करता है, और हमने क्या चुनौतियां और सफलताएं देखी हैं? एक प्रतिच्छेदन दृष्टिकोण को काम में लेते हुए, हमें अपने ज्ञान, सिद्धांत और विश्लेषण को प्रकाश डालने, कार्य करने और हस्तक्षेप करने के लिए काम में लेना चाहिए। हमें उन संगठनों और पहलों का समर्थन करने की आवश्यकता है जो इस नए यथार्थ को पूरा करने के रचनात्मक तरीके खोज रहे हैं। मानव इतिहास की इस अवधि के दौरान, हमें स्वयं, घरेलू हिंसा और सभी प्रकार की लिंग आधारित हिंसा को पुनःपरिभाषित और पुनःनिर्मित करना होगा। लॉकडाउन में महिलाओं और बच्चे अपने दुराचारियों के साथ घर पर इंतजार नहीं कर सकते हैं। ■

सभी पत्राचार मार्गरेट अब्राहम को
<Margaret.Abraham@Hofstra.edu> पर प्रेषित करें।

> कोविड–19 संकट: नए समाजशास्त्र और नारीवाद

करीना बेथयानी, कार्यकारी सचिव, CLASCO, उरुग्वे और **एस्तेबान टोर्रेस**, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉरडोबा–कोनीसेट, अर्जेंटीना द्वारा

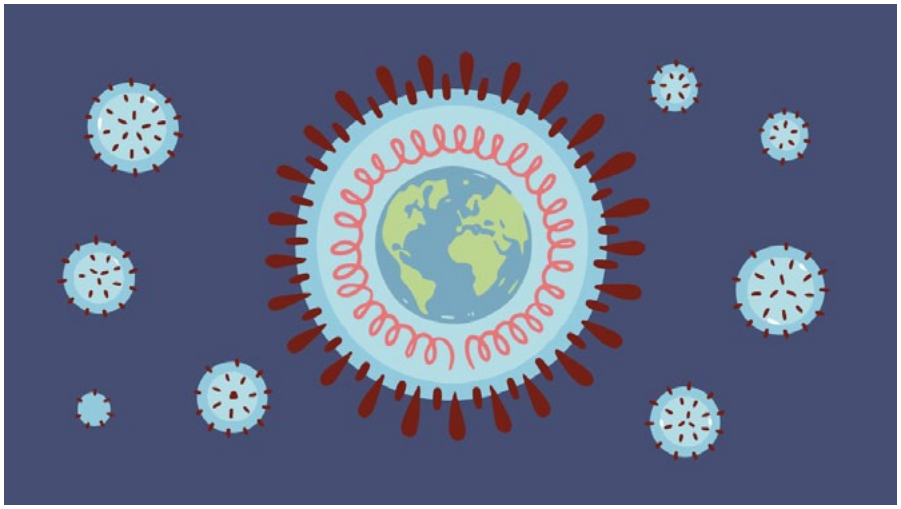

साभारः क्रिएटिव कॉमन्स।

सामाजिक विज्ञानों के लिए, कोविड–19 के विस्तार से जुड़े विशाल संकट ने जो मुख्य नवीनता पैदा की है, वह इस बात की अनदेखी करने की असंभवता की पहचान है कि हम क्षेत्रीय समाजों में रहते हैं जो तेजी से वैश्विक स्तर पर अन्योन्याश्रित हैं। यदि, 2020 से पहले, सामाजिक अध्ययन अभी भी अवलोकन के वैश्विक ढांचे के वितरण के लिए स्वीकार्य औचित्य विकसित करने में सक्षम थे, तो अब ऐसा नहीं है। महामारी ने अपरिवर्तनीय ध्यान की एक प्रक्रिया शुरू की है, जो जल्द या बाद में सभी शोध वस्तुओं को प्रभावित करेगी तथा जहाँ से लौटना संभव नहीं होगा।

गंभीर कालानुभ्रम में पड़े बिना वैश्विक समाज के अस्तित्व को छोड़ना अब संभव नहीं है। यदि समुद्रतटीय नौवहन के समय में, अमेरिका की विजय ने भौतिक वैश्वीकरण की शुरुआत की, तो इसकी काफी संभावना है कि हमारे डिजिटल स्क्रीनों पर कोविड–19 के प्रतिनिधित्व से निपटे गए प्रहार हमेशा के लिए बौद्धिक सामान्य ज्ञान के रूप में वैश्वीकरण का लंगर डालेंगे। इस प्रकार भौतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विस्तार करने के बजाए, कोविड–19 के अवतारों का सामूहिक प्रसंस्करण मानसिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विस्तार कर रहा है। हम सूक्ष्म सामाजिक संवेदनाओं और व्यक्तिपरक एकीकरण की गिरावट नहीं देख रहे हैं, बल्कि समाजों पर विश्व गतिशीलता के गुरुत्वाकर्षण बलों की अज्ञानता और ऐतिहासिक खंडन की एक लंबी प्रक्रिया के लिए एक ऊर्ध्वाधर, औचक, अकल्पनीय अंत को देख रहे हैं।

> सामाजिक विज्ञान ज्ञान उत्पादन की यांत्रिकी

ज्ञान उत्पादन के एजेंडों को कैसे रूपांतरित किया जाता है, की यांत्रिकी पूरी तरह से अज्ञात नहीं है। सामाजिक परिवर्तन आमतौर पर दो स्वयंसिद्ध सिद्धांतों के साथ प्रबल होता है। प्रथम, ऐतिहासिक घटनाएं और प्रक्रियाएं सामाजिक विज्ञानों में ज्ञान उत्पादन के दिशानिर्देशों को निर्धारित करती हैं, ना कि इसके विपरीत। कोविड–19 का प्रसारण एक ''बाहरी'' और तटस्थ घटना के रूप में उभरता है जो सामाजिक –वैज्ञानिक क्षेत्र को पूरी तरह से प्रभावित करता है। चार दशक पहले, प्रादेशिक क्षेत्र में एक अन्य ''बाहरी'' घटना, जैसे दक्षिण अमेरिका में सैन्य तानाशाही के विनाशतंत्र की शुरुआत ने, समाजशास्त्र के स्थानिक आधारों को विघटित करते हुए, 1960 के दशक से उच्च गति से प्रसारित होते वैश्वीकरण के आवेगों को बाधित किया।

दूसरा, व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान से आगे हैं, जो बाद में उसके द्वारा निगल लिया जाता है। यहां एक भ्रूण अवस्था में वैश्विक संबद्धता की नई धारणा प्रकट होती है, जो अभी तक नए सैद्धांतिक और विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ साथ प्रायोगिक क्रिया द्वारा स्वयं को पुनः–कूटित करने में सक्षम नहीं है। यदि हम कोविड–19 की घटना को गंभीरता से लेने का फैसला करते हैं, यदि हम पूरे ध्यान से इसमें उतरते हैं, तो हमें इसे अपने ऊपर पूरी तरह से हावी होने देना चाहिए। सामाजिक वैज्ञानिकों के रूप में हम आम तौर पर कुछ शांतचित्तता के साथ यह मानने को तैयार होते हैं कि सत्य अनंतिम है, लेकिन इस पुष्टि के साथ आने वाले गंभीर प्रायोगिक परिणामों को नहीं, प्रत्येक सृजित दृष्टिकोण और विचार को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने की आवश्यकता है अथवा उसे स्वयं को नष्ट करने की जरूरत है ताकि इसे पुनर्निर्मित किया जा सके। ज्ञात के मिथ्यात्व में आराम से रहने से बचने का अब यही एकमात्र उपाय है।

> विश्व– समाज के नए सिद्धांत

जिस प्रकार विश्व–समाज किसी एक स्थान की उपज नहीं है, उसी प्रकार विश्व समाज का सिद्धांत भी नहीं हो सकता है। एक विश्व समाज एक उच्च–क्रम नेटवर्क

>>

''कोविड–19 का विश्व संकट सभी समाजशास्त्रों के लिए हमें विश्व समाज के नए सिद्धांतों के निर्माण में आगे बढ़ने का अवसर देता है, ताकि प्रत्येक ऐतिहासिक स्थान से, सामाजिक, लिंग और आर्थिक असमानताओं के बढ़ते वैश्वीकरण का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके।''

जैसा हो सकता है, जो पूरे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सामाजिक क्षेत्रों को अलग, एकीकृत और संबंधित करता है। हम मान सकते हैं कि दुनिया में सामाजिक स्थिति का प्रत्येक बिंदु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन तीन परस्पर क्रिया क्षेत्रों का एक अनूठा संघनन है। जर्मनी का वैश्विक समाज निश्चित रूप से अर्जेंटीना, उरूग्वे, मेक्सिको, चिली या चीन के समान नहीं है। लेकिन ये सभी, आपस में परस्पर अंतः क्रिया के आधार पर, विश्व समाज का निर्माण करते हैं। न ही यहां एक एकल पितृसत्तात्मक व्यवस्था या वैश्वीकृत पूंजीवाद जैसी कोई चीज है: जो मौजूद है, वह ठोस पितृसत्तात्मक तरीके हैं, साथ ही विश्व समाज में केंद्रीय और परिधीय पूंजीवाद के बीच अधीनता की विभिन्न गतिशीलताएँ हैं।

अपरिवर्तनीय विभेदीकरण के इस सिद्धांत की मान्यता सार्वभौमिक नियमितताओं की खोज की संभावना को समाप्त नहीं करती है, लेकिन वे इस संभावना को कम जरूर करती हैं कि संरचनात्मक संबंध और प्रक्रियाएं विभिन्न स्थानों में समान तौर–तरीकों को ग्रहण कर सकती है। समाज का प्राथमिक आधार सांसारिक है को मानने का अर्थ है कि सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र की भौतिकता भी सांसारिक है। 1960 के दशक के बाद से, लैटिन अमेरिकी समाजशास्त्र, विश्व समाजशास्त्र की एक सक्रिय धारा बनने के लिए, समाजशास्त्र का ''अन्य'' या इसके सरल अलगाववादी पुनरुत्पादन के रूप में बंद हो गया है। इस अर्थ में, हमारा मत है कि जिस विश्व समाज के सिद्धांत का निर्माण करने की आवश्यकता है, वह हस्तक्षेप स्थानों के कुल जाल के उभरते ज्ञान की मांग करता है, जिसमें इस विभेदित समग्रता पर एक दूसरे के स्थानिक दृष्टिकोण के साथ अपने स्वयं के दृष्टिकोण को संतुलित किया जाए, और इस विस्तारित अभ्यास से ''स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखने'' के महत्वपूर्ण मानवशास्त्रीय अभ्यास की कोशिश को सक्रिय करना है। इस प्रारंभिक धारणा से, दुनिया को उपलब्ध मौजूदा ज्ञान को इकट्ठा करके नहीं जीता जाएगा, बल्कि एक नया वैश्विक संवाद बना कर, जो ऐतिहासिक स्थान के प्रत्येक बिंदु से उत्पादित और प्रक्षेपित विश्व विचारों से नए संश्लेषण उत्पन्न करने में सक्षम होगा, द्वारा जीता जायेगा।

कोविड–19 का विश्व संकट हमें सभी समाजशास्त्रों के लिए विश्व समाज के नए सिद्धांतों के निर्माण में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। नई वैश्विक दृष्टि हमें प्रत्येक ऐतिहासिक स्थान से सामाजिक, लैंगिक और आर्थिक असमानताओं के बढ़ते वैश्वीकरण का बेहतर ढंग से सामना करने की अनुमति देगी। आलोचनात्मक नारीवादी दृष्टिकोण के मामले में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे उनके दृष्टिकोणों का अधिक से अधिक वैश्वीकरण, संरचनात्मक, सामाजिक परिवर्तन के उनके कार्यक्रमों को बढ़ा सकता है। यह राजनीतिक गतिशीलता की भौतिक तैनाती के लिए बौद्धिक समायोजन की एक प्रक्रिया होगी, जो अनिवार्य रूप से वैश्विक है।

आधुनिक आलोचनात्मक समाजशास्त्र के साथ प्रश्न अधिक जटिल हैं। इसके परिप्रेक्ष्यों का और अधिक वैश्वीकरण, आवश्यक रुप से सामाजिक रूप से जुड़े विज्ञानों के विकास की ओर नहीं ले जाता है। साथ ही यह संभावित परिवर्तनकारी समाजशास्त्र की ओर भी कम ही जाता है। यह समझने के लिए कि यह दशकों से अतिरिक्त शैक्षणिक–राजनीतिक प्रभाव क्यों पैदा नहीं कर रहा है, आधुनिक आलोचनात्मक समाजशास्त्र में राजनीतिक प्रतिबद्धता की धारणा को और अधिक समस्याग्रस्त करना आवश्यक है। हमारा मानना है कि ऐसी प्रथाओं को सामाजिक परिवर्तन की सामान्य नीति की सेवा में रखना आवश्यक है। एक आधुनिक आलोचनात्मक समाजशास्त्र का विकास, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो, आंदोलनों की राजनीति और राष्ट्रीय दलों के साथ एक तरह के नए संबंध की मांग करता है। यह आराम के अकादमिक स्थान को छोड़ने की बात है, उसी तरह से जैसे कम–से–कम लैटिन अमेरिका में 1970 के दशक तक समाजशास्त्रीय धाराओं ने किया था और जिसे नारीवादी आलोचनात्मक विचारधारा आज भी कर रही है। राष्ट्रीय राजनीति की पहुंच हेतु वास्तविकता के सिद्धांत के एकीकरण की आवश्यकता है, जो स्वयं में अंत के रूप में आलोचना के आदि– आमूलपरिवर्तनवाद और अधिकतमवादी आदर्शलोक के खिलाफ सबसे अच्छा मारक है, जो ठोस रूप में यह नहीं समझा सकता कि हम सभी के लिए एक बेहतर समाज की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। बदले में, आधुनिक आलोचनात्मक समाजशास्त्र का यह राजनीतिक परिवर्तन नारीवाद के साथ एक शक्तिशाली और रचनात्मक संवाद में प्रवेश करने के लिए एक आवश्यक शर्त है।

एक संरचनात्मक परिवर्तन को गति देने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ सामूहिक पहल करने के लिए जो इस चिंताजनक ऐतिहासिक समय में हमारे समाज की वर्तमान दिशा को बदल सकता है, यह हम पर, हमारी बौद्धिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक समुदाय का निर्माण करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। ■

सभी पत्राचार
करीना बेथियानी को <kbatthyany@clacso.edu.ar>
और एस्तेबान टोर्रेस को <esteban.torres@unc.edu.ar>
पर प्रेषित करें।

कोविड–19 का भयावह वैश्विक प्रभाव

महमूद धौदी, ट्यूनिस विश्वविद्यालय, ट्यूनीशिया और समाजशास्त्र का इतिहास (आरसी 08), धर्म का समाजशास्त्र (आरसी 22) और भाषा और समाज (आरसी 25) पर आईएसए की अनुसंधान समितियों के सदस्य द्वारा

कोविड–19 महामारी ने मानव सामूहिक अस्तित्व के सबसे बुनियादी सामाजिक मानदंडः सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रहार किया है। सामाजिक दूरी भविष्य में हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करेगी? साभारः विकिमीडिया कॉमन्स।

सभी विवरणों से कोरोनावायरस महामारी एक बहुत ही असामान्य विश्वव्यापी आपदा घटना है। इसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को, विशेष रूप से उन्नत समाजों में मृत्यु–दर और संक्रामक रोगियों की दर को कम करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खींचा है। इनमें से कुछ समाजों तथा अन्य को एक से अधिक बार, हफ्तों तक व्यापक लॉकडाउन के लिए बाध्य होना पड़ा हैं। अमेरिका और ब्रिटेन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके परिणामस्वरूप यह संकट सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए एक प्राथमिक चिंता का विषय होना चाहिए, जिसका विश्लेषण ना केवल मात्रात्मक रूप से बल्कि गुणात्मक परिपेक्ष्य से भी किया जाना चाहिए। इस तरह के विश्लेषण पृथ्वी की हालिया और भविष्य की स्थिति को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

>>

> सामाजिक विज्ञानों को स्वयं चिंता करनी चाहिए

कोविड–19 महामारी ने मानव सामूहिक अस्तित्व के सबसे बुनियादी सामाजिक मानदंड: सामाजिक अंतर्क्रिया पर प्रहार किया है। अधिकांश देशों में ''घर पर रहें'' का नारा प्रमुख संदेश बन गया है। विश्व–स्तर पर सामान्य सामाजिक अंत: क्रिया को रोककर रखा गया है। समाजों के भीतर और मध्य में सामान्य सामाजिक अंत: क्रिया पहले जैसी नहीं है और भविष्य में आने वाली कोरोना लहरें भी इस स्थिति से शायद ही बाहर रहेंगी। विश्वस्तर पर इसकी वर्तमान उपस्थिति और आने वाले वर्षों के लिए इसकी संभावित निरंतरता, लोगों और समाज के जीवन के पैटर्न की मुख्यधारा का हिस्सा बन सकती है।

कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महामारी की खतरनाक स्थिति एक नई वैश्विक सामाजिक समस्या प्रस्तुत करती है, जिसके लिए सामाजिक विज्ञानों को नई अवधारणाओं का पता लगाना होगा और नए उपकरणों की कल्पना करनी होगी जो उदाहरणार्थ, दिवंगत समाजशास्त्री इर्विंग गॉफमैन (1922–82) द्वारा प्रस्तावित अवधारणाओं से से अलग हों। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने नई समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का एक शब्दकोश प्रदान किया जो आमने–सामने की अंतर्क्रिया के सूक्ष्म विवरणों को समझने की सुविधा प्रदान करता है। चल रही वैश्विक महामारी के भीतर, मनुष्यों पर इस महामारी के निम्नलिखित परिणामों : जीवन अनिश्चितता, घटनाओं पर नियंत्रण का महत्वपूर्ण नुकसान, सिर्फ तत्कालिक वर्तमान के साथ चिंता, का विश्लेषण करने के लिए संभावित नई समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का अविष्कार करने की आवश्यकता होगी। इन नई विशेषताओं से निपटने के लिए गुणात्मक समाजशास्त्र बेहतर रूप से प्रभावी हो सकता है। हालांकि सामाजिक विज्ञानों का कार्य दोहरा होगा : सर्वप्रथम, तो हमें दिसंबर 2019 से संकट का अनुभव करने वाले लोगों के व्यवहारों और समाजों की विभिन्न गतिशीलता पर कोविड–19 महामारी के वर्तमान सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका ने अपने जून और जुलाई 2020 के अंक में लोगों पर कोरोना महामारी के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जुड़े मुद्दों जैसे विपरीत परिस्थितियों में लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, महामारी हमें इस बारे में क्या सिखा सकती है? पर ध्यान केंद्रित किया है। जून के अंक ने उस तनाव को रेखांकित किया है, जिसे सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में कार्यरत चिकित्सकों और नर्सों द्वारा झेला जा रहा है। फिर भी, अपने अगस्त 2020 के अंक में इस पत्रिका ने कोरोनावायरस के प्रति शांत स्वर अपनाते हुए यह बताया कि जानवरों के बीच सामाजिक दूरी एक प्राकृतिक प्रघटना है जिसके द्वारा वे स्वयं को बीमार से संक्रमित होने से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि यह सच हो सकता है, परंतु निसंदेह सामान्य मानव सामाजिक अंत: क्रियाओं के लिए सामाजिक दूरी, लंबे समय में समस्याग्रस्त हो सकती है।

दूसरा, यदि आने वाले कुछ महीनों या वर्षों में कोई आमूल–चूल उपचार नहीं मिलता है, तो समाजों को आज दुनिया में सामाजिक जीवन के दृश्यों का पूर्वावलोकन करना चाहिए। महामारी के परिणामों से निपटने के लिए दोनों प्रकार के अध्ययनों के निष्कर्ष, आंशिक रूप से वर्तमान मुख्यधारा से अलग नए सामाजिक विज्ञानों का नवप्रवर्तन करेंगे। कोरोना महामारी की अन्य प्रमुख विशेषताएं समाजों में सामाजिक एकजुटता पर उनके प्रभाव के संदर्भ में सामने आ रही हैं। पश्चिमी उन्नत समाजों को व्यक्तिवादी के रूप में वर्णित किया गया है, और कथित रूप से सोशल मीडिया नेटवर्कों ने उस व्यक्तिवाद के मूल को और कठोर कर दिया है। सामाजिक दूरी और पृथक्करण के पक्ष में अन्य कोरोना विरोधी उपायों की नैतिकता और अनुशीलन न केवल इन समाजों में बल्कि गैर –पश्चिमी समाजों में भी व्यक्तिवाद और अकेलेपन को मजबूत करेगा। इस प्रकार, व्यक्तियों ,समूह, सामूहिकताओं और समाजों के मध्य सामान्य सामाजिक अंत: क्रियाओं को वैश्विक क्षति काफी स्पष्ट है।

> जलवायु परिवर्तन और घृणा वाक भाषण

कोविड–19 महामारी से संबंधित दो बड़ी समस्याएं रेखांकित करने योग्य हैं: जलवायु परिवर्तन और घृणा वाक् भाषण। कुछ विश्लेषकों द्वारा कोरोनावायरस महामारी को पृथ्वी पर मानव व्यवहार के परिणाम के रूप में समझाया गया है जिसके कारण वैश्विक प्रदूषण हुआ है। परिणामस्वरूप, प्रदूषण का जलवायु परिवर्तन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा जैसा कि कुछ मौजूदा सिद्धांत बताते हैं, एक नए खतरनाक वायरस के उभरने की संभावना भी है। वे चीनी शहर वुहान का उदाहरण लेते हैं जहां से प्रारम्भ में कोरोनावायरस उभरा था। इसका कारण चाहे जो हो, वैश्विक कोरोनावायरस संक्रमण एक पेचीदा और चकाचौंध भरी चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है जो आधुनिक वैज्ञानिकों को अपने विषयों के अनुशीलन में अधिक अभिमानरहित और विनम्र होने के लिए आमंत्रित करता है। उनकी वैज्ञानिक नैतिकता को सबसे पहले उनके वैज्ञानिक कार्य के परिणामस्वरूप हो सकने वाली संभावित समस्याओं की सीमा को कम करने के बारे में बहुत गंभीर होना चाहिए।

जहां तक दुनिया भर में घृणा वाक् भाषण की प्रघटना का प्रश्न है, कोविड–19 महामारी के दौरान और उसके बाद इसके बढ़ने की संभावना है। घृणा वाक् भाषण एक ऐसा व्यवहार है जो लोगों को नीचा दिखाता है, नृशंस है और बहिष्कृत करता है और उनके धर्म, रंग, लिंग और जातीयता के आधार पर उनके साथ भेदभाव करता है। इसका स्त्रोत आमतौर पर किसी एक व्यक्ति, एक समूह या पूरे समाज या सभ्यता के प्रति प्रतिकूल या शत्रुतापूर्ण भावना या रवैया होता है। ऐसा अपेक्षित है कि कोरोनावायरस को घृणा वाक् भाषण फैलाने वाली वस्तुओं की सूची में जोड़ा जाएगा। कोरोनावायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों के नागरिक अपने देशों से बाहर यात्रा करने पर बढ़े हुए भेदभाव और घृणा वाक् भाषण का सामना कर रहे हैं और उसका सामना करेंगे। जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने अगस्त 2020 में अनुमान लगाया था, दुनिया भर में पर्यटन उद्योग को अभी और आने वाले महीनों और वर्षों में भारी मार झेलनी पड़ी है और आगे भी झेलनी पड़ेगी। यहां एक विरोधाभास है। वैश्विक कोविड–19 महामारी को आज समाजों को एकजुट करना चाहिए लेकिन भेदभाव और घृणा वाक् भाषण पर इसका प्रभाव शायद ही सकारात्मक है। इस प्रकार, वैश्विक पर्यटन उद्योग को आज और कल न केवल गतिशीलता की बाधाओं के कारण बल्कि घृणास्पद भाषण और भेदभाव में संभावित वैश्विक वृद्धि के कारण भी नुकसान होने की संभावना है। ■

सभी पत्राचार महमूद धौदी को
<m.thawad43@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> महामारी–पश्च परिदृश्य, अनुकूलन से सामूहिक सीख तक

एलेजांद्रो पेल्फिनी, यूनिवर्सिदाद डेल सल्वाडोर, ब्यूनस आयर्स और FLASCO अर्जेंटीना, अर्जेंटीना द्वारा

साभारः क्रिएटिव कॉमन्स।

यद्यपि हम अभी भी कोविड–19 महामारी के बीच में हैं और इसके प्रभाव और नुकसान की गणना करना मुश्किल है, साथ ही किसी तारीख का अनुमान लगाना जब तक यह नियंत्रण में आ जाएगा, मुश्किल है। सामाजिक विज्ञानों ने महामारी–पश्च दुनिया के संभावित परिदृश्यों पर चिंतन करना बंद नहीं किया। वैश्विक संकट की गहराई, साथ ही दैनिक जीवन और सामान्य रूप से पूंजीवाद के कामकाज पर महामारी के अप्रत्याशित प्रभाव इतने नाटकीय है कि यह चिंतन, टीकों की उपलब्धता,सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की पुनः संरचना और विश्व स्वास्थ्य संगठन के भीतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बहुत परे है। इसके बजाय, यह ध्यान में रखते हुए कि यह महामारी एक प्रमुख सभ्यतागत चुनौती है, यह चरम स्थितियों में वास्तविक सीखने की क्षमता और संपूर्ण समाजों के लचीलापन के लिए दर्दनाक परिस्थितियों का सामना करने पर केंद्रित है, जिसमें समाज और मनुष्य एक अभूतपूर्व संरचनात्मक अरक्षितता साझा करते हैं।

> संभावित पश्च–महामारी प्रतिक्रियाएं

जैसा कि अर्थशास्त्री ब्राँको मेलानोविक ने दर्शाया किया है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और कुछ समाजों ने अन्य वैश्विक संकटों के बाद विकास और राजनीतिक संगठन के अपने मॉडल में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे 1873 या 1919 का संकट, या बड़े युद्ध, जो आर्थिकता से परे गए और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां पेश की। इसलिए, यह विचार करना काल्पनिक नहीं है कि इस महामारी से भी उत्पादन, उपभोग और जीवन शैली के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न होंगे, जो एक बार पुनः पूंजीवाद और आधुनिकता की नई चुनौतियों के साथ अनुकूलन करने और स्वयं पर पुनर्विचार की क्षमता को दर्शाता है। बेशक, इसकी गारंटी नहीं है,परंतु यह प्रथम रूप से चिंतन और फिर उन परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक कार्यवाही की सक्रियता पर निर्भर करता है।

फिलहाल, पहली प्रतिक्रिया और इसलिए महामारी के बाद के संभावित परिदृश्यों में से एक विशिष्टतावादी वापसी है। जैसा कि कुछ देशों (ट्रंप के तहत अमेरिका या बोलसोनारो के तहत ब्राजील) में पहले ही यह अनुभव किया जा चुका है, इस पर लंबे समय तक सोचना श्रेयस नहीं है। यह हमेशा की तरह कार्य को जारी रखने, और राष्ट्र– राज्य में शरण लेकर सामान्य स्थिति में वापसी को बढ़ावा देने, अन्य मुद्दों की तरह महामारी के वैश्विक प्रभाव और मौजूदा कट्टरपंथी अन्योन्याश्रितता को अनदेखा करने के बारे में है। इसके बजाय, दो संभावित परिवर्तनकारी परिदृश्यों का पता लगाना अधिक दिलचस्प है जो मनुष्यों की एजेंसी और समाजों की सजगता पर निर्भर रहते हैं। इन क्षमताओं से परिवर्तन के दो स्तरों या डिग्री को अलग करना संभव हैः अनुकूलन से जुड़ा एक पहला कदम (जिसे पर्यावरण की नई जटिलताओं के लिए अपनी प्राथमिकताओं और रुचियों के समायोजन के रूप में समझा जाता है), और दूसरी, सामूहिक सीखने की अधिक अपेक्षा वाली प्रक्रिया (नुकसान को कम करने के लिए नैतिक दायित्व के आधार पर इन प्राथमिकताओं और हितों की वैधता की समीक्षा करना)।

>>

> अनुकूलन

फिर, एक मुख्य रूप से अनुकूलित परिदृश्य की कैसे कल्पना की जा सकती है, जिसमें तीन मूलभूत सामाजिक क्षेत्र (राज्य, बाजार और नागरिक समाज) एक अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए, पहले से ही हानिकारक सिद्ध होने वाली प्रथाओं को पूर्णरूपेण छोड़ें अथवा इसके फलस्वरूप पुनर्विचार किए बिना एक संचार समायोजन विकसित कर सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें बहुपक्षवाद को मजबूत करना शामिल होगा। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य की भूमिका अधिक होगी, यद्यपि साथ ही, जब यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश करता है तो यह प्रतिभूतिकरण और निजता की निगरानी के लिए अधिक चौकस होगा। बाजार से हम बौद्धिक संपदा के संरक्षण में बदलाव किए बिना, अधिक वाणिज्यिक सरंक्षणवाद और सार्वजनिक निवेशय डिजिटलाइजेशन की गहनता, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद कर सकते हैं। और, कुछ हद तक, शुद्ध वित्तीयकरण के बजाय उत्पादक अर्थव्यवस्था और तथाकथित आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की वसूली होगी। हालांकि कम तीव्रता वाले लोकतंत्र के ढांचे के भीतर, नागरिक समाज, जिम्मेदार उपभोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहायकता और आत्म–देखभाल को बढ़ावा दिया जाएगा और सतत विकास पर ध्यान दिया जायेगा।

> सामूहिक सीख

अधिक परिवर्तनकारी क्षमता के साथ एक अधिक उपेक्षा वाली प्रतिक्रिया का तात्पर्य एक गहन सामूहिक सीखने की प्रक्रिया से है, जिसके लिए समझौता वार्ता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्रम से परे वैश्विक शासन की जगहों पर जाने की आवश्यकता है जो सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान और संरक्षण जोखिम में कमी और आपदाओं की रोकथाम पर केंद्रित हो। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे राज्य में परिलक्षित होता है जो अपनी सार्वजनिक नीतियों को देखभाल की धारणा और सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच में असमानताओं को कम करने के इर्द–गिर्द अपनी सार्वजनिक नीतियों को केंद्रित करता है। उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में, कम दूरी के रसद और स्थानीय व्यापार तथा उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा, साथ ही छोटे शहरों और आवश्यक गतिविधियों के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाये; अंतिम परंतु कमतर नहीं, महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा और पेटेंट पर वर्तमान उत्तर–दक्षिण विवाद अधिक समान और समावेशी शासन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नागरिक समाज का तेजी से ''अभियोक्ताओं'' (जे. रिफकिन) के एक नेटवर्क के रूप में गठन किया जाएगा, जहां भूस्थानीयकरण उभरेगा और लैंगिक अंतर के प्रति संवेदनशील देखभाल संबंधी नेटवर्कों का विस्तार होगा; परिवर्तनशीलता के लिए स्थान खोले जाएंगे जो राजनीतिकरण की प्रक्रिया जो समानता और पहुंच के मामले में मौलिक लोकतंत्रिकरण के लिए जिम्मेदार हैं, में पश्च–विकास और डी–ग्रोथ जैसे वैकल्पिक विचारों से प्रेरित होंगे।

इनमें से किस विकल्प में अधिक संभावनाएं हैं और इनके होने में यह किस पर निर्भर है? हम पहले से ही गैर–परिवर्तनकारी प्रतिक्रिया की सीमाओं से अवगत हैं और इससे बहुत कम उम्मीद की जा सकती है। हालाँकि, इस पर विचार करने की सम्भावना हमेशा है और इसके अनुयायी भी हैं। पूंजीवाद और और आधुनिकता ने अनुकूलन और नवीनीकरण के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करी है। यहां तक कि उन्होंने उनके लिए व्यक्त अतिवादी आलोचनाओं को भी समावेशित किया है (जैसा कि द न्यू स्पिरिट ऑफ कैपिटलइस्म में बोल्तान्स्की और चियापैलो द्वारा प्रदर्शित किया गया है)। इसलिए, यह सोचना अनुचित नहीं है कि अनुकूलन प्रक्रिया सबसे अधिक संभावित विकल्प है, और यह लगभग यांत्रिक रूप से विशेषज्ञ प्रणालियों, बड़े निगमों (विशेषकर डिजिटलीकरण से जुड़े लोगों) और अल्पावधि में सोचने वाले राजनीतिक अभिनेताओं के बीच बातचीत से उत्पन्न होगा। इस बीच, सबसे अधिक मांग वाली सामूहिक सीख, सामाजिक आंदोलनों और लोकप्रिय संगठनों के आमूल परिवर्तन और सक्रियण पर निर्भर करती है, जो एक वैश्विक ग्रीन न्यू डील के लक्ष्य के लिए सहायता और स्वास्थ्य जोखिमों की एक महान योजना अथवा उससे भी आगे, बेहतर दक्षिण की पारिस्थितिक सामाजिक संधि, जिसमें उत्तर–दक्षिण संवाद में सामाजिक न्याय को हमेशा पर्यावरणीय न्याय के साथ रखा जाता है तथा जिसमें,एक बार के लिए, उत्पादक कार्य की केंद्रीयता को जीवन की प्रधानता से बदल दिया जाता है, से परे जाती है। निसंदेह, यह विकल्प सबसे कम संभावित है। परंतु दाव के आलोक में, यह सबसे आवश्यक और त्वरित है। ■

सभी पत्राचार एलेजांद्रो पेल्फिनी को
<pelfini.alejandro@usal.edu.ar> पर प्रेषित करें।

> नागरिक–राजनीतिक क्षेत्र में समाजशास्त्री

फ्रेडी एल्डो मैसेडो हुआमन, यूनिवर्सिडैड इबेरोअमेरिकाना (आईबीईआरओ), मैक्सिको सिटी, मैक्सिको द्वारा

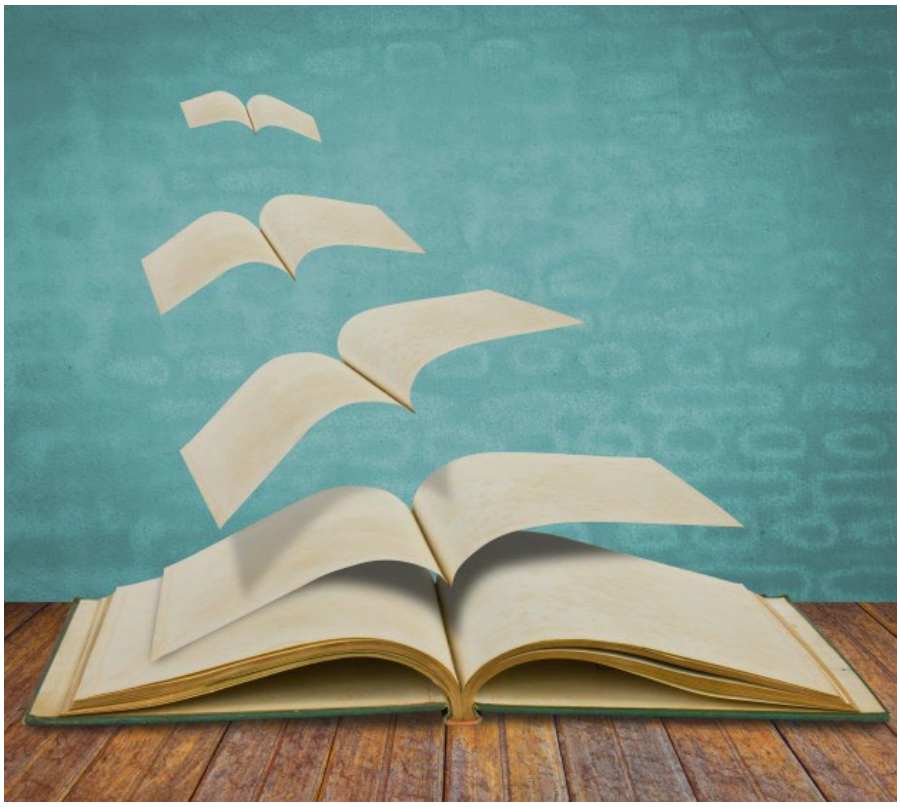

साभारः क्रिएटिव कॉमन्स।

प्रारम्भ से ही, समाजशास्त्री अपने समाजों के सार्वजनिक मामलों में सम्मिलित थे (उदाहरण के लिए, एमिल दुर्खीम, मैक्स वेबर, मैरिएन श्नाइटर और जेन एडम्स), चाहे वह व्यापक समुदाय को असमानता, भेदभाव और दुख की स्थितियों के बारे में चेतावनी देना था, और साथ ही साथ अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग, अधिकारों का कुचला जाना, और समाज के बड़े वर्गों द्वारा झेली गई सार्वजनिक सेवाओं की सरकार की उपेक्षा, या सुविज्ञ सार्वजनिक बहस को प्रेरित करना। समाजशास्त्री सुलभ और उत्तेजक भाषा को अपना कर प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों के साथ संलग्न होते हैं। ऐसा वे अपने विवेचनात्मक स्वभाव और अन्वेषी कार्य को छोड़े बिना विवेक को झिंझोड़ कर और शक्ति पर प्रश्न खड़े कर के करते हैं। हाल ही में, एक समाजशास्त्री प्रोफाइल जो यहां व्यक्त किए गए प्रतिबिंबों के साथ अच्छी तरह से फिट बैठती है, वह हेलेन जेफरसन लेन्स्कीज की है। अपने शोध के सम्बन्ध में सार्वजनिक बुद्धिजीवियों के रूप में शिक्षाविदों की भूमिका की विशेषता का निरूपण करते हुए हेलेन कहती हैंः वे ''ओलंपिक के हानिकारक प्रभावों जैसी सामाजिक समस्याओं से झूझते हैं, उनकी उत्पत्ति और उनको समर्थन देने वाली उत्पीड़न प्रणालियों को उजागर करना चाहते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन के लिए सिफारिशें करते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देने के लिए समुदायों के साथ काम करते हैं, कभी सफलतापूर्वक और कभी नहीं। हमारे लक्ष्य अक्सर 'पवित्र गाय' होते हैं – उदाहरण के लिए ओलंपिक या संगठित धर्म, (और इनमें अतिच्छादन होता है)– और हमारे निष्कर्ष अक्सर प्रदर्शित करते हैं कि 'सम्राट के पास कपड़े नहीं हैं'।

एक उपद्रवी और अनिश्चित युग के समक्ष, आज बहुत बेचैन, हतप्रभ लेकिन रचनात्मक सामाजिक वैज्ञानिकों की पीढ़ी भी है। अपनी विषयगत विरासत को ध्यान में रखते हुए, वे अपने साथी नागरिकों और समुदायों के दैनिक जीवन के प्रति संवेदनशील हैं, ताकि वे वर्तमान क्षण का सामना करने के लिए अभिनव और चिंतनशील फ्रेमवर्क तैयार कर सकें। मेरे विचार में, इसने डेविड एम फैरेल और जेन सूटर को अपनी रीइमेजिनिंग डेमोक्रेसी (2019) में खुद को आयरिश समाज में तल्लीन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसके नागरिकों के बीच एक विचारशील लोकतंत्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनका काम आयरलैंड में नागरिकों की सभाओं को जनता के ध्यान में लाया, जो जनमत संग्रह के लिए वाहक के रूप में कार्य करती थी जिसके कारण सभी के लिए गर्भपात और विवाह को वैध बनाना पड़ा।[1] इस प्रकार, अकादमिक जगत में जो सिद्धांत उभरता है, उसे सामाजिक रूप से पोषित किया जाता है, जहाँ उत्तेजक प्रश्नों और मुद्दों के अलावा कर्ताओं के साथ संबंधों का पता लगाया जाता है, और सार्वजनिक संस्थानों और संस्कृतियों के नए स्वरूप के लिए संवाद की अनुमति देता है।

यदि दैनिक स्तर पर कई कर्ता अपने राजनीतिक समुदाय के

> >

महत्वपूर्ण मुद्दों में सम्मिलित होने के लिए एकजुट होते हैं – अपने हितों को बढ़ावा देने और अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए, अपने सीखने, सहयोग और संगठनात्मक मॉडल, चैनल पहलें और कार्रवाई कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए, शक्ति के स्थानों का निर्माण करना चाहते हैं जो सहभागी चैनलों और लोकतांत्रिक नवाचारों को सम्मिलित करें– समाजशास्त्रियों और उनके पक्ष में अन्य पेशेवरों के समूह भी हैं जो उनका समर्थन और प्रचार करने के इच्छुक हैं।

> समाजशास्त्रियों के लिए नई भूमिकाएँ

इस प्रकार, अकादमिक दुनिया और नागरिक–राजनीतिक क्षेत्र के बीच, नागरिक एजेंसी में योगदान देने की दृष्टि से समाजशास्त्री समकालीन लोकतंत्रों में कार्रवाई के क्षेत्रों की बहुलता में विभिन्न प्रोफाइल ग्रहण कर सकते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समाजशास्त्रियों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन में क्या योगदान, भागीदारी और पुनर्विचार पर विचार किया जा सकता है?

सामान्य तौर पर, पारंपरिक शैक्षणिक–पेशेवर विभाजन अधिक जटिलता एवं अंतर्वेधन और क्षेत्रों और कर्त्ताओं की प्रणालियों के विविधीकरण की वर्तमान स्थिति से बहुत आगे निकल गया है। ये विशेषताएं उन स्थितियों में उभर रही हैं जो अभी भी विचार विमर्श के लायक होंगी।

सैद्धांतिक रूप से समाजशास्त्रियों के लिए, इन जटिलताओं का प्रत्युत्तर देने से– उनके विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र नागरिक और राजनीतिक कर्ताओं के लिए, उनकी जरूरतों, सीमाओं, क्षमता और सामान्य ढांचे को ध्यान में रखते हुए, अधिक प्रासंगिक बनते हैं । दूसरे, इन बदलते क्षेत्रों में समाजशास्त्रियों के अनुभव से यह संभव हो सकेगा कि जो पहले से मौजूद है, उसके आलोक में जो योजना बनाई गई है, उसका दायरा और परिष्कृत करना, सबक लेना और इस प्रकार नागरिकों के उद्देश्य से उचित शैक्षिक नवाचार और विशेषज्ञता को बढ़ावा देना।

लोकतांत्रिक राजनीति और नागरिक व्यवहार के स्तर पर, एक नागरिक सलाहकार–मध्यस्थ के रूप में समाजशास्त्री के व्यक्तित्व के बारे में सोचना विचार योग्य है।

नागरिक क्षेत्रों के साथ जुड़कर, समाजशास्त्रियों को महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक–संचालन क्षमताओं के आधार पर दृष्टि और कार्यक्षमता को बढ़ावा देना होगा, और रचनात्मक, शैक्षणिक, संवादात्मक, प्रस्तावक और भावनात्मक कौशल के साथ–साथ परिभाषित, लामबंद और लचीलेपन के स्व–परिभाषा के तरीकों, जो नागरिक और राजनैतिक कर्त्ताओं की भूमिका निभाने वालों का समर्थन (या सह–उत्पादन) करेंगे, को उत्तेजित करना होगा। इसके अनुरूप, लोकतांत्रिक जीवन के प्रमुख मूल्यों (न्याय, स्वतंत्रता, बहुलवाद, सहिष्णुता, एकजुटता, आलोचना और असहमति, सुनना और सहयोग) पर आधारित नैतिकता के प्रति समाजशास्त्रियों की प्रतिबद्धता उनकी भागीदारी की एक मार्गदर्शक धुरी का गठन करती है।

अधिक विशिष्ट अर्थों में, इन नए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के उद्भव के लिए पूर्व शर्तें यह बताती हैं कि वे इसके लिए ग्रहणशील होंगे:

- संगठनात्मक विकास की उनकी आंतरिक (या साझा) प्रक्रिया में बेहतर तत्वों, कौशल और अनुभवों का अधिग्रहण, जिसका अर्थ है कि विभिन्न पैमानों पर खुद को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करना,
- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में एक लक्षित और निरंतर प्रगति और उनकी पहचान के लिए प्रमुख आदर्शों का ठोसकरण (लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के अनुसार),
- नागरिक लॉबिंग के एक मंच ग्रहण करने का कार्य, जिसका उद्देश्य उनके प्रभाव के अंतर्गत नीतियों और उसके आगे के पुनर्गठन के लिए एक योजना बनाना है; तथा
- राज्य और नागरिकों को जोड़ने के समावेशी और नवोन्मेषी तरीकों की दिशा में कठोर संस्थागत ढांचे को पुनर्निर्देशित करते हुए, विभिन्न क्षेत्रों में अपने लोकतांत्रिक व्यवहार (अन्य सामाजिक एजेंटों और विशेषज्ञों से जुड़े) के माध्यम से उनके योगदान का स्पष्टीकरण।

समाजशास्त्रियों के मामले में, इस प्रकार के कार्य के लिए प्रासंगिक और प्रमुख भूमिकाएँ विशिष्ट हैं, वे इस रूप में कार्य करेंगी:

- अधिक महत्व के संचार, सांस्कृतिक और राजनीतिक परियोजनाओं में उनके पुनः प्रसंस्करण के लिए प्रवचनों, कथाओं और कल्पनाओं के डिकोडर,
- संगठनों के भीतर या बाहर निहित संघर्ष और तनाव के मध्यस्थ,
- सार्वजनिक और निजी शक्तियों के खिलाफ राजनीतिक, नागरिक और सार्वजनिक कार्रवाई की प्रक्रियाओं के साथी और अनुवादक, तथा
- एक नागरिक, लोकतांत्रिक, और सार्वजनिक नीति के दायरे की परियोजनाओं के सवाक (या सह– जन्मदाता) जिन्हें उनके साथ काम करने वाले नागरिक समूहों द्वारा अपनाया जाएगा।

संक्षेप में, आज के प्रबल दो गंभीर खतरों के बीच स्थित है जो आज प्रबल हैं– चरम दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद और तकनीकी निगमों की विशाल शक्ति (सरकारी निगरानी प्रणालियों से जुड़ी) – के मध्य स्थित स्पष्टता और सक्रिय अभिविन्यास से अपनी लोकतांत्रिक आवाज और शासन की क्षमताओं, जो उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनायेंगी, दोनो को व्यक्त करते हुए जवाब देने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, लोकतांत्रिक परियोजना को नवीनीकृत करने की अत्यधिक आवश्यकता के साथ, वे अपने राजनीतिक ज्ञान, ज्ञान के एकीकरण, नागरिक मित्रता और संगठनात्मक अभिविन्यास पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की तलाश करेंगे। और इसके साथ–साथ, उन्हें समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और नृविज्ञान जैसे विषयों के चिकित्सकों सहित अन्य अभिनेताओं के साथ पुल बनाने की आवश्यकता होगी, जिन्हें अधिक ऊर्जावान और मुखर आवेग के साथ एक तर्कपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के संयोजन से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ■

सभी पत्राचार फ्रेडी एल्डो मैसेडो हुआमैन को <fredy.macedo@gmail.com> पर प्रेषित करें।

1. देखें https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/irish-referendums-deliberative-assemblies/.

> त्रिनिदाद और टोबैगो में अंतरंग साथी हिंसा के आसपास चुप्पी

अमांडा चिन पैंग, वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय, सेंट ऑगस्टीन, त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा

त्रिनिदाद और टोबैगो (टी एंड टी) में, जब अंतरंग साथी हिंसा (आईपीवी) या गिरोह से संबंधित युद्ध में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की मौत हो जाती है, तो इस पर तत्काल ध्यान दिया जाता है। हालांकि, तुरंत ही, पीड़ित और बचने वालों की चीखें शांत हो जाती हैं और अपराधी अपनी हिंसा के बारे में घिसे–पिटे बहानों को सामने रख, निरंतर दुर्व्यवहार का एक आसन्न विनाश छोड़ जाते हैं।

त्रिनिदाद और टोबैगो में, अंतरंग साथी हिंसा (आईपीवी) और लिंग आधारित हिंसा की स्थितियों में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की हत्या होने पर लंबे समय से चुप्पी रही है। एक महिला, एंड्रिया भरत की मौत, एक आशावादी उत्प्रेरक है जो पीड़ितों और दुर्व्यवहार और हिंसा से पीड़ित और उससे बचने वालों लोगों के रोने को शांत करती है।

> हिंसा की संस्कृति

कोविड–19 के ''स्टे–एट–होम'' उपायों के आह्वान के बाद से, घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है– घरेलू हिंसा को कभी–कभी आईपीवी के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इनमें से कई घरेलू हिंसा के रूप में वर्णित मामले वास्तव में वयस्क अंतरंग साथी के मध्य होते हैं।

पीड़ितों की चुप्पी और अनवरत हिंसा से बचने के अवसरों के आभाव ने मुझे हिंसा की संस्कृति जो ट्रिनबागोनियन लोगों में गहराई से निहित है, के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। इन स्थितियों से वाकिफ होने पर दोस्तों और रिश्तेदारों के मुंह पर ताले लग जाते हैं। मैं हिंसा पर चुप्पी तोड़ने का आह्वान करती हूं जिसकी जड़ें गहरी औपनिवेशिक हैं। बर्गनर (1995) की ''हू इज दैट मास्क्ड वुमन? में या, फैनॉन की *ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क* में जेंडर की भूमिका'' के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डालती है, न केवल प्रणालीगत नस्लवाद, बल्कि पुरुषों के अधीन महिलाओं की वंचित स्थिति भी। अंतरंग भागीदारों और उनके आश्रितों पर इसके गंभीर प्रभाव के बावजूद, आईपीवी पर प्रत्यक्ष नीतियों और अनुसंधान का अभाव, मुझे यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कुछ कैरिबियाई लोग हिंसा के इस पैटर्न के साथ बहुत सहज हैं। मैं इसे ''हिंसा की संस्कृति'' कहती हूं, जैसा कि ब्रेरेटन (2010) द्वारा ''त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंसा की संस्कृति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि'' में वर्णित है, क्योंकि यह देश में सामान्य माना जाता है।

> हिंसा का सामान्यीकरण

हम इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं। अंतरंग साथी संबंधों में हिंसा कैरिबियन अंतर्क्रिया में सामान्य के रूप में प्रकट होती है। त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे छोटे जुड़वां द्वीप गणराज्य के भीतर हिंसा के सामान्य होने का क्या कारण है? क्या यह रिश्ते की कठिनाइयों का सामना करने में असमर्थता हो सकती है, या ऐसा है कि यह हिंसा अंतरंग भागीदारों, या दोनों को स्वीकार्य है? टी एंड टी संस्कृति के बारे में ऐसा क्या है जो इस हिंसा को कम या बिना किसी सार्वजनिक विरोध के सहज बनाता है और इसे अनदेखा करता है? क्या आईपीवी को रिश्तों के भीतर एक निजी मुद्दा माना जाता है? क्या पुरुष और महिलाएं डरते हैं?

वैश्विक स्तर पर, कई जोड़ों के बीच आईपीवी प्रचलित है। डब्ल्यूएचओ की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा फैक्टशीट के आंकड़ों के अनुसार, तीन में से एक महिला को अंतरंग संबंध में आईपीवी का अनुभव होगा और दुनिया भर में महिलाओं की 38% हत्याएं पुरुष अंतरंग साथी (डब्ल्यूएचओ, 2017) द्वारा की जाती हैं। जहाँ ये आंकड़े पुरुष हिंसा को महिला अंतरंग साथी के खिलाफ दर्शाते हैं, पुरुषों के खिलाफ महिलाओं द्वारा अंतरंग साथी हिंसा, साथ ही समान–सेक्स संबंधों के भीतर भी आईपीवी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की घरेलू हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन (एनसीएडीवी, 2020) में कहा गया है कि प्रत्येक नौ पुरुषों में से एक ने आईपीवी के किसी न किसी रूप, यौन संपर्क हिंसा, और पीछा का अनुभव किया है। । इसके अलावा, इस रिपोर्ट के अनुसार, पुरुष बलात्कार पीड़ितों और अवांछित यौन संपर्क के पुरुष पीड़ितों ने मुख्य रूप से पुरुष अपराधियों की सूचना दी है। यह त्रिनिदाद और टोबैगो में एक समान स्थिति को दर्शाता है। "इंटरपर्सनल वायलेंस इन थ्री कॅरीबीयन कन्ट्रीजः बारबाडोस, जमैका, एंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो" में ले फ्रैंक एट अल (2008) त्रिनिदाद और टोबैगो में शारीरिक और यौन हिंसा की रिपोर्टिंग पर साक्ष्य प्रदान करते हैं, जिसमें पाया गया कि 47.7% पुरुषों ने संबंधों के भीतर शारीरिक हिंसा का अनुभव किया और 52.5% पुरुषों ने संबंधों के मध्य यौन जबरदस्ती का अनुभव किया।

दिलचस्प बात यह है कि, "यूथ मस्क्युलिनीटीएस एंड वायलेंस इन द कॅरीबीयन'' में विल्टशायर (2012) के अनुसार, मर्दानगी पीढ़ियों, धर्म, स्कूल, मीडिया और दोस्तों में पारिवारिक समाजीकरण द्वारा प्रबलित शक्ति के माध्यम से सीखी जाती है। इसके अलावा, विल्टशायर उल्लेख करते हैं कि मर्दानगी हिंसा और आक्रामकता के कृत्यों के माध्यम से व्यक्त की जाती है और कुछ पुरुष सोचते हैं कि महिलाओं को कभी–कभी अपने पुरुष भागीदारों द्वारा अनुशासित करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि पुरुष और महिला दोनों अंतरंग साथी हिंसा के अपराधी हैं, टी एंड टी में समाचार रिपोर्ट महिलाओं की अपने अतरंग जोड़ीदारों द्वारा मारे जाने की घटनाओं से भरी हुई हैं। इसका कारण यह है कि पुरुषों पर इन कृत्यों को अंजाम देने वाली महिलाओं के अनुपात की तुलना में महिलाओं के खिलाफ आईपीवी करने वाले पुरुषों का एक अधिक बड़ा अनुपात है।

पुरुषों और महिलाओं द्वारा साझा की गई मर्दानगी और स्त्रीत्व की धारणाएं अंतरंग संबंधों में पुरुष हिंसा की अनिवार्यता और इस मुद्दे

> >

''इस हिंसा के खिलाफ बोलने को आदर्श बनाने और स्वयं की अभिव्यक्ति और रिश्तों के भीतर हिंसा को अस्वीकार्य और असंगत के रूप में समझने से चुप्पी टूट जाएगी और अंततः अंतरंग साथी संबंधों को बेहतर के लिए बदल देगी।''

पर स्वीकृति और चुप्पी को दर्शाती हैं। इसके अलावा, इस दुर्व्यवहार को जब वे कैरेबियन सम्मान की अपेक्षाओं की सीमाओं को पार करती हैं, महिलाओं को ''सम्मानजनक नहीं'' के रूप में लेबल करके वैध किया जाता है। यद्यपि, महिलाओं की अपनी कामुकता और स्त्रीत्व की अभिव्यक्ति पर पुरुषों के विचार निश्चित रूप से दुर्व्यवहार का कोई बहाना नहीं हैं।

> आईपीवी को संबोधित करने में बाधा के रूप में चुप्पी

यह उल्लेखनीय है कि चुप्पी तोड़ने और पीड़ितों को आवाज देने की कोशिश की जा रही है. त्रिनिदाद और टोबैगो चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (TTCIC) की घरेलू हिंसा कार्यस्थल नीति (2018) और त्रिनिदाद और टोबैगो पुलिस सेवा (TTPS) की लिंग–आधारित हिंसा इकाई आईपीवी के मुद्दों को संबोधित करने वाली नीतियां हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्पॉटलाइट इनिशिएटिव कोविड–19 के कारण घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों को उजागर कर रही है। इन पहलों के बावजूद, हिंसा की संस्कृति और टी एंड टी में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की धारणाएं देश में हिंसा की संस्कृति की सामान्य स्वीकृति को दर्शाती हैं।

सुरक्षा और समर्थन तंत्र के माध्यम से आईपीवी सर्वाइवरस को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना, जोड़ों और वे अपराधी जो इंकार नहीं करते हैं के लिए उपचारात्मक विकल्प, पुरुषों और महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और मदद मांगने के लिए पुरुषों का आह्वान करना हिंसा पर चुप्पी की संस्कृति को एक ऐसी संस्कृति में सकारात्मक रूप से बदल सकता है जो हिंसा के खिलाफ बोलती है और सार्वजनिक रूप से हिंसा को अस्वीकार करती है।

इसके अलावा, कामुकता और लिंग भूमिकाओं की अभिव्यक्ति में पुरुषों और महिलाओं का पुनर्समाजीकरण आवश्यक है। मेरा मानना है कि आईपीवी से जुड़ी शर्म और डर पीड़ित के लिए और यहां तक कि अपराधी के लिए भी, और एक सर्वाइवर की अपने उत्पीड़न के लिए जिम्मेदारी की झूठी भावना, हिंसा पर इस चुप्पी की ओर ले जाती है। वैलेस (2019) की "डोमेस्टिक वायलेंसः इंटिमेट पार्टनर वायलेंस विक्टिमाइजेशन नॉन–रिपोर्टिंग टू द पुलिस इन त्रिनिदाद एंड टोबैगो" के अनुसार, इस प्रकार शर्मिंदगी/शर्म पुरुष और महिला पीड़ितों के लिए पुलिस को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने में एक मुख्य बाधा थी। कारण के बावजूद, प्रतिक्रिया चुप्पी है, जो अक्सर हत्या में समाप्त होती है।

इस हिंसा के खिलाफ बोलने को आदर्श बनाने और स्वयं की अभिव्यक्ति और रिश्तों के भीतर हिंसा को अस्वीकार्य और असंगत के रूप में समझने से चुप्पी टूट जाएगी और अंततः अंतरंग साथी संबंधों को बेहतर के लिए बदल देगी। ■

सभी पत्राचार को अमांडा चिन पैंग <amandalall91@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> विश्व की देखभाल करने की क्षमता पर

फ्रांसेस्को लारुफा, जिनेवा विश्वविद्यालय, स्विटजरलैंड द्वारा

व्यक्तियों को ''एजेंट'' के रूप में माना जाना चाहिए जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सह–निर्णय लेते हैं। सात वर्षीय मतिओ लारूफा द्वारा आरेखण।

कोविड–19 महामारी ने 'कोरोना के बाद का विश्व' और ''जो भविष्य हम चाहते हैं'' पर आधारित कई चर्चाओं को पोषित किया है। विचार यह है कि यह महामारी न केवल नवउदारवादी पूंजीवाद और उसमें अंतर्निहित प्रकृति के अतिदोहन (वनों की कटाई आदि) का एक दुखद परिणाम है: बल्कि यह महामारी हमारे समाज और इसे संचालित करने के विभिन्न तरीकों पर भी पुनर्विचार करने का एक अवसर प्रदान करती है। हालाँकि यहाँ कल्पित भविष्य पर कोई सहमति होने जैसी बात नहीं है. कुछ लोग 'समावेशी हरित विकास' और 'हरित रोजगार' को बढ़ावा देने के लक्ष्य से हरित समझौतों (ग्रीन डील) पर बल देते हैं। यहाँ पर लोगों की जीवन शैली (जैसे उपभोक्तावाद) या पूंजीवादी ढाँचे (जैसे नियोक्ता और श्रमिकों की मध्य शक्ति की असमानता) को परिवर्तित किये बिना पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए तकनीकी नवाचारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके बजाय अन्य एक अधिक गहन 'सामाजिक पारिस्थितिक परिवर्तन' की आकांक्षा रखते हैं, जहां अर्थव्यवस्था लाभ की बजाय सामाजिक और पारिस्थितिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधीन है।

निम्नलिखित में, मैं अमर्त्य सेन और मार्था नुस्बॉम के 'क्षमता दृष्टिकोण' की एक अतिवादी व्याख्या को प्रस्तावित करता हूँ। यह व्याख्या इस बात का अन्वेषण करती है कि यह हमें अधिक मुक्त और टिकाऊ भविष्य की कल्पना में कैसे सहायता कर सकती है। स्पष्ट रूप से, एक मूल्यवान भविष्य का चित्रण करना समाजशास्त्र या (दर्शनशास्त्र) का अनन्य कार्य नहीं हो सकता है: भविष्य का लोकतान्त्रिक तरीके से सह–निर्माण करना आवश्यक है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी हो सके। मेरा तर्क है कि क्षमता दृष्टिकोण ''जो भविष्य हम चाहते हैं'' के सम्बन्ध में लोकतान्त्रिक परिपेक्ष्य की अनुमति देता है।

> क्षमताओं की एक अतिवादी व्याख्या

क्षमता दृष्टिकोण सुझाता है कि सार्वजनिक कार्यवाही लोगों की क्षमताओं को बढाने पर केंद्रित होनी चाहिए यानी उनके मूल्यवान जीवन को जीने की वास्तविक स्वतंत्रता। इस परिपेक्ष्य में, सामाजिक विकास की तुलना आर्थिक वृद्धि से नहीं की जा सकती बल्कि इसे मनुष्य के विकास में आने वाली बाधाओं के निस्तारण के साथ जोड़ा जाता है: सार्वजनिक नीतियों को मूल्यवान 'प्राणियों' और 'कार्यों' की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार करना चाहिए,

> >

यानी कि 'अच्छे जीवन' की तर्कपूर्ण धरणा को आगे बढ़ाने के लिए। यह फोकस हमें, इस पर बहस करते हुए कि आतंरिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, अंतिम छोर के सन्दर्भ में चिंतन करने के लिए मजबूर करता है। क्षमता दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। लोकतान्त्रिक भागीदारी का न केवल एक यांत्रिक प्रकार्य है (नागरिक को अपनी आवाज को सुनाने की अनुमति देना ताकि सार्वजनिक कार्यवाई उनके हितों को बेहतर तरीके से प्रतिबिम्बित कर सके)बल्कि एक रचनात्मक भूमिका भी है जो सामाजिक प्राथमिकताओं को आकार देती है और चूँकि अच्छे जीवन की अवधारणाएँ विचार–विमर्श की प्रक्रियाओं के दौरान परिवर्तित हो जाती हैं, यहाँ तक – वे व्यक्तिगत मूल्यों को भी आकारित करती हैं।

इस आधार पर मेरा तर्क है कि क्षमता दृष्टिकोण को नीतिगत चक्रों में हावी की तुलना में अधिक अतिवादी तरीके से आकारित किया जा सकता है। वास्तव में क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि के मध्य की कड़ी पर अधिक गहराई से प्रश्न उठाये जा सकते हैं। क्षमता दृष्टिकोण की प्रमुख व्याख्या इस बात पर प्रकाश डालती है कि वृद्धि अपने आप में लक्ष्य नहीं है बल्कि यह मूल्यवान लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। फिर भी, पर्यावरण पर इसके विनाशकारी परिणामों और मानव कल्याण पर बहुत कमजोर प्रभावों को देखते हुए आर्थिक वृद्धि एक उचित साधन का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती है और सार्वजनिक करवाई को यह लक्ष्य पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। कई मामलों में अर्थव्यवस्था मानव पीड़ा और पर्यावरणीय आपदा के *माध्यम* से बढ़ती है: निर्माण उद्योग के आर्थिक विकास में भूकम्प का आर्थिक वृद्धि का इंजन बनने से लेकर उत्पादन–जनित प्रदूषण से बीमारियाँ ट्रिगर हुई। यहाँ तक कि जो *पहली नजर* में सकारात्मक दिखता है वह वास्तव में निराशाजनक है। उदाहरण के लिए, समृद्धि एक अच्छे जीवन को प्राप्त करने की अर्जनशील–भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धी– व्यक्तिवादी दृष्टि को प्रोत्साहित करती है जो अंततः मानव–कल्याण को कमजोर करती है। इस तरह से पाश्चात्य जीवन शैली न केवल अवहनीय है: 'विकास' के इस वृद्धि आधारित मॉडल की वांछनीयता अपने आप में मानव कल्याण के नजरिए से प्रश्नयोग्य है. इसी तरह, नीति जगत में क्षमता दृष्टिकोण का व्यक्ति को एक 'एजेंट' के रूप में मानने का केन्द्रीय विचार बहुत प्रभावशाली हो गया है। फिर भी, लोगों को एक संकीर्ण अर्थ में एजेंट के रूप में माना जाता है अर्थात वे आर्थिक एजेंट जो बाजारों में भागीदारी करते हैं। इसके बजाय सामाजिक परिवर्तन की दिशा पर सह–निर्णय लेने वाले लोकतान्त्रिक नागरिकों की संख्या हाशिये पर है। इस संदर्भ में, क्षमता दृष्टिकोण 'सशक्तिकरण' की नवउदार–व्यक्तिकेंद्रित व्याख्या में सहयोजित होता है जो मानव स्वतंत्रता को अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से, श्रम बाजारों में भागीदारी तक सीमित कर देता है। क्षमता मानव पूँजी का पर्याय बन गई है: कौशल का वह समूह जो एक व्यक्तियों को सफल आर्थिक कर्त्ता बनाने के लिए जरूरी है।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक कार्रवाई के लिए वांछनीय लक्ष्य के रूप में आर्थिक विकास और लोगों के समावेश दोनों को अस्वीकार करते हुए क्षमता दृष्टिकोण की एक अतिवादी व्याख्या का तात्पर्य नागरिकों को सामाजिक परिवर्तन की दिशा, विकास, प्रगति के अर्थ पर विमर्श, प्रगति बहस और अंतिम लक्ष्य के रूप में जीवन की गुणवत्ता को सह–निर्धारण करने की शक्ति देनी होगी। इस तरह की समझ हमारे सामूहिक भाग्य को आकार देने में बाजारों के प्रभावों को कम करने पर बल देती है, (आंशिक रूप से) उन्हें सहभागी–विचारशील लोकतंत्र के साथ में बदल देती है।

> 'विश्व की देखभाल करने की क्षमता' पर सार्वजनिक कार्रवाई को केन्द्रित करना

इस बिंदु पर, क्षमता दृष्टिकोण को नारीवादी सिद्धान्कारों द्वारा विकसित ''देखभाल की नैतिकता'' के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसा कि जोन ट्रोंटो सुझाती हैं, देखभाल का दृष्टिकोण समाज के रूप में हम किसकी परवाह करते हैं, को रेखांकित करता है। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो लाभ की देखभाल पर आधारित है और व्यक्तियों को लाभ में उनके योगदान के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें अन्य लोगों (जैसे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार), पर्यावरण के लिए (पर्यावरण संरक्षण/रखरखाव और पर्यावरण सुधार दोनों के रूप में), लोकतान्त्रिक संस्थानों के लिए और स्वयं के लिए (खेल, कला, शिक्षा आदि) देखभाल को मुनाफे पर प्राथमिकता दी जाती है ।

इस दृष्टिकोण से पुरस्कार उत्पादन से सामाजिक पुनरुत्पादन में स्थानांतरित हो सकते हैं और कार्य को *विश्व की देखभाल करने* की प्रमुख गतिविधि के रूप में पुनःसंकल्पित किया जा सकता है। परवर्ती के अर्थ को लोकतान्त्रिक विचार–विमर्श से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से समाज में मूल्यवान योगदान क्या है को स्थापित करने में लोकतंत्र (आंशिक रूप से) बाजार को प्रतिस्थापित कर देता है। बाजार मूल्य के बजाय ''सामाजिक उपयोगिता'' पर आधारित कार्य की इस समझ ने महामारी के दौरान अति–आवश्यक कामगारों पर चर्चा के प्रमुखता प्राप्त की है। इस ढांचे का अनुगमन करने वाला एजेंडा पूंजीवादी समाजों के ग्रीन या अन्य *'अर्थहीन रोजगारों'* (डेविड ग्रैबर) के प्रसार का विरोध करेगा और सार्थक कार्यों के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ावा देगा। परवर्ती में श्रम बाजार के भीतर या बाहर दोनों जगह ही समपन्न होने वाली एक गतिविधि सम्मिलित है जो इन्हें पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिए मानव उत्कर्ष के अवसर प्रदान करती है और जो समाज में ''निष्पक्षता'' से मूल्यवान योगदान देती है। क्या महत्पूर्ण है, इस पर सभी नागरिक लोकतान्त्रिक बहस में भागीदारी निभाने के लिए बराबर के हकदार हैं। (रूथ यमन)

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि एक बार पूंजीवाद के बारे में इसकी आलोचनात्मक दृष्टि के और अधिक स्पष्ट होने के बाद क्षमता दृष्टिकोण प्रगतिशील लोगों को प्रेरित कर सकता है जो जो आर्थिक वृद्धि पर नहीं या सार्वजनिक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने या श्रम बाजार में लोगों को सम्मिलित करने का सुझाव न दें बल्कि ''दुनिया की देखभाल करने की क्षमता'' को प्रोत्साहित करें–जिसमें देखभाल योग्य क्या है पर बहस में भाग लेने का अधिकार भी सम्मिलित है। ■

सभी पत्राचार फ्रांसेस्को लारुफा को <Francesco.Laruffa@unige.ch> पर प्रेषित करें।

> होमो कल्चरस के रूप में मनुष्य

महमूद धौदी, ट्युनिस विश्वविद्यालय, ट्यूनीसिया और आईएसए की समाजशास्त्र के इतिहास (आरसी 08), धर्म के समाजशास्त्र (आरसी 22) और भाषा और समाज (आरसी 25) की शोध समितियों के सदस्य द्वारा

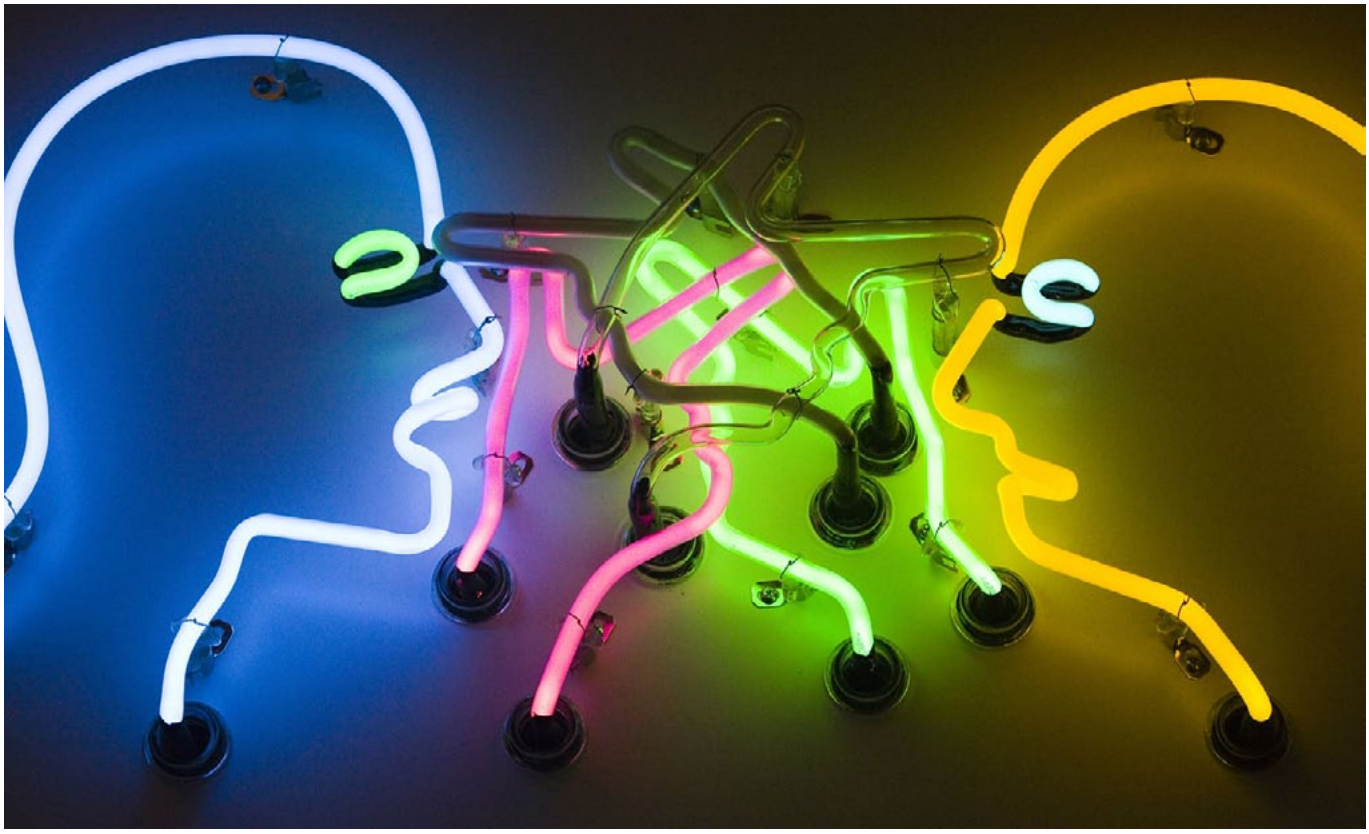

मनुष्य न केवल बोलने वाले जानवर हैं बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रतीकों के उपयोगकर्ता हैं। भाषा को इन सांस्कृतिक प्रतीकों के आधार के रूप में समझने की जरूरत है। साभारः : पिलकर/थॉमस हॉक

समाज विज्ञानों में होमो कल्चरस की अवधारणा गायब है। अर्थशास्त्रियों और एक भौतिकवादी दृष्टि रखने वाले लोगों ने मनुष्य का वर्णन *होमो ओइकॉनॉमिकस* के तौर पर किया है, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उसे *होमो पॉलिटिक्स* की संज्ञा दी और समाजशास्त्री मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी और *होमो सोशियोलॉजिकस* के रूप में देखते हैं। वर्तमान में संख्याओं के बढ़ते उपयोग के कारण कुछ लोग होमो नुमेरिक्स की चर्चा भी करते हैं। संस्कृति के अध्ययन में गहरी रूचि होने के बावजूद समकालीन मानवशास्त्रियों ने भी 'संस्कृति' शब्द का प्रयोग करते हुए मनुष्य को *होमो कल्चरस* के रूप में वर्णित नहीं किया। समाज विज्ञानों में प्रत्यक्षवादी ज्ञानमीमांसा अधिक प्रबल रही है। यह दावा करती हैं कि संवेदी अनुभव ज्ञान का आधार हैं। अग्रणी मानवशास्त्री उस ज्ञान मीमांसा के प्रभाव के साक्षी हैं। लेस्ली व्हाईट ने 1973 में अपनी पुस्तक *'दि कांसेप्ट ऑफ कल्चर'* में उल्लेख किया कि राल्फ लिटन, रैडक्लिफ–ब्राउन और अन्य लोगों ने संस्कृति को अमूर्त या कुछ वह जो उपस्थित नहीं है या कोई ठोस वास्तविकता नहीं प्रदर्शित करता है, माना है । प्रत्यक्षवादी समाज वैज्ञानिक एक गैर–संवेदी और अस्पष्ट प्रघटना के रूप शायद ही संस्कृति में रूचि दिखायेंगे।

> प्रत्यक्षवाद का आग्रही प्रभाव

संस्कृति के बारे में उपरोक्त पूर्वाग्रह पश्चिम समाजशास्त्र के 'संस्थापक जनकों' के मध्य भी पाए जाते हैं। 1960 के पूर्व के संस्कृति के सिद्धांतकारों जैसे वेबर, दुर्खिम, मार्क्स, पारसन्स, मिल और अन्य अपनी प्रकाशित कृतियों में संस्कृति के बारे में 'कमजोर कार्यक्रम' रखने के लिए विख्यात हैं। यानि कि वे संस्कृति को बहुत कम महत्त्व देते हैं। इसके अतिरिक्त बर्मिंघम स्कूल, बोर्दियू और फूको ने भी कुछ बेहतर नहीं किया हैः उन्होंने भी संस्कृति के अध्ययन के लिए एक 'कमजोर कार्यक्रम' को अपनाया। 1990 के के दशक के अंत में ''सांस्कृतिक मोड़'' के जन्म के बाद भले ही सांस्कृतिक

> >

समाजशास्त्र का 'मजबूत कार्यक्रम' (जो संस्कृति को बहुत महत्त्व देता है) आगे बढ़ रहा हो लेकिन 'कमजोर कार्यक्रम' आज भी संस्कृति के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर हावी है।

> होमो कल्चरस की खोज

मेरे शोध ने संयोग से मुझे संस्कृति के अध्ययन के साथ लम्बे समय तक जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। 1990 के दशक में मेरी बौद्धिक जिज्ञासा ने मुझे एक सैद्धांतिक ढांचे पर काम करने के लिए प्रेरित किया जो लोगों के व्यवहार और मानव समाज की गतिशीलता को जानने और समझाने में मदद करेगा। 2014 में प्रकाशित अपनी पुस्तक *'दि आर्ट ऑफ सोशल थ्योरी'* में समाजशास्त्री रिचर्ड स्वेडबर्ग तर्क देते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत अच्छी स्थिति में नहीं है। मुझे लगा कि मुझे सैद्धांतिक एडवेंचर में जोखिम उठानी चाहिए। मैंने इस पद्धतिगत प्रश्न को उठाकर प्रारम्भ किया: मानव व्यवहार और समाज की गतिशीलता के पीछे निहित शक्तियों ताकतों की पहेली की खोज का आरम्भिक बिंदु कौन–सा होना चाहिए ? मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे उन *विशिष्ट तत्वों* की पहचान करनी होगी जो मानव प्रजाति को अन्य प्रजातियों से अलग करते हैं। मुझे लगा कि उन लक्षणों की पहचान करने की कोशिश में मुझे प्रारम्भ से शोध कार्य करना चाहिए। संभावित विशिष्ट मानवीय लक्षणों की खोज में मैं मैं जो जानना चाहता था उसकी खोज करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी: *सांस्कृतिक* प्रतीक (सीएस) अर्थात भाषा, विचार, ज्ञान, धर्म, कानून, मिथक, सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड। इस तरह से सांस्कृतिक प्रतीकों का अध्ययन मानवीय व्यवहार और सामाजिक घटनाओं की समझ और व्याख्या के लिए मौलिक प्रतीत होता है। मेरे सैद्धान्तिकरण ने मुझे भाषा को सांस्कृतिक प्रतीक की उत्पति के पीछे की ताकत के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया है: *भाषा सीएस की ''माँ'' है।* यानि कि, मनुष्य प्राचीन दार्शनिकों और सामाजिक विचारकों द्वारा वर्णित केवल बोलने वाला जानवर ही नहीं है बल्कि वह सीएस का महान उपयोगकर्ता भी है। इस तरह, *कोगितो एर्गो सम* का मेरा संस्करण कहेगा: मैं भाषा का उपयोगकर्ता हूँ, इसलिए मैं मानव हूँ।

इन सैद्धांतिक मान्यताओं ने *होमो कल्चर्स* की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने वाले क्षेत्रीय अनुभवों को अग्रेषित किया है। मुझे चार विशिष्ट मानवीय विशेषताएं मिली जो बता सकती है कि मनुष्य *होमो कल्चरस* व्यक्ति क्यों है।

जैसा कि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है, समकालीन समाज विज्ञानों में मनुष्य की पहचान में सीएस के केन्द्रीय भूमिका को नया माना जा सकता है। मानव पहचान *(होमो कल्चरस)* के मूल में सीएस की मेरी अवधारणा इस प्रकार निर्मित हुई:

1) अधिकांश अन्य जीवित प्राणियों की तुलना में मानव शरीर की वृद्धि और परिपक्वता प्रक्रिया धीमी होती है। उदाहरण के लिए, औसतन मानव शिशु एक वर्ष की आयु में चलना शुरू कर देते हैं, जबकि पशु शिशु अपने जन्म के तुरंत बाद या कुछ घंटों या दिनों के भीतर चल सकते हैं।

2) अधिकांश जानवरों की तुलना में मानव का *जीवन काल लंबा* होता है।

3) इस ग्रह पर मानव जाति की एक निर्विरोध *प्रमुख भूमिका* है।

4) सीएस द्वारा मानवों को *विशेषाधिकार* प्राप्त हैं।

5) मानव पहचान दो भागों से बनी है: *शरीर* और सीएस। यह एक द्वि–आयामी पहचान है जिसे अक्सर धर्मों और दर्शन में शरीर और आत्मा से बनी दोहरी पहचान के रूप में संदर्भित किया जाता है।

> सीएस द्वारा प्रदत अंतर्दृष्टि

शरीर और सीएस दोनों मोर्चों पर मनुष्य धीरे–धीरे बढ़ता है और परिपक्वता प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य अपने समग्र विकास में *द्वि–आयामी* है। इसके विपरीत, व्यापक और परिष्कृत मानवीय अर्थों में सीएस के आभाव के कारण गैर–मानव प्रजातियों की वृद्धि और परिपक्वता अधिकांशतः एक–आयामी (केवल शरीर) हैं। मनुष्य के शरीर में वृद्धि और परिपक्वता के मामले में दो स्तरों पर प्रगती की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। अर्थात, मानव शरीर की वृद्धि और परिपक्वता की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि मनुष्य सीएस द्वारा वृद्धि और परिपक्वता के दूसरी प्रक्रिया में शामिल है। सीएस को साइंटिफिक अमेरिकन (सितम्बर 2018) के विशेष अंक के मुख पृष्ठ पर छपी पहेली का उत्तर देने में योगदान देना चाहिए: 'मनुष्य: हम इस ग्रह पर अन्य प्रजाति से अलग क्यों हैं'। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, सीएस के आधार पर मनुष्य अन्य प्रजातियों से भिन्न है। इस प्रकार से सीएस वह है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाता है। निम्नलिखित चित्र दर्शाता है कि मनुष्य एक होमो कल्च रस क्यों है।

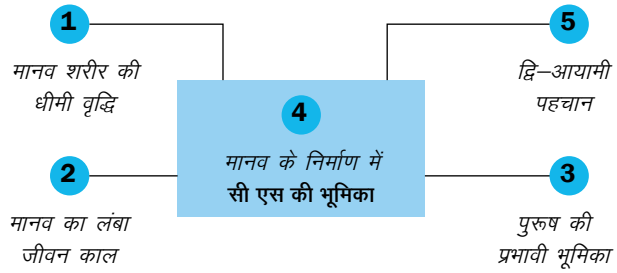

> होमो कल्चर्स और पारसीमोनी सिद्धांत

अभी यह स्पष्ट किया गया है कि सीएस चार विशिष्ट मानवीय विशेषताओं की व्याख्या कर सकता है। सीएस मानव व्यक्ति की और समूहों के अनगिनत विशिष्ट व्यवहारों के साथ समाजों और सभ्यताओं की गतिशीलता की विविधता की व्याख्या कर सकता है। इस प्रकार, सीएस परिसीमोनी सिद्धांत के साथ संगत है: घटनाओं की अधिकतम संभव संख्या की व्याख्या करने के लिए चरों की संभावित न्यूनतम संख्या का उपयोग। ■

सभी पत्राचार महमूद धौदी को <m.thawad43@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> 22 जुलाई 2011 को नार्वे का आतंकवादी हमला

पॉल हल्वोर्सन, जर्नल्स एडिटर, स्कैंडिनेवियाई यूनिवर्सिटी प्रेस, नार्वे द्वारा

उतोया द्वीप पर मुख्य भवन, जिसके बाग में 69 लोग मारे गए थे। साभारः पाल हल्वोर्सन।

''चीजें होती हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व हवा में होता है''
अलेक्जेंडर, जे.सी. और गाओ, आर. (2012)

प्रजोटोल्फ हेनसेन, अन्देर्स बेहरिंग ब्रिएविक के नाम से विख्यात, ने 22 जुलाई 2011 को नार्वे में दो आतंकवादी हमले किए। एक हमला नार्वे में कार्यकारी सरकारी क्वार्टर पर हुआ और दूसरा उटोया में हुआ, जहाँ वर्कर्स यूथ लीग का ग्रीष्मकालीन शिविर था। अब दस साल बाद भी, नार्वे का समाज अभी भी उन प्रश्नों से जूझ रहा है जो इसके बाद उठाये गए थे। हमलों में 77 की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में नार्वे पर हमला किया लेकिन दुनिया को भी मारा। अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों ने ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने हमलों को कवर भी किया। उदाहरण के लिए, तुरंत उठाये गए प्रश्नों को हमलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा माना जाता है। हालाँकि नार्वेजियन समाज तत्काल बाद में व्यावहारिक निर्णयों का मुकाबला करने के लिए सक्षम था। कई लोगों ने हमले के वृत्तांतों में हमलों के समय को रेखांकित किया, गर्मियों के मध्य का दौर जब ओस्लो काफी खाली होता है और अधिकांश लोग छुट्टियों पर होते हैं। इसने समाज को इस तरह की भयावह घटना का सामना करने के लिए कम ही तैयार किया और प्रतिक्रिया उतनी त्वरित नहीं थी जितनी अपेक्षा थी या वांछित थी। एक आतंकवादी जिसने अपने नाम और पहचान के साथ आत्मसमर्पण किया और उसने हमले से ठीक पहले व्यापक रूप से अपने 'घोषणापत्र' को

> >

वितरित किया, जवाब की तलाश इस उपलब्ध जानकरी से शुरू हो सकती थी। मनोवैज्ञानिक फोरेंसिक विशेषज्ञों की दो समितियों द्वारा ब्रेविक के मानसिक रूप से स्वस्थ होने या न होने के मनोवैज्ञानिक प्रश्न को दो विपरीत निष्कर्षों के बावजूद एक ही तरीके से संभाला गया। पहली समिति ने उन्हें पैरानायड सिजोफ्रेनिक बताया जबकि दूसरी ने उनमें एक आत्मरातिक व्यक्तित्व विकार पाया, लेकिन फिर भी उसे हमलों के दौरान मानसिक रूप से स्वस्थ माना गया। ओस्लो की जिला अदालत में यह ट्रायल ब्रेविक को मानसिक रूप से स्वस्थ और दोषी करार देने के साथ समाप्त हुई। उन्हें नार्वे में अधिकतम संभव सजा दी गईः संभावित विस्तार के साथ 21 वर्ष की जेल। अपने कारवास के दौरान उसने अपना नाम बदल लिया। 15 मार्च 2019 ब्रेंटन टेरेंट ने न्यूजीलेंड के क्राइस्टचर्च में मुस्लिमों के खिलाफ आतंकवादी हमला किया। उसने स्पष्ट रूप से ब्रेविक को अपना प्रेरणास्त्रोत माना और 22 जुलाई पुनः अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई ।

इस घटना के बाद '22 जुलाई' आने वाले सांस्कृतिक हमलों के लिए एक उपनाम बन गया है। एक अवसर के रूप में उभरा। यह न केवल एक ऐतिहासिक घटना को दर्शाता है बल्कि 9/11 की तरह बाद की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। इन घटनाओं ने इस घटना ने सामूहिक पहचान की अवधारणा के बारे में प्रश्न खड़े किये और इस संबंध में नार्वेजियन समाज की पूर्व धारणाओं को चुनौती दी। जैसा कि नार्वेजियन ट्रेड यूनियनों के परिसंघ ने प्रश्न कियाः "एक 'हमारा अपना' सामूहिक हत्यारा कैसे बना?" चर्चा के लिए सामूहिक नीवों को खोलने का यह तरीका सांस्कृतिक आघात का एक संकेतक है।

'22 जुलाई' पर न केवल नार्वेजियन बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक और लगातार बढ़ने वाला साहित्य मौजूद है। शायद *वन ऑफ अस* नामक शीर्षक के साथ असने सेरस्ताद की कथेतर शैली की सबसे अधिक चर्चित पुस्तक है। अकादमिक साहित्य में, मानवशास्त्री सिंड्रे बैंगस्टेड ने 2014 में *'अन्देर्स ब्रेविक एंड द राइज ऑफ इस्लामोफोबिया'* नाम से पुस्तक लिखी है जिसमें आतंकवाद के लिए वैचारिक प्रेरणा के प्रश्न पर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई। जबकि बैंगस्टेड इस्लामोफोबिया के खतरों को एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक कारक के रूप में अध्ययन करने पर स्पष्ट है, स्विनुंग सैंडबर्ग ब्रेविक के ''घोषणापत्र'' में प्रस्तुत आत्म–कथाओं का अध्ययन करते हैं और विश्लेष्ण के चार भिन्न–भिन्न तरीके खोजते हैं, ''या तो रणनीतिक या निर्धारक या एकीकृत या खंडित।'' उन्होंने यह भी बताया कि ब्रेविक का वर्णन करने के विभिन्न तरीके कैसे ब्रेविक की एजेंसी और वामपंथी अभिनेताओं पर संरचनात्मक दृष्टिकोणों को रेखांकित करने वाले इस्लाम विरोधी के बीच संघर्ष को दर्शाते हैं। इसी तरह के शोध की अन्य रुख का भी उल्लेख किया जा सकता है, जैसे मीडिया का अध्ययन, बहुसंस्कृतिवाद, विश्वास और नागरिक संबंध पर विमर्श और आतंकवाद विरोधी नीतियाँ। ये सभी उदाहरण आमतौर पर 22 जुलाई के प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय परिणाम यह है कि आतंकवादी हमलों के मद्देनजर नार्वे सरकार ने ओस्लो विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एक्सट्रीमिज्म (सी–आरइएक्स) की स्थापना के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया। सिंथिया मिलर इदरीस के अनुसार इसे, ''अब विश्व स्तर पर अति चरमपंथी उग्रवाद पर विद्वता और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञता के एक व्यापक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।''

यह 22 जुलाई या उससे संबंधित अध्ययन का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने की जगह नहीं है लेकिन निम्नलिखित लेख उस परिदृश्य के उदाहरण के रूप में सामने रखे गए हैं जो राफोस *नार्वेजियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी* के ''22 जुलाई'' की विषयवस्तु पर केन्द्रित अंक पर मैंरे और टोरे के काम करने के दौरान सामने आए। ये लेख विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। पहला आलेख, "ट्रस्ट इन द आफ्टरमाथ ऑफ टेररिज्म इन नॉर्वे, फ्रांस एंड स्पेन," आतंकवादी हमलों के बाद राजनेताओं और समाज में नागरिकों के विश्वास के एक हिस्से के रूप में कथाओं के महत्त्व का अध्ययन करता है। जो आतंकवादी हमले का प्रति है। तुलनात्मक मामले 2016 में नीस में और 2017 में बार्सिलोना में हुए आतंकवादी हमलों हैं ।

दूसरा लेख स्मृति कार्य के बारे में है और इसका शीर्षक "नेशनल मेमोरिअल्स एस अ रिस्पांस टू टेररिज्म" है। यह ओक्लाहोमा सिटी नेशनल मेमोरियल एवं न्यूयॉर्क के नेशनल 9/11 मेमोरियल के साथ तुलना करके ओस्ला और उटोया में राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। लेख इस बात पर चर्चा के साथ समाप्त होता है कि विरोधाभासी रूप से, कैसे राष्ट्रीय स्मारक अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं के राजनीतिक आयाम और याद करने की क्रिया पर पर्दा डालते हैं।

तीसरा लेख, "द रोल ऑफ द कोर्ट आफ्टर 22nd ऑफ जुलाई", अदालत और बचे लोगों के मध्य संबंधों, और स्मृति कार्य और पुनर्निर्माण के बीच के दस्तावेजीकरण के द्वारा कानून के समाजशास्त्र के भीतर एक शोध एजेंडा को चित्रित करता है। महत्वाकांक्षा इस बात की और समझ प्रदान करना है कि अदालत असाधारण घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। महत्वकांक्षा यह है कि असाधारण घटनाओं पर अदालत किस तरह से प्रतिक्रिया देती है की अधिक समझ विकसित करना ।

जिन पुस्तकों की समीक्षा की जाएगी, वे हैं सिंथिया मिलर–इदरीस की *'हेट इन द होमलैंड'*, ऐनी गेजेल्विक की संपादित एंथोलॉजी *Bearbeidelser* (वेज ऑफ वर्किंग थ्रू), एरिक होयर लीवेस्टैड की *Frykt og avsky i demokratiet* (लोकतंत्र में भय और घृणा), और हॉलवर्ड नोटाकर की *'Arbeiderpartiet og 22. Juli'* (लेबर पार्टी और 22 जुलाई)।

जैसा कि ये लेख और पुस्तक समीक्षाएँ स्पष्ट करती हैं, जब यह ''22 जुलाई'' का अध्ययन करने की बात आती है तो समाजशास्त्र की ताकत इसके विस्तार पर निर्भर करती है। ■

सभी पत्राचार पॉल हल्वोर्सन को
<pal.halvorsen@universitetsforlaget.no> पर प्रेषित करें।